चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

12 जनवरी–18 जनवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार भाजपा का चक्रव्यूह

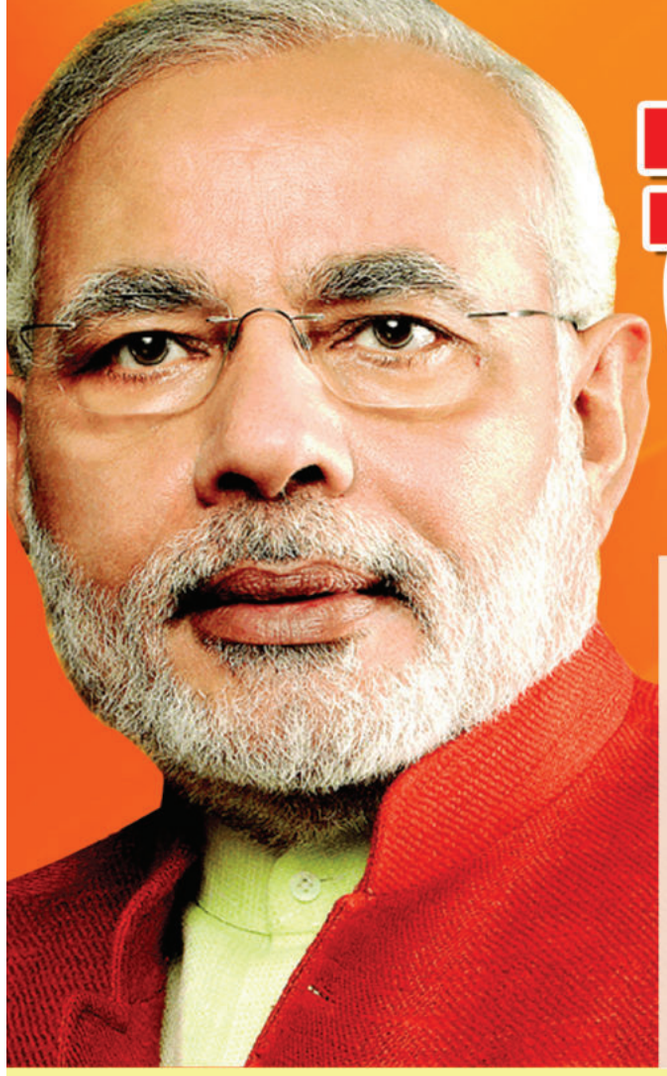

ऐसी क्या बात है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार और लालू यादव पर तो हमला करते हैं, लेकिन मांझी सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा नहीं खोलते. यह बात भी सार्वजनिक होने लगी है कि जदयू के कई मंत्रियों और नेताओं के भाजपा के साथ रिश्ते मधुर से मधुरतम होते जा रहे हैं. राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता. उसके पीछे रहस्य छिपा होता है. ऐसी क्या बात है कि जिन नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश ने गठबंधन तोड़ा था, उन्हीं मोदी के नाम को सुनते ही जदयू के कई नेता वाह-वाह कर उठते हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन प्रदेश का राजनीतिक पारा अभी से गरम हो चुका है. नीतीश कुमार और लालू यादव जनता परिवार और महा-गठबंधन के ज़रिये भाजपा को उपचुनाव की तरह शिकस्त देने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में लालू और नीतीश की पार्टियां तोड़ने का चक्रव्यूह रच रही है.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत ने बिहार में सियासत की एक नई बिसात बिछा दी है. इस खेल का खाका तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही खींचा जाने लगा था, पर इंतज़ार झारखंड चुनाव परिणाम का हो रहा था. परिणाम आते ही सूबे का राजनीतिक पारा चढ़ना तय था और यह हुआ भी. बंद कमरों में देर रात तक बैठकों का दौर शुरू है और सबसे ज़्यादा हलचल भाजपा खेमे में देखी जा रही है. मिशन 175 प्लस को हासिल करने के लिए भाजपा ने अपने घोड़े हर दिशा में खोल दिए हैं. संगठन को मजबूत करने से लेकर बूथ स्तर की तैयारियां दुरुस्त करने का काम तो पहले से ही किया जा रहा है. कार्यकर्ता सम्मेलनों और छोटी रैलियों का सिलसिला भी जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगा. अमित शाह जनवरी के तीसरे हफ्ते में बिहार आकर सारी तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं. साथ ही बिहार में अमित शाह की 37 रैलियां होने वाली हैं. यह तो आम तौर पर सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन बिहार के लिए भाजपा की स्ट्रेटजी कुछ और ही है. भारतीय जनता पार्टी की एक स्पेशल टीम एक और महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम देने में जुटी है. इस टीम की ज़िम्मेदारी नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेताओं को तोड़ने की है. हैरानी की बात यह है कि इस काम में जदयू के बागी विधायक भाजपा की मदद कर रहे हैं. गुप्त तरीके से जदयू के बड़े जनाधार वाले नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है. इस मिशन में जातीय समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है. मिशन का मकसद है कि साम–दाम–दंड–भेद के ज़रिये जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना और जनता को यह संदेश देना कि सत्ताधारी खेमे में भगदड़ मची है, क्योंकि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है.

मिशन का एक मकसद हां–ना में फंसे नेताओं को यह भी संदेश देना है कि जीत की संभावना भाजपा की तरफ़ बन रही है, इसलिए देर करने में होशियारी नहीं है. आइए और मजबूत सरकार की बुनियाद बिहार में रखी जाए. भाजपा की तरफ़ से सहयोगी दलों को भी यह इशारा है कि जो लोग किसी भी वजह से भाजपा में आने में दिक्कत महसूस करते हैं, उन्हें वे अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं. इस लाइन पर लोजपा और रालोसपा का होमवर्क भी जारी है. जानकार सूत्रों पर भरोसा करें, तो भाजपा ने जदयू के कम से कम आधा दर्जन मंत्रियों को भरोसे में लेने का काम शुरू किया है. बताया जा रहा है कि जदयू के इन नेताओं को भी लग रहा है कि झारखंड के नतीजे जिस तरह से आए हैं, उसके उलट बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा है. यह सभी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस्तीफ़े के बाद बिहार सरकार की हनक कम हुई है. और, सच्चाई भी यह है कि नीतीश कुमार की हालत वैसी ही है, जैसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की है. लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार ने अपने व्यक्तित्व की साख को बचाने के लिए राज्य को दांव पर लगा दिया. लोग नीतीश कुमार के शासन से खुश थे. सकारात्मक बदलाव भी हो रहा था. लोगों की निराशा ख़त्म करने में नीतीश कुमार पूरी तरह से सफल रहे थे. अगर वह आज मुख्यमंत्री होते, तो उनकी स्थिति काफी बेहतर होती और वह अकेले ही भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में होते. लेकिन, जीतन राम मांझी ने पूरी स्थिति ही बदल दी है. मांझी सरकार एक ढुलमुल सरकार है. अपने विवादास्पद बयानों की वजह से जीतन राम मांझी ने जाने–अनजाने अगड़ी जातियों को बेहद नाराज़ कर दिया है. इसके अलावा दलित एवं पिछड़ी जातियों के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि वे जीतन राम मांझी से कहीं बेहतर मुख्यमंत्री साबित होते. नीतीश कुमार ने मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर ग़लत घोड़े पर दांव लगा दिया. अब स्थिति यह है कि दिल्ली में अगर भाजपा जीत जाती है, तो बिहार में उसका मनोबल सातवें आसमान पर होगा. और अगर भाजपा दिल्ली में हार जाती है, तो बिहार चुनाव उसके लिए वाटर लू सिद्ध हो सकता है.

बताया जाता है कि खुद नीतीश कुमार को लगता है कि कुछ चूक हो गई है. सत्ता के दो केंद्र की बात जो पहले छिप–छिपाकर कही जा रही थी, अब खुलेआम हो रही है. यही वजह है कि जदयू के भीतर भी अलग–अलग गोलबंदी है. ये ऐसे हालात हैं, जो आगामी चुनाव में जदयू नेताओं की जीत की संभावनाएं

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नीतीश कुमार की हालत वैसी ही है, जैसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की है. लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार ने अपने व्यक्तित्व की साख को बचाने के लिए राज्य को दांव पर लगा दिया. लोग नीतीश कुमार के शासन से खुश थे. सकारात्मक बदलाव भी हो रहा था. लोगों की निराशा ख़त्म करने में नीतीश कुमार पूरी तरह से सफल रहे थे. अगर वह आज मुख्यमंत्री होते, तो उनकी स्थिति काफी बेहतर होती और वह अकेले ही भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में होते.

पप्पू पास हो रहा है

पप्पू यादव एक ऐसा नाम है, जिसे लेकर समाज में हमेशा अलग-अलग धारणाएं रही हैं. मंडल आंदोलन के दौरान वह एक तबके का हीरो था, तो एक तबके के लिए विलेन. वह दौर ख़त्म हुआ, तो पप्पू सलाखों के पीछे चले गए. इस कारण उनकी राजनीतिक गतिविधियों को विराम-सा लग गया. साल 1994 में उनके द्वारा बनाया गया ग़ैर-राजनीतिक संगठन युवा शक्ति ही इस दौर में पप्पू यादव की भावनाओं से समाज को अवगत कराता रहा. पप्पू यादव जेल से बाहर निकले और लोकसभा चुनाव में खुद तो जीते ही, उनकी पत्नी भी सुपौल से सांसद बन गईं. मोदी लहर में इस दंपत्ति की जीत ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया. जिस लहर में बड़े-बड़े दिग्गज ध्वस्त हो गए, वहां पप्पू यादव ने अपनी राजनीतिक कुशलता और चुनाव प्रबंधन का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए जीत दर्ज कराकर अपना कद काफी बढ़ा लिया. पप्पू यादव अब पूरे बिहार में घूम रहे हैं. वैसे तो भ्रष्टाचार, दलाल संस्कृति, बेलगाम अफसरशाही, छोटे राज्य और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली जैसे मुद्दे पप्पू यादव के एजेंडे में हैं, लेकिन इन दिनों वह डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को लेकर काफी आक्रामक आंदोलन चला रहे हैं. 14 जनवरी के बाद पप्पू यादव हर ज़िले में दो-दो सभाएं करने जा रहे हैं. उसके बाद पटना में एक बड़ी रैली करने का उनका कार्यक्रम है. यह विंडबना ही है कि इन सारे आंदोलनों में पप्पू यादव को अपनी पार्टी यानी राजद का समर्थन नहीं मिल रहा है. इस सवाल पर पप्पू यादव कहते हैं, राजद की जो विचारधारा है, हम उसी विच-ारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं. अब यह पार्टी को तय करना है कि वह मेरे आंदोलनों को किस रूप में देखती है. लालू यादव की परेशानी यह है कि उन्हें पता है कि युवाओं के बीच अब उनका वह क्रेज नहीं रहा. उनकी चिंता यह भी है कि वह अब चुनाव नहीं लड़ सकते, वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी नहीं बन सकते हैं. ऐसे में पार्टी को आगे ले जाने की चिंता भी है. वह अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है. उधर, पप्पू यादव बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरना चाहते हैं और यही राजद के लिए चिंता का विषय है. पप्पू यादव मांझी सरकार को भी कठघरे में खड़ा करते हैं. वह कहते हैं कि उनके कुछ मंत्री दलाल संस्कृति को प्रश्रय देते हैं. पप्पू यादव इन दिनों पीड़ित दलितों को धर्म परिवर्तन की भी सलाह दे रहे हैं. पप्पू यादव अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर अपने आपको किस तरह आगे रखना है. लालू के बाद कौन यादवों का नेता? जब यह सवाल चौक-चौराहे पर चर्चा में आता है, तो पप्पू यादव सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं. बिहार की लगभग 18 फ़ीसद यादव आबादी का नेता बनने के लिए पप्पू यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हालांकि, वह कहते हैं, मैं कभी जाति की राजनीति नहीं करता, मैं तो हमेशा जमात की बात करता हूं. लेकिन, यह सच है कि पप्पू यादव अब धीरे-धीरे यादवों के बीच स्वीकार्य हो रहे हैं. बिहार के कोसी, सीमांचल एवं अंग के बाद अब पप्पू यादव मिथिलांचल में पांव पसारने लगे हैं. आनंदमार्गी पृष्ठभूमि से आने वाले पप्पू यादव आनंदमार्गियों की तरह ही छोटे राज्य के हिमायती हैं.

पिछले दिनों पप्पू यादव ने विद्यापति की जन्मस्थली मिथिला के बिस्फी में जाकर मैथिल ब्राह्मणों के बीच उनकी ज़ुबान में भाषण देकर सबको खुश कर दिया. उन्होंने मैथिली में कहा, मिथिलाक सभ जन मैथिल छथि. सबहक भाषा मैथिली अछि. हमरा सभके मिथिला-मैथिलि के विकास के लेल हर चीज से ऊपर उठि के प्रयास

(शेष पृष्ठ 2 पर)

ग़रीबों की ज़मीन जबरन छीनने की साजिश

पेज-03

नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार का दमनकारी प्लान

पेज-04

दंगा पीड़ित सिखों के लिए केंद्र संजीदा, यूपी नहीं पसीजा

पेज-05

साई की महिमा

पेज-12

बिहार : भाजपा का चक्रव्यूह

पृष्ठ एक का शेष

कम कर रहे हैं. चुनावी साल में पार्टी के भीतर इस तरह के माहौल ने जदयू के कई बड़े नेताओं को बेचैन कर दिया है. यह मुसीबत तो खड़ी ही है, पर असली आफत खरमास के बाद आने वाली है. चर्चा है कि खरमास के बाद जदयू एवं राजद का विलय हो सकता है. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों ही यह लाइन खींचने में लगे हैं. अगर इन दोनों नेताओं का यह सपना साकार हो गया, तो फिर जदयू और राजद के कई नेताओं के दिन खराब होना तय है. मौजूदा विधानसभा में जदयू के 70 विधायक ऐसे हैं, जो सीधे मुकाबले में राजद प्रत्याशी को हराकर आए हैं. मतलब यह है कि कम कम इन 70 सीटों पर तो निश्चित तौर पर दो मजबूत प्रत्याशी टिकट के प्रबल दावेदार हैं. इसलिए यह तो तय है कि 70 नेताओं के अच्छे दिन जाने वाले हैं. इनमें कुछ जदयू के हो सकते हैं और कुछ राजद के. इन 70 में जदयू के कुछ मंत्री भी शामिल हैं.

जानकार बताते हैं कि जदयू के कुछ नेताओं को यह पच नहीं रहा है कि उन्हें एक बार फिर लालू प्रसाद के साथ काम करना होगा. ऐसे नेता जनता को लालू प्रसाद को जंगलराज का राजा बताकर विधानसभा पहुंचे थे. उन्हें लगता है कि लालू प्रसाद के साथ मंच साझा करना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है. 2015 में विधानसभा कैसे पहुंचें, यह चिंता उन्हें खाए जा रही है. ऐसे ही हालात ने भाजपा को मौक़ा दिया है कि वह सत्ताधारी पार्टी में भगदड़ मचा सके. झारखंड के चुनाव नतीजों ने भाजपा नेताओं के हौसले काफी बढ़ा दिए हैं. उन्हें लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी का जादू बिहार की जनता के सिर चढ़कर बोलेगा और यही बात वे जदयू के बड़े नेताओं को भी समझा रहे हैं. नीतीश कुमार से खफा चल रहे शकुनी चौधरी तो खुलेआम नरेंद्र मोदी की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं. कहते हैं, कुछ बात तो है नरेंद्र मोदी में. झारखंड के नतीजों के बाद शकुनी चौधरी का भरोसा नरेंद्र मोदी पर और बढ़ा है. अपनी भावी राजनीति के बारे में कुछ भी बोलने से वह परहेज करते हैं, पर जब बात नरेंद्र मोदी की होती है, तो वह वाह-वाह कह उठते हैं.

ग़ौरतलब है कि उनके पुत्र सम्राट चौधरी इस समय जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री हैं. सम्राट चौधरी नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी दोनों के क़रीबी माने जाते हैं. सम्राट चौधरी काम करने वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं. अपने कुछ फ़ैसलों से उन्होंने इस बात को साबित भी किया है. ऐसे में अगर उनके पिता शकुनी चौधरी पर मोदी मैजिक का असर बरकरार रहा, तो फिर सम्राट चौधरी के लिए धर्मसंकट की स्थिति पैदा हो सकती है. हालांकि, सम्राट चौधरी बार-बार कहते हैं कि वह सौ फ़ीसद नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के साथ हैं. सूत्रों पर भरोसा करें, तो मंत्री रमई राम, नरेंद्र सिंह, विनय बिहारी, शाहिद अली खान, वृशिण पटेल और मनोज सिंह कुशवाहा सहित जदयू के कई बड़े नेताओं पर एनडीए, खासकर भाजपा की नज़र है. भाजपा तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी डोरे डाल रही है. भाजपा के कई बड़े नेता इस संदर्भ में मीडिया में बयानबाजी भी कर चुके हैं.

भाजपा चाहती है कि जदयू में पसोपेश में फंसे बड़े नेताओं को एक विकल्प दिया जाए. अगर वे चुनाव से पहले आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा और किसी वजह से नहीं आ पाए, तो इतना संतोष रहेगा कि चलो कोशिश तो की गई थी. अगर चुनाव बाद किसी वजह से इन नेताओं की मदद की ज़रूरत पड़ी, तो कम से कम पहल करने में आसानी रहेगी. लेकिन, भाजपा को लगता है कि उसका प्रयास खाली नहीं जाएगा, क्योंकि मोदी मैजिक का असर बिहार में बढ़ने ही वाला है और कोई भी नेता, जो चुनावी जंग में जीत के लिए आश्वस्त होना चाहता है, वह इस समय तो भाजपा को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पप्पू पास हो रहा है

पृष्ठ एक का शेष

करय पड़त. पप्पू यादव की उक्त बातें मैथिलों को अच्छी लगीं और मिथिला राज्य की राजनीति को बल मिला है. पप्पू यादव कहते हैं कि कोसी और मिथिला की भूमि उर्वरा होने के बावजूद यह इलाका हमेशा शोषित-उपेक्षित रहा है. लिहाजा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए मिथिला राज्य के वह समर्थक हैं. पप्पू कहते हैं कि युवा शक्ति द्वारा सामाजिक जागृति अभियान चलाने के बाद वह बिहार में बड़ा आंदोलन करने के मूड में हैं. दरअसल, पप्पू यादव इन दिनों अपने आंदोलन को लेकर अधिक चर्चा में हैं. पहले डॉक्टरों के ख़िलाफ़ सीधी कार्रवाई करके और फिर युवा शक्ति संगठन बनाकर वह लोगों की ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं. पप्पू के इस क़दम की न सिर्फ़ समर्थक, बल्कि उनके विरोधी भी तारीफ़ करने लगे हैं. बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों की स्थिति काफी दयनीय है. पप्पू ने डॉक्टरों के ख़िलाफ़ अपने आंदोलन को सही दिशा देने के लिए युवा शक्ति को मैदान में उतारा था. पप्पू यादव अब अपने आंदोलन को व्यापक और धारदार बनाने की सोच रहे हैं. अब वह केवल डॉक्टरों के ख़िलाफ़ ही आंदोलन नहीं करेंगे, बल्कि निजी स्कूलों और कलेक्टर राज यानी प्रशासनिक संवेदनहीनता के विरुद्ध भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. पप्पू मई 2013 में अजीत सरकार हत्याकांड में निर्दोष करार दिए जाने के बाद से काफी सक्रिय हो उठे हैं. वह एक बार फिर अपनी खोई हुई ज़मीन मजबूत करने में लग गए हैं. मजे की बात यह है कि अलग-अलग राजनीतिक दलों में होने के बावजूद पति-पत्नी इस अभियान में जुटे हुए हैं.

ग़ौरतलब है कि पप्पू की पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से कांग्रेस सांसद हैं. इस बार पप्पू यादव ने जदयू प्रमुख शरद यादव को उनकी परंपरागत मधेपुरा सीट से पटखनी देकर चुनाव जीता है. बहरहाल, पप्पू की बढ़ती लोकप्रियता से राजद नेतृत्व बेचैन है. पप्पू भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छिपा नहीं पा रहे हैं. लालू यादव द्वारा पीठ थपथपाए जाने के बाद कोसी क्षेत्र में मधेपुरा के राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर और सुपौल के यदुवंश सांसद पप्पू यादव के प्रखर आलोचक बनकर उभरे हैं. उक्त दोनों राजद नेता पप्पू को खुली चुनौती देते रहे हैं. जबकि राजद के राज्य प्रमुख डॉ. रामचंद्र पूर्वे ने खुलेआम कहा है कि वह राजद के बैनर का अनाधिकृत इस्तेमाल नहीं होने देंगे. यह पार्टी के ख़िलाफ़ है. उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राजद की इकाई नहीं है, बल्कि पप्पू यादव का निजी संगठन है. ऐसी संस्थाओं और उनके क्रियाकलापों से राजद का कोई लेना-देना नहीं है. इसके बाद पप्पू यादव ने तत्काल अपने आंदोलन को विराम दे दिया और राजद प्रमुख लालू यादव को विश्वास में लेने के लिए जुट गए. हालांकि, डॉक्टरों के ख़िलाफ़ आंदोलन से उनकी ही जाति का एक वर्ग उनसे खार खाने लगा है और समय का इंतज़ार कर रहा है. पप्पू यादव राजद प्रमुख लालू प्रसाद को अपना निर्विवाद नेता मानते हैं. वह कहते हैं, हम ग़रीबों और शोषितों के हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं. युवा शक्ति भी समाज के दबे-कुचले और पिछड़े लोगों के लिए संघर्षरत है, लेकिन जो लोग पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, वे मेरे और युवा शक्ति के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह ऐसे लोगों का नोटिस लेने की बजाय लालू यादव से परामर्श करने के बाद अपने आंदोलन का विस्तार करेंगे. ■

-साथ में देवाशीष बोस

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 06 अंक 45
दिल्ली, 12 जनवरी–18 जनवरी 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060
+91–8451050786
+91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

एक और खेमका!

दिलीप चेरियन

सरकार के बदलने का हरियाणा के उन बाबुओं के लिए कोई खास मतलब नहीं है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा शासन में बच गए थे, लेकिन उन्हें अशोक खेमका और संजीव चतुर्वेदी जैसे अधिकारियों से काफी संघर्ष करना पड़ा. इन दोनों ने अपने कार्यकाल में एक स्वतंत्र लाइन लेने की कोशिश की थी. लेकिन, अब ऐसा लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार के मार्ग का ही अनुसरण कर रही है. बाबू सर्किल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं गुड़गांव के डिवीजनल कमिश्नर प्रदीप कासनी के अचानक स्थानांतरण से आश्चर्यचकित है. कासनी इस पद पर एक महीने पहले ही आए थे. सूत्रों का कहना है कि कासनी ने राजस्व अधिकारियों और कुछ शक्तिशाली भूमि माफियाओं के बीच गठजोड़ के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी. इसी वजह से कासनी को उनके पद से हटाया गया. हालांकि, आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि यह तबादला प्रशासनिक कारणों से हुआ है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई नई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है. बाबुओं को आशंका है कि कहीं वह भी एक और खेमका न बन जाएं. ■

हताश राजनयिक

अब जबकि पीएमओ मोदी सरकार के ज़्यादातर कामों की बागडोर अपने हाथ में ले चुका है, ऐसे में अकेली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ही नहीं हैं, जो थोड़ी अनिश्चित नज़र आ रही हैं. राजनयिक भी विदेशी शिष्टमंडल से बातचीत करने में खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं. विदेश सेवा के अधिकारियों ने इस मसले को विदेश सचिव सुजाता सिंह के समक्ष भी रखा है. दरअसल, पेरू में जलवायु परिवर्तन पर हुई एक वार्ता में अमेरिकी शिष्टमंडल से बातचीत का मौक़ा न दिए जाने को लेकर विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल नाराज़ बताया गया. इस तरह के कई और भी उदाहरण हैं. हालांकि, मीडिया ने सुषमा स्वराज और मोदी के बीच ऐसे मामले को उठाया है, जहां उन्हें नज़रअंदाज़ किया गया है, लेकिन विदेश सेवा के अधिकारियों के मामले में ऐसा नहीं हुआ है. अब जबकि बराक ओबामा 26 जनवरी को भारत आ रहे हैं, तो जाहिर है कि विदेश सेवा के अधिकारी इस मौक़े से जुड़ी गतिविधियों में शिरकत करना चाहेंगे. ऐसी चर्चा चल रही है कि अमेरिका में भारत के राजदूत सुब्रह्मण्यम जयशंकर (जो शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं) को प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति सलाहकार के तौर पर वापस बुलाया जा सकता है. यह क़दम पीएमओ को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देगा. ■

लीक होती सूचना

सबसे चिंताजनक होता है सत्ता के शीर्ष से सूचनाओं का लीक होना. इस लिहाज से देखें, तो मोदी सरकार, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सूचना के प्रवाह को लेकर काफी सजग है, के शीर्ष से सुरक्षा क़ानूनों के उल्लंघन करने वाली सूचनाएं लीक हो रही हैं. यह विडंबना भी है और शर्मनाक भी. हाल में भारत की परमाणु पनडुब्बी से संबंधित वर्गीकृत दस्तावेज़ मीडिया में लीक हुए. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल काफी गुस्साए और उन्होंने कई मेमो जारी कर दिए तथा ज़िम्मेदार पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. डोभाल की ओर से की गई इस कार्रवाई ने ख़तरे की घंटी बजा दी है. हाल में मंत्रिमंडल सचिवालय ने गृह सचिव अनिल गोस्वामी को निर्देश दिया है कि वह एनएसए के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और यह भी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर कर सकने वाली सूचनाएं लीक न हों. ■

dilipcherian@gmail..com

> इस संशोधन के ज़रिये कुछ ख़ास परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण से होने वाले सामाजिक प्रभाव के आकलन वाले प्रावधान को हटा दिया गया है. जबकि ज़रूरी यह है कि किसी भी काम के लिए होने वाले ज़मीन अधिग्रहण से भविष्य में पड़ने वाले सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए. यह आकलन विशेषज्ञ समिति द्वारा ग्रामसभा के सहयोग से किया जाना चाहिए और संबंधित रिपोर्ट ग्रामसभा को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन

ग़रीबों की ज़मीन जबरन छीनने की साजिश

> सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने जिस उम्मीद में उसे सत्ता सौंपी थी, अगर वह उम्मीद टूटती है, तो वही जनता उसे सत्ता से बाहर भी कर सकती है. ज़मीन का प्रत्यक्ष संबंध इस देश के 80 फ़ीसद से भी अधिक लोगों के साथ है. अध्यादेश के ज़रिये लाए गए उक्त संशोधन इस क़ानून को देश के किसानों, दलितों, आदिवासियों और ग़रीबों के ख़िलाफ़ खड़ा कर देते हैं. सरकार ने जिस जल्दबाजी में उक्त संशोधन किए हैं, उससे एक बात तो साफ़ हो गई है कि कम से कम इस देश के किसानों के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं.

शशि शेखर

ज़मीन एक ऐसी संपत्ति है, जिसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है. यह ज़मीन ही है, जो इस देश की अस्सी फ़ीसद आबादी को रोजी–रोटी–कपड़ा–मकान मुहैया कराती है. ज़मीन और किसान के बीच मां और बेटे का संबंध होता है. लेकिन, 90 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण और निजीकरण की आंधी आने के साथ ही ज़मीन और किसान के इस सनातन संबंध को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया जाने लगा. यह सब सरकार, नौकरशाहों और उद्योगपतियों की साठगांठ की वजह से हुआ. कभी सेज के नाम पर, कभी औद्योगिक विकास के नाम पर, टाउनशिप के नाम पर, यहां तक कि सड़क (एक्सप्रेस–वे) बनाने के नाम पर और अब नए जमाने में पीपीपी मॉडल के नाम पर सरकार किसानों से उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करेगी. सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, पूरी तरह से प्रॉपर्टी डीलर बन गई है. ज़मीन की दलाली होने लगी है. हज़ार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज़मीन खरीद कर पूंजीपति अरबों–खरबों की कमाई करेंगे. इसकी वजह से भट्टा पारसौल, सिंगुर एवं नंदीग्राम की कहानी हमारे सामने आ चुकी है और आगे न जाने कितने नंदीग्राम और भट्टा पारसौल की कहानियां देखने को मिलेंगी.

यूपीए–2 के शासनकाल में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे ज़मीन अधिग्रहण क़ानून को संशोधित करने की मांग शुरू हुई. खुद राहुल गांधी ने भी इस क़ानून में संशोधन की मांग की थी. संशोधन हुआ भी. मामला स्थायी समिति के पास भी गया. अंत में जो संशोधित बिल सामने आया, उसमें स्थायी समिति के ज़्यादातर सुझाव नहीं माने गए थे. यह कहानी तो यूपीए सरकार की रही. अब कहानी शुरू होती है एनडीए सरकार की. जनता को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार ने भी इस क़ानून को और कमज़ोर बनाने का काम किया है. इस बार भाजपा ने आधारभूत संरचना के विकास, औद्योगिक विकास, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचागत, ग्रामीण आवास, औद्योगिक गलियारे से जुड़ी पीपी–पीपी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण क़ानून में अध्यादेश के ज़रिये संशोधन किए हैं. अरुण जेटली ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण क़ानून 2013 की धारा 10–ए में पांच नए उद्देश्य भी जोड़े गए हैं. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा उत्पादन, विद्युतीकरण आदि के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना, सस्ते आवासों के निर्माण, औद्योगिक गलियारे बनाने एवं पीपीपी मॉडल पर सामाजिक उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के वास्ते भी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा. जेटली के मुताबिक, इस क्षेत्र में भी भूमि अधिग्रहण के लिए उच्च मुआवजा जारी रहेगा और ज़मीन पर मालिकाना हक़ सरकार के पास रहेगा. अरुण जेटली ने कहा है कि गांवों के ढांचागत विकास के लिए ही इस क़ानून में संशोधन किए गए हैं, ताकि लोगों को सस्ते घर बनाकर दिए जा सकें, क्योंकि 65 फ़ीसद लोगों के पास घर नहीं है. भूमि अधिग्रहण से ही स्मार्ट शहर बनेंगे और कच्चे घरों में रहने वालों को पक्के मकान मिल सकेंगे. उक्त संशोधन आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के नाम पर किए गए हैं. अब इन परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना और भी आसान हो जाएगा. अब ज़मीन अधिग्रहण के लिए 80 फ़ीसद किसानों की रजामंदी ज़रूरी नहीं होगी. इसके साथ ही ज़मीन अधिग्रहण से होने वाले सामाजिक प्रभाव की जांच भी ज़रूरी नहीं होगी.

बहरहाल, यह समझते हैं कि पीपीपी मॉडल और सार्वजनिक मकसद का अर्थ क्या है और अन्य देशों में इसे लेकर वहां का ज़मीन अधिग्रहण क़ानून क्या कहता है. जाहिर है, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान, दोनों विकसित देश हैं. इन दोनों देशों में इस क़ानून को लेकर क्या प्रावधान हैं, यह जानना भी दिलचस्प होगा. सार्वजनिक मक़सद यानी पब्लिक परपस की जो बात कही जाती है, उसे समझने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी पूंजीपति देश और विकसित लोकतांत्रिक देश में भूमि अधिग्रहण निजी लाभ के लिए नहीं होता है. ऐसा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान में नहीं होता है. कोई भी ऐसा देश नहीं है सिवाय भारत के, जहां भूमि अधिग्रहण सरकार की तरफ़ से किया जाता है और फिर वह भूमि निजी संस्थानों को दे दी जाती है. एक उदाहरण नॉर्दन टेरेट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया का है, जहां बहुत सारे आदिवासी रहते हैं. कोई भी निजी कंपनी वहां जाकर ज़मीन नहीं ख़रीद सकती है. ऑस्ट्रेलिया की तक़रीबन 90 फ़ीसद ज़मीन नॉर्दन टेरेट्रीज से जुड़ी हुई है. निजी संस्थाएं ज़मीन ख़रीदने के लिए सरकार को आवेदन देती हैं. वहां की सरकार मौक़े पर जाकर देखती है कि वहां हालात क्या हैं. इससे वहां कितना विस्थापन होगा और उसकी एवज़ में सेटेलमेंट की क्या व्यवस्था होगी, तभी वह ज़मीन निजी कंपनियों को दी जा सकती है. इसी तरह का एक और उदाहरण है, जापान का नरीता एयरपोर्ट. यह शायद विश्व में सबसे बड़े एयरपोर्टों में से एक है. इसे विस्तृत करने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोग अपनी ज़मीन बेचने को तैयार नहीं हुए. उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सरकार से कहा कि आप इस ज़मीन का अधिग्रहण कीजिए. सरकार ने कहा कि हम कोई अधिग्रहण नहीं कर सकते. आप उस ज़मीन के मालिकों से बात कीजिए. अगर वे अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं, तो हम इस एयरपोर्ट को विकसित नहीं कर सकते. फ्रांस और जर्मनी में जबरन भूमि अधिग्रहण तो क़तई नहीं किया सकता.

अब बात केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन की, जिसके तहत अब ज़मीन अधिग्रहण के लिए 80 फ़ीसद किसानों की रजामंदी आवश्यक नहीं होगी. सवाल है कि अगर ज़मीन अधिग्रहण के लिए 70 से 80 फ़ीसद किसानों की रजामंदी की शर्त ख़त्म कर दी गई है, तो इसका अर्थ है कि सरकार जहां की भी ज़मीन, जितनी भी ज़मीन चाहेगी, उसका अधिग्रहण कर पाने में सक्षम हो जाएगी. जाहिर है, विकास के नाम पर टाउनशिप, अस्पताल, होटल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाने का काम निजी कंपनियां करेंगी. उन्हें इस अधिग्रहीत ज़मीन से फ़ायदा होगा. मुनाफ़ा उक्त कंपनियां कमाएंगी. तब, क्यों सरकार उक्त कंपनियों के लिए प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहती है? क्यों नहीं ज़मीन की खरीद–बिक्री सीधे किसानों के ज़रिये कराने की कोशिश की जा रही है. नव–उदारवाद के दौर में व्यवसायिक घरानों के निवेश और फ़ायदों को लेकर स्थापित किए जाने वाले उद्योग बहुमूल्य ज़मीनों–खनिज संपदा पर क़ब्ज़ा करके अपनी जड़ें मज़बूत करते जा रहे हैं और पीढ़ियों से अपनी ज़मीन पर रह रहे लोगों को बेदखल करते जा रहे हैं. यह बंद होना चाहिए और यह तभी संभव है, जब सरकारें व्यवसायिक घरानों के लिए ग़रीब किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण बंद कर दें. दूसरी बात यह कि ऐसे संशोधन के बाद विकेंद्रीकृत सत्ता यानी ग्रामसभा जैसी संस्था की महत्ता क्या रह जाएगी? लोकतंत्र में जन–सहमति का क्या मतलब रहेगा? संसद की स्थायी समिति ने भी भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल (यूपीए–2 के वक्त) कहा था कि किसी भी निजी अथवा पीपीपी प्रोजेक्ट, जिसे सार्वजनिक उद्देश्य के प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित न किया गया हो, उसके लिए ज़बरदस्ती ज़मीन का अधिग्रहण न किया जाए. लेकिन, तब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थायी समिति के इस सुझाव को सिरे से नकार दिया था. तब मंत्रालय ने कहा था कि किसी भी निजी प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले 80 फ़ीसद लोगों की सहमति मिलने पर ज़मीन अधिग्रहीत कर ली जाएगी. अब मौजूदा सरकार ने पीपीपी परियोजनाओं के लिए इस 80 फ़ीसद सहमति वाले प्रावधान को भी ख़त्म कर दिया है.

इस संशोधन के ज़रिये कुछ ख़ास परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण से होने वाले सामाजिक प्रभाव के आकलन वाले प्रावधान को हटा दिया गया है. जबकि ज़रूरी यह है कि किसी भी काम के लिए होने वाले ज़मीन अधिग्रहण से भविष्य में पड़ने वाले सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए. यह आकलन विशेषज्ञ समिति द्वारा ग्रामसभा के सहयोग से किया जाना चाहिए और संबंधित रिपोर्ट ग्रामसभा को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए. वर्षों से जन संगठन भी इस बात की मांग करते रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण क़ानून में सरकारी और निजी, हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामसभा की सीधी भागीदारी और सहमति आवश्यक होनी चाहिए. इस संशोधन से पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं. यूपीए–2 में भी जब इसमें संशोधन किए गए थे, तब कई सवाल खड़े हुए थे. उनमें एक महत्वपूर्ण सवाल स्थायी समिति ने उठाया था. समिति ने कहा था कि ज़बरदस्ती कृषि भूमि का अधिग्रहण न किया जाए, जिसमें एक–फसली और बहु–फसली, दोनों तरह की ज़मीनें शामिल हैं. लेकिन, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सिर्फ़ यह कहा कि केवल बहु–फसली ज़मीन को ही अधिग्रहण के दायरे से बाहर रखा जाएगा. ऐसा हुआ भी. ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस तरह तो देश के 75 फ़ीसद किसान अधिग्रहण के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि देश में अधिकांश जगहों पर खेती वर्षा पर निर्भर है. इन खेतों में वर्ष में केवल एक फसल ही सिंचाई के साधनों की अनुपलब्धता के कारण पैदा की जा सकती है. ऐसी ज़मीनें भी अधिकांशत: दलितों, आदिवासियों एवं छोटे किसानों के अधीन हैं. अधिग्रहीत की गई ज़मीन की वापसी को लेकर भी इस बिल में कुछ सवाल उठाए गए थे. मसलन, स्थायी समिति ने कहा था कि यदि अधिग्रहीत की गई ज़मीन का पांच साल तक उपयोग नहीं होता है, तो ज़मीन अधिग्रहण की तिथि के पांच साल बाद भूमि मालिक को वापस कर देनी चाहिए. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पांच साल की बात स्वीकार भी की. लेकिन, अनुभव यह बताता है कि ऐसी बहुत–सी अधिग्रहीत ज़मीनें हैं, जिनका इस्तेमाल 25 सालों तक नहीं हुआ और फिर भी वे उनके पुराने मालिकों को नहीं लौटाई गईं. फिर इस बात की क्या गारंटी है कि पांच साल बाद ज़मीन वापस कर दी जाएगी.

बहरहाल, भाजपा सरकार ने पूर्व की ग़लतियां दोहराते हुए या कहें कि एक क़दम और आगे बढ़कर इस क़ानून को कमज़ोर बनाने का काम किया है. इन संशोधनों को देखने और इनके दूरगामी प्रभाव को समझने के बाद पूर्ववर्ती यूपीए सरकार और मौजूदा एनडीए सरकार की नीतियों में कोई फ़र्क़ करना मुश्किल है. इन संशोधनों के बाद यह साफ़ हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार भी वही काम कर रही है, खासकर ग़रीब किसानों के ख़िलाफ़, जो यूपीए–2 सरकार ने किया था. लेकिन, मौजूदा सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने जिस उम्मीद में उसे सत्ता सौंपी थी, अगर वह उम्मीद टूटती है, तो वही जनता उसे सत्ता से बाहर भी कर सकती है. ज़मीन का प्रत्यक्ष संबंध इस देश के 80 फ़ीसद से भी अधिक लोगों के साथ है. अध्यादेश के ज़रिये लाए गए उक्त संशोधन इस क़ानून को देश के किसानों, दलितों, आदिवासियों और ग़रीबों के ख़िलाफ़ खड़ा कर देते हैं. सरकार ने जिस जल्दबाजी में उक्त संशोधन किए हैं, उससे एक बात तो साफ़ हो गई है कि कम से कम इस देश के किसानों के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं.■

shashishekhar@chauthiduniya.com

फोटो– प्रभात पाण्डेय

कितना कारगर होगा विपक्ष का विरोध

सरकार के इस फ़ैसले का विरोध भी शुरू हो गया है. कांग्रेस और जनता दल (यूनाइटेड) ने भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन के लिए मोदी सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने का विरोध किया है. इन दोनों पार्टियों ने इस अध्यादेश का संसद के आगामी सत्र में विरोध करने की बात कही है. जनता दल (यूनाइटेड) ने तो इस अध्यादेश के ख़िलाफ़ देश भर में आंदोलन करने का भी फ़ैसला किया है. कांग्रेस ने कहा है कि तीन साल के गहन विचार–विमर्श के बाद यह क़ानून बनाया गया था और इसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया था. अब मोदी सरकार इसमें संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाई है. हम उसका संसद में विरोध करेंगे. जदयू के मुताबिक, नया अध्यादेश कॉरपोरेट एवं औद्योगिक घरानों और बिल्डरों के हितों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है. पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि सरकार ने इस तरह किसानों के हितों की अनदेखी की है और संसद का भी अपमान किया है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने यह अध्यादेश वापस नहीं लिया, तो जनता दल परिवार उसके ख़िलाफ़ देश भर में आंदोलन छेड़ेगा. ज़मीन अधिग्रहण क़ानून में संशोधन के लिए केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाने की सिफारिश का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोरदार विरोध करते हुए इसे अनुचित करार दिया है. बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हम प्रतीक रूप में इसकी प्रतियां जलाकर ज़मीन अधिग्रहण पर इस काले और अनुचित अध्यादेश का विरोध करेंगे.

पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के सरकार के फ़ैसले को निराशाजनक बताया. रमेश के मुताबिक़, इससे जबरन अधिग्रहण, अत्यधिक अधिग्रहण और किसानों के स्वामित्व वाली ज़मीन को दूसरे काम में लगाने का चलन शुरू हो जाएगा.■

नक्सलवाद की समस्या को दो रूपों में देखा जाता है. कुछ लोग इसे क़ानून व्यवस्था की समस्या मानते हैं. उनका मानना है कि नक्सली हिंसा फैलाकर देश के ख़िलाफ़ विद्रोह कर रहे हैं, उनकी वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वे दूरदराज के इलाकों में विकास कार्यों का विरोध करते हैं. इसके साथ ही माओवादियों पर पाकिस्तान और चीन से मदद लेकर देश को अस्थिर करने का भी आरोप लगता रहा है. इसलिए ऐसे लोगों का मानना है कि यह हिंसक आंदोलन है, इसलिए इसका जवाब सिर्फ़ सैन्य कार्रवाई से दिया जा सकता है.

नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार का दमनकारी प्लान

मोदी सरकार बहुत जल्द शहरों में चल रहे माओवादी संगठनों की शाखाओं और समर्थकों पर धावा बोलने वाली है. सरकार को लगता है कि माओवादी गतिविधियां सिर्फ़ दूरदराज के जंगलों में ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अब वे देश के शहरों के लिए भी ख़तरा बन गई हैं. माओवादी संगठन जो अब तक जंगलों से अपनी गतिविधियां चला रहे थे, वे खुफिया एजेंसियों को चमका देकर अब देश के शहरों में घुसपैठ कर चुके हैं. सरकार अब उन पर कड़ी कार्रवाई की योजना बना रही है. खुफिया एजेंसियां नक्सलवादी संगठनों के हमदर्दों और विचारकों के ख़िलाफ़ सुबूत इकट्ठा करने में जुटी हैं. सरकार सुबूत इकट्ठा कर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और विचारकों की गिरफ्तारी की योजना पर काम कर रही है.

मनीष कुमार

नक्सलवाद को देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बताया जाता है. जब यूपीए की सरकार थी, तब भी नक्सलियों और माओवादी आतंक से निपटने के लिए योजना बनाई जा रही थी. सरकार के कुछ मंत्री सैन्य कार्रवाई करने के पक्षधर थे. यहां तक कि सेना को भेजने की तैयारी हो चुकी थी. दो वजहों से कार्रवाई रुक गई. एक तो सेना ने ही मना कर दिया कि वह अपने ही देश के नागरिकों पर गोलियां नहीं चलाएगी और दूसरी वजह यह रही कि सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों ने सैन्य कार्रवाई के ख़िलाफ़ अपनी राय जाहिर कर दी. अब सवाल यह है कि नक्सलवाद से निपटने के उपायों में नज़रिये का फ़र्क़ क्यों है? वे कौन लोग हैं, जो माओवादियों के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई चाहते हैं और वे कौन लोग हैं, जो सैन्य कार्रवाई के पक्षधर नहीं हैं. उनके नज़रिये में इतना फ़र्क़ क्यों है? इसमें कोई दो मत नहीं है कि नक्सलवाद एक समस्या है. यह एक हिंसक आंदोलन है. वे भारत सरकार और राज्य सत्ता के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं. वे हिंसा के ज़रिये परिवर्तन लाना चाहते हैं. 1991 में वे क़रीब 40 ज़िलों तक सीमित थे, लेकिन आज 2015 में 270 ज़िलों में फैल चुके हैं. माओवादी संगठनों को भारत के प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं है, अदालत पर भरोसा नहीं है. वे अपनी गतिविधियां जंगलों के अंदर से ही चलाते हैं. वे सामने नहीं आते हैं. सरकार ने उनके सभी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. गृह मंत्रालय यह मानता है कि माओवादियों का फैलाव 21 राज्यों में हो चुका है. दूसरी समस्या यह है कि उक्त संगठन जहां भी सक्रिय हैं, वहां पर उन्हें स्थानीय समर्थन हासिल है.

नक्सलवाद की समस्या को दो रूपों में देखा जाता है. कुछ लोग इसे क़ानून व्यवस्था की समस्या मानते हैं. उनका मानना है कि नक्सली हिंसा फैलाकर देश के ख़िलाफ़ विद्रोह कर रहे हैं, उनकी वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वे दूरदराज के इलाकों में विकास कार्यों का विरोध करते हैं. इसके साथ ही माओवादियों पर पाकिस्तान और चीन से मदद लेकर देश को अस्थिर करने का भी आरोप लगता रहा है. इसलिए ऐसे लोगों का मानना है कि यह हिंसक आंदोलन है, इसलिए इसका जवाब सिर्फ़ सैन्य कार्रवाई से दिया जा सकता है. ऐसे लोग नक्सलियों के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई चाहते हैं.

इसके ठीक उलट, एक दूसरा नज़रिया है. कुछ लोग इसे सामाजिक और आर्थिक समस्या मानते हैं. उनका मानना है कि चूंकि सरकार दूरदराज के इलाकों में जनता को मूलभूत सेवाएं-सुविधाएं मुहैया कराने में असफल रही है, रोज़गार देने में असफल रही है, वहां स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार और नियम-क़ानून गांव एवं वनवासियों के हित में नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए सरकारी तंत्र से आमजन का भरोसा ख़त्म हो रहा है. ऐसे लोगों का मानना है कि समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण और पिछड़ापन ही नक्सलवाद जैसे आंदोलनों का मूल कारण है. आमजन की नाराज़गी इन आंदोलनों के लिए उर्वरक का काम करती है. इसलिए इसका उपाय सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बदलाव और सुधार है.

यह बात भी सच है कि जबसे भारत में नक्सलियों का उदय हुआ है, तबसे इस समस्या का सामाजिक और आर्थिक नज़रिये से उपाय नहीं किया गया. हर बार भारत सरकार और राज्य सरकारें इसका ताकत के बल पर दमन करने की कोशिशें करती रही हैं, लेकिन वे इस पर पूरी तरह काबू पाने में विफल रही हैं. यह समस्या एक राज्य से उठकर दूसरे राज्य और दूसरे से तीसरे-चौथे राज्य में पहुंच जाती है. सरकार ने सीआरपीएफ को लगाया, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली, उलटे सीआरपीएफ के सैकड़ों जवान शहीद हो गए. जबसे नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तबसे इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार नक्सलियों के ख़िलाफ़ एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी. भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद को क़ानून व्यवस्था की समस्या मानती है. इसलिए वह ताकत के बल पर निपटने की पक्षधर है.

गृह मंत्रालय ने रेड टेरर यानी लाल आतंक यानी नक्सलियों से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई है. इस रिपोर्ट में नक्सलियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है. इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के बारे में बताया गया है कि उसकी शाखाएं 21 राज्यों में अलग-अलग नामों से चल रही हैं. गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों से उक्त संगठनों की गतिविधियों पर नज़र रखने और उनके ख़िलाफ़ सुबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया है. गृह मंत्रालय ने देश भर में 128 संगठनों को चिन्हित किया है, जिनका रिश्ता माओवादी और नक्सली संगठनों से है. उक्त सभी संगठन देश के अलग-अलग शहरों में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं. खुफिया एजेंसियों ने उक्त संगठनों को अपने रडार पर ले लिया है. उन पर निगरानी रखी जा रही है. गृह मंत्रालय के नोट में बताया गया है कि उक्त संगठन देश के अलग-अलग शहरों में आंदोलनात्मक गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे वे अपनी पार्टी के लिए जन-समर्थन तैयार करते हैं और सशस्त्र विद्रोह की तैयारियों में जुटे हैं.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, उक्त संगठनों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई सरकार की प्राथमिकता है. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, उक्त संगठन शहरों में रहकर नक्सली संगठनों की मदद करते हैं, नक्सलियों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियों के बीच कड़ी का काम करते हैं, समन्वय बैठाते हैं. उनकी भूमिका मुख्य रूप से नक्सली संगठनों के ऑडियोलॉग यानी विचारक की होती है. साथ ही यही वे लोग हैं, जो शहर के पढ़े-लिखे युवाओं को बहला-फुसला कर संगठन में भर्ती करते हैं और उनका ब्रेनवाश करके उन्हें जंगलों में भेजते हैं, ताकि उनका आंदोलन जीवित रहे. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, इस तरह के संगठनों की पहचान हो गई है. अब सिर्फ़ यह साबित करना बाकी है कि वे सशस्त्र विद्रोह के न सिर्फ़ हमदर्द हैं, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के शहरी चेहरे हैं. बिना कोई ठोस सुबूत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना कठिन है, क्योंकि वे लोग शहरों में मज़दूर संगठनों, सामाजिक संगठनों और एनजीओ में घुसपैठ कर चुके हैं. खुफिया एजेंसियों को माओवादियों की शहरों में संगठन बनाने की रणनीति का तब पता चला, जब 2009 में दिल्ली में कोबाड गांधी को गिरफ्तार किया गया था. छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नक्सली प्रभावशाली हैं. इन राज्यों के शहरों में खुलेआम उनकी कार्रवाई होती है. इन राज्यों में उक्त संगठन पहले से सक्रिय हैं, लेकिन अब वे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केरल में भी सक्रिय हैं. गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली और एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन) के अंदर सक्रिय कई संगठनों की पहचान हो चुकी है, जिनके तार माओवादियों से जुड़े हुए हैं. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, शहरों में सक्रिय माओवादी संगठनों से जुड़े विचारक सुनियोजित और संगठित होकर राज्य के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करने में शामिल हैं. माओवादी गतिविधियों पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में लिखा है कि शहरों में सक्रिय विचारकों की वजह से माओवादी आंदोलन ज़िंदा है और ये कई मायनों में जंगलों में लड़ रहे माओवादी गुरिल्ला कैडर से ज़्यादा ख़तरनाक हैं.

कोबाड गांधी पर माओवादी संगठन के लिए शहरी युवाओं को भर्ती करने का आरोप है. इसी तरह नक्सलियों की मदद करने के आरोप में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के हेम मिश्रा को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली विश्वविद्यालय के जीएन साईबाबा को भी महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इनका रिश्ता रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट से बताया गया. खुफिया एजेंसियों का मानना है कि नक्सली संगठनों की रणनीति बहुत ही साफ़ है. वे पहले मज़दूर, छात्र और विभिन्न सामाजिक संगठनों में घुसते हैं, फिर उन संगठनों को आंदोलित करते हैं. सड़कों पर आंदोलन करते हैं और फिर उन्हें हिंसक आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं.

गृह मंत्रालय की रणनीति का विश्लेषण किया जाए, तो यह निष्कर्ष निकालना आसान है कि जो भी लोग नक्सलवाद को सामाजिक और आर्थिक समस्या मानते हैं, वे नक्सलवाद के हमदर्द और समर्थक की श्रेणी में आ जाएंगे. इसका मतलब यह है कि अब शहरों में कार्यरत-सक्रिय कई सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, पत्रकार और बुद्धिजीवी खुफिया एजेंसी के निशाने पर आ जाएंगे. खुफिया एजेंसियों के हाथ कोई छोटा-सा भी सुबूत आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. देश में जिस तरह से पुलिस काम करती है, उसमें यह भी ख़तरा बना रहेगा कि पुलिस झूठे सुबूतों के आधार पर भी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है. नक्सली संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ जाने-अनजाने फोन पर बातचीत करना भी मुसीबत का सबब बन सकता है. इस वजह से कई राज्यों में कई पत्रकार जेल जा चुके हैं. यह आशंका ग़लत नहीं है कि गृह मंत्रालय की इस रणनीति का दुरुपयोग होगा.

अब सवाल यह कि गृह मंत्रालय ने जिन 128 संगठनों को चिन्हित किया है, उनमें शामिल लोग कौन हैं. वे कोई अपराधी नहीं हैं, बल्कि देश के एक ज्वलंत मुद्दे पर एक तार्किक राय रखते हैं. वे अख़बारों में लिखते हैं, सेमिनारों और गोष्ठियों में अपनी राय रखते हैं. कभी-कभी वे टीवी चैनलों की बहस में भी दिखाई देते हैं. हां, उनकी राय सरकार की राय से मेल नहीं खाती है. तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार जिस तरह से सोचती है, पूरे देश को उसी राय का पालन करना होगा? यह प्रजातंत्र के किसी भी वीभत्स रूप में भी उचित नहीं है कि अगर आप सरकार के विरोध में अपनी राय रखते हैं, तो उसे गुनाह माना जाए. यह तो तानाशाही की निशानी है. क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने दायित्व का पालन किया है? क्या सरकार उन दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोज़गार के अवसर मुहैया करने में सफल हो गई है? उक्त सारी मूलभूत सेवाएं-सुविधाएं सरकार की ओर से जनता के लिए ख़ैरात नहीं है, बल्कि यह उसका अधिकार है. संविधान ने उक्त सेवाएं-सुविधाएं मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी सरकार को दी है. अगर सरकार ने अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी है, तो उसकी दलील पर भरोसा भी किया जा सकता है. और अगर नहीं, तो जनता के अधिकार के लिए बात रखना और लड़ना गुनाह कैसे हो सकता है?

नक्सलवाद को लेकर सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए. सच का सामना और ज़मीनी हक़ीक़त का विश्लेषण करके ही अच्छी नीतियों का सृजन किया जा सकता है. नक्सलवाद एक जटिल समस्या है. इसमें स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय तत्वों तक का मिश्रण है. माओवादियों की हिंसा का विस्तार गुंडागर्दी, डकैती, फिरौती से लेकर राज्य के ख़िलाफ़ हिंसक क्रांति तक है. उनके संगठन में शामिल लोगों में भोले-भाले एवं अनपढ़ वनवासियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारी तक हैं. उनकी गतिविधियां गांवों में न्यायालय चलाने से लेकर आतंकी हमले अंजाम देने तक फैली हुई हैं. इन सबके अलावा सरकार को आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि जबसे देश में नव-उदारवादी आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई है, तबसे नक्सलवाद का विस्तार तेज हो गया? क्या देश की आर्थिक नीतियों की वजह से गांवों और वनों में रहने वाले लोग मुख्य धारा से अलग-थलग हो गए हैं? अगर विकास की रोशनी उन इलाकों में नहीं पहुंच रही है और उसका फ़ायदा नक्सली संगठन उठाने में सफल हो रहे हैं, तो इसमें कुसूर किसका है? नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार को सबसे पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की आम जनता का विश्वास जीतना होगा, उन इलाकों का विकास करना होगा और वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होगा. जनता के समर्थन के बिना नक्सलवाद खुद-ब-खुद दम तोड़ देगा और शहरों में रहने वाले विचारकों की दलीलें बेमानी हो जाएंगी. सिर्फ़ कड़ी कार्रवाई की नीति से, आनन-फानन गिरफ्तारी से नक्सलवाद और भी मजबूत होगा तथा प्रजातंत्र की जड़ें कमज़ोर होंगी. ■

manishbph244@gmail.com

देश में सक्रिय कुछ माओवादी संगठन

पंजाब
कीर्ति मज़दूर यूनियन
लोक मोर्चा
लोक संग्राम मंच
पंजाब रेडिकल स्टूडेंट यूनियन

हरियाणा
जन चेतना मंच
जागरूक छात्र मोर्चा
दिशा संस्कृति मंच
नौजवान दस्ता

दिल्ली
रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट
कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स
पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया
मेहनतकश मज़दूर मोर्चा
विकल्प (कल्चरल फ्रंट)
नारी मुक्ति संघ
फोरम अगेंस्ट वॉर ऑन पीपुल

गुजरात
गुजरात वर्किंग क्लास विंग
क्रांतिकारी कामदार संगठन
नौजवान भारत सभा

महाराष्ट्र
इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपुल्स लॉयर
रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट
पुरोगामी महिला समिति

कर्नाटक
बगैर हुकुम सक्रामागोलिसी बोराता (शिमोगा)

तमिलनाडु
एंटी इंपिरियलिस्ट मूवमेंट
रेडिकल स्टूडेंट यूनियन
रेडिकल यूथ लीगल

केरल
रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट
जनकिया विमोचना मुनानी

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly
Chauthi Duniya
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

> सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि सिख विरोधी दंगों के कुल 3325 पीड़ितों में से 2733 पीड़ित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के हैं. जबकि शेष उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हैं. गृह मंत्री ने दिल्ली में 17 दंगा पीड़ितों को पांच–पांच लाख रुपए के चेक पिछले दिनों खुद वितरित किए. गृह मंत्रालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों की फिर से जांच के लिए विशेष जांच गठित करने की संभावनाओं की पड़ताल के लिए एक समिति गठित करने का भी फैसला किया है.

दंगा पीड़ित सिखों के लिए केंद्र संजीदा, यूपी नहीं पसीजा

दंगे से कम नहीं है भेद का दंश

प्रभात रंजन दीन

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 1984 के दंगा पीड़ित सिख परिवारों की सुध लेने की पहल शुरू हो गई. 30 साल हो गए. इन तीन दशकों में देश भर में कई दंगे हुए. इन दंगों पर तमाम सियासी रुदालियां हुईं. मुआवजों की तमाम रेवड़ियां बांटी गईं. लेकिन 84 के दंगा पीड़ित सिख परिवारों की खोज खबर किसी भी सत्ताधारी दल ने ली. सिख संख्या में कम हैं. उनका वोट मुसलमानों की तरह गोलबंद नहीं होता. इसीलिए उनकी राजनीतिक औकात भी कम है. राहत और मुआवजे की जद्दोजहद करते–करते पीढ़ियां बुढ़ा गईं और कई बुजुर्ग चले भी गए. लेकिन सिख परिवारों को मुआवजे के नाम पर केवल धोखा बांटा जाता रहा. उत्तर प्रदेश में तो सिखों की और भी दुर्गत की गई. बसपा और सपा सरकारों ने सिखों से खूब खेला. इधर दौड़ाया, उधर दौड़ाया. कभी यह शासनादेश तो कभी वह शासनादेश. फिर तो यूपी भी बंट गया. उत्तराखंड वाले क्षेत्र के सिखों की तो दुर्दशा कर दी गई. घर उनका उत्तराखंड में, लेकिन मुआवजे की कानूनी लड़ाई चलेगी उत्तर प्रदेश में. और उत्तर प्रदेश में कानूनी लड़ाई का हश्र यह किया गया कि मुआवजे की फाइलें गायब करा दी गईं. दंगा पीड़ित सिख परिवारों के दावे के दस्तावेज गायब करा दिए गए. यहां तक कि दंगे का शिकार हुए गुरुद्वारों की मरम्मती तक सरकारों ने नहीं होने दी. टूटे–फूटे गुरुद्वारों में ही सिख मत्था टेकते हैं और सियासतदानों को कोसते हैं. लखनऊ में अलीगंज स्थित चौधरी टोला संगत श्री गुरुग्रंथ साहब गुरुद्वारा इसका नायाब उदाहरण है. इस गुरुद्वारे को तीन नवंबर 1984 को तहस–नहस कर दिया गया था. हमलावरों ने गुरुग्रंथ साहब को भी जलाकर खाक कर दिया था. उस गुरुद्वारे की आज तक मरम्मत नहीं होने दी गई. स्थानीय असामाजिक तत्वों, भू माफियाओं और पुलिस की मिलीभगत के कारण गुरुद्वारा आज तक उसी तरह खंडहर बना पड़ा है.

उत्तर प्रदेश में तो दंगा पीड़ित सिख परिवारों के मुआवजे का मामला वीभत्स हालत में है. दंगों के शिकार सिखों को मुआवजा दिलाने के लिए दाखिल मूल याचिका के संवेदनशील पन्ने और सात-सात अन्य याचिकाएं अदालत से गायब करा दी गई हैं. मूल याचिका के महत्वपूर्ण पन्ने फाड़ कर हटा दिए गए हैं. और तो और, सिखों के मुआवजे पर जिस भी बेंच ने सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया, वह बेंच ही ऐन फैसले के वक्त बदल दी गई.

गनीमत है कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश भेजा कि 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए कम से कम पांच–पांच लाख रुपये जारी किए जाएं और उनका तत्काल भुगतान कराया जाए. सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि सिख विरोधी दंगों के कुल 3325 पीड़ितों में से 2733 पीड़ित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हैं. जबकि शेष उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हैं. गृह मंत्री ने दिल्ली में 17 दंगा पीड़ितों को पांच–पांच लाख रुपये के चेक पिछले दिनों खुद वितरित किए. गृह मंत्रालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों की फिर से जांच के लिए विशेष जांच गठित करने की संभावनाओं की पड़ताल के लिए एक समिति गठित करने का भी फैसला किया है. यह समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. भाजपा पहले से ही 84 के दंगों से जुड़े सभी मामलों की दोबारा जांच कराने की मांग करती रही है. नरेंद्र मोदी सरकार ने इंदिरा गांधी की 30वीं पुण्यतिथि से एक दिन पहले ही फैसला किया था कि 84 के दंगा पीड़ित सिख परिवारों को पांच लाख का मुआवजा दिया जाएगा. इस मुआवजे से सरकारी खजाने पर 166 करोड़ रुपये का भार आएगा.

उत्तर प्रदेश में तो दंगा पीड़ित सिख परिवारों के मुआवजे का मामला वीभत्स हालत में है. दंगों के शिकार सिखों को मुआवजा दिलाने के लिए दाखिल मूल याचिका के संवेदनशील पन्ने और सात–सात अन्य याचिकाएं अदालत से गायब करा दी गई हैं. मूल याचिका के महत्वपूर्ण पन्ने फाड़ कर हटा दिए गए हैं. और तो और, सिखों के मुआवजे पर जिस भी बेंच ने सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया, वह बेंच ही ऐन फैसले के वक्त बदल दी गई. 1984 के दंगों के शिकार ज्यादातर सिखों को अब तक मुआवजा नहीं मिला. सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर 1984 के दंगों के मुआवजे के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दंगों के शिकार सिखों की तरफ से मुआवजे के लिए छह हजार 647 दावे दाखिल किए गए. इनमें रिट संख्या 1582–एमबी–97, 2513–एमबी–97 और 3647–एमबी–97 समेत सात याचिकाएं गायब कर दी गईं. जिस बेस रिट पर पूरा मामला टिका था, उस याचिका (संख्याः 3175–एमबी–96) से 47 महत्वपूर्ण पेज गायब कर दिए गए. मूल याचिका से 30 से 44 नंबर तक के पन्ने गायब हैं. इसी तरह 52 से 55 नंबर, 163 से 175 नंबर, 191 से 205 नंबर और 250 से 251 नंबर पेज गायब कर दिए गए हैं.

दंगा पीड़ित सिखों को मुआवजा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे गुरु नानक मिशन इंटरनेशनल के अध्यक्ष सरदार अमीर सिंह विर्क कहते हैं कि मूल रिट के महत्वपूर्ण पन्ने और सात सेकेंडरी रिटें गायब किए जाने के बारे में अदालत से शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. सिख दंगों के शिकार लोगों को मुआवजा दिलाने का मामला पिछले ढाई दशक से अधिक समय से चल रहा है. सरकार ने दस कमीशन गठित किए, लेकिन एक भी कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की. यहां तक कि जस्टिस नरूला कमीशन की रिपोर्ट पर रोक लगा दी. अदालत के किसी भी फैसले में किसी कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया गया.

सुप्रीमकोर्ट ने यह स्पष्ट आदेश दे रखा है कि 84 दंगों के भुक्तभोगियों को अद्यतन (करंट) दर से मुआवजे दिए जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में शासनादेशों के मुताबिक मुआवजे दिए जाने का फैसला किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवजे का जिलेवार ब्योरा देने को कहा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने कोई ब्योरा नहीं दिया. इसके बावजूद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि शासनादेशों के मुताबिक मुआवजे दिए जाएं. इस फैसले के मुताबिक मिले मुआवजे का हाल देखिए. कानपुर के मंजीत सिंह आनंद के परिवार को चार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने उनकी मां ज्ञान कौर

1984 के दंगों के समय यूपी में रहने वाले कई सिख राज्य का विभाजन होने के बाद उत्तराखंड के हो गए. लेकिन उनके मुआवज़े का मसला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही अटका रहा. लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला. सरदार अमीर सिंह विर्क कहते हैं कि जिन सिखों को मुआवजा मिला, वह राशि भीख से भी बदतर है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने दंगा पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा वर्ष 2006 में दिए गए आश्वासन के बावजूद मुआवजा नहीं दिया.

को 27 हजार रुपये देकर निबटा दिया. लखीमपुर खीरी जिले के निघासन स्थित कुन्नू घाट निवासी बलविंदर सिंह के परिवार के पांच सदस्यों को दंगा पीड़ित तो माना गया, लेकिन उन्हें 30 रुपये से 70 रुपये का मुआवजा देकर निबटाया गया. कानपुर के गांधी ग्राम स्थित फौजी सूबेदार दलजीत सिंह का घर दंगे में तबाह कर दिया गया था. उनके पिता को गोली मारी गई. वे विकलांग हो गए. लेकिन मुआवजे में उन्हें पांच हजार रुपये देकर किनारे कर दिया गया. कानपुर में ही तिवारीपुर के रिटायर फौजी सरदार हरबंस सिंह और उनके भाई सरदार कुलवंत सिंह दंगे के दिन लापता हो गए. उनका कुछ पता नहीं चला और न उनकी लाशें बरामद हुईं. मुआवजे का मसला उठा तो कानूनगो ने रिपोर्ट में लिख दिया कि तिवारीपुर में कोई सिख रहता ही नहीं. पांच–पांच गांवों के लोगों और ग्राम प्रधानों ने शपथपत्र दाखिल कर के कहा कि तिवारीपुर में सिख रहते हैं. यह भी लिखा कि दंगे के दिन से ही सरदार अमरजीत सिंह के पिता और भाई गायब हैं, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और पीड़ित परिवार का दावा खारिज कर दिया. 1984 के दंगों के समय उत्तर प्रदेश में रहने वाले कई सिख राज्य का विभाजन होने के बाद उत्तराखंड के हो गए. लेकिन उनके मुआवज़े का मसला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही अटका रहा. लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला. सरदार अमीर सिंह विर्क कहते हैं कि जिन सिखों को मुआवजा मिला, वह राशि भीख से भी बदतर है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने दंगा पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा वर्ष 2006 में दिए गए आश्वासन के बावजूद मुआवजा नहीं दिया. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए जो राहत की घोषणा की गई थी. उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ. अकेले कानपुर में 141 सिख शहीद हुए थे. 2800 से अधिक सम्पत्तियां जला दी गई थीं या लूट ली गई थीं. उस समय तत्कालीन राज्यपाल मोती लाल वोरा के साथ दंगा पीड़ितों का समझौता हुआ था. यूपी में बसपा की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की, किसी ने सिखों के मुआवजे पर कोई ध्यान नहीं दिया. विर्क ने अफसोस जताया कि उत्तराखंड के निर्माण के दौर में हुए संघर्षों में जो लोग मारे गए उन्हें उसी समय दस–दस लाख का मुआवजा मिल गया, लेकिन उत्तराखंड के ही सिख मारे–मारे फिरते रह गए. दंगा पीड़ित सिखों को मुआवजे में खेती के लिए जमीनें ही दे दी गई होतीं, तो आज यह दुर्दशा नहीं रहती। ■

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

यूपी सरकार का स्वभाव मुआवजे में भेदभाव

मुआवजे में भेदभाव उत्तर प्रदेश सरकार के स्वभाव में शामिल है. समाजवादी पार्टी के चरित्र में यह भेदभाव का स्वभाव कुछ अधिक ही है. मुस्लिम पुलिस अधिकारी के मरने पर अखिलेश सरकार त्वरित गति से जो मुआवजा और सुविधाएं देने के लिए दौड़ पड़ती है, वही तेजी किसी अन्य धर्म के पुलिस अधिकारियों के मरने पर नहीं दिखाती. कुंडा के सीओ की हत्या पर 50 लाख का मुआवजा और दो–दो परिजनों को सरकारी नौकरी इस तेज गति की नायाब मिसाल है. जबकि कई अन्य पुलिस अधिकारी उसके बाद भी शहीद हुए हैं. मुआवजे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेदभाव बरतने पर तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है. मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में भी यूपी सरकार ने यही किया. उस दंगे में दोनों धर्मों के लोग मारे गए थे. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल मुस्लिम पीड़ितों को ही मुआवजा दिया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और संबंधित अधिसूचना रद्द करके नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि दंगा पीड़ितों के लिए तय मुआवजे में भेदभाव क्यों बरता जा रहा है. जबकि राज्य सरकार को सभी समुदायों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने यही भेदभाव 84 के दंगा पीड़ित सिख परिवारों के साथ भी रखा और उनके मुआवजे के मामले को सरकार के गलियारे में आज तक भटकाए रखा गया है.

feedback@chauthiduniya.com

> पतंजलि योगपीठ में पत्रकारों से वार्ता में बाबा रामदेव ने कहा कि न्यूयार्क टाइम्स स्क्वायर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, राष्ट्रपति बराक ओबामा और संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों के स्थायी प्रतिनिधि योग करने आएंगे. इसी दिन विश्व की सभी राजधानियों में योग शिविर लगाए जाएंगे. देश के कई योगी कार्यक्रम में भाग लेंगे. जहां तक भारत का सवाल है, बाबा का दावा है कि 21 जून को हर गांव और शहर में योग कराया जाएगा.

झारखंड में कितनी मजबूत होगी भाजपा-आजसू सरकार

ए.यू. आसिफ

28 दिसंबर 2014 को वरिष्ठ भाजपा नेता रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली दो दलों की एनडीए के तहत गठबंधन वाली सरकार ने झारखंड राज्य में शपथ ले लिया है. अब देखना यह है कि इस आदिवासी राज्य को राजनीतिक मजबूती के साथ–साथ विकास देने के नाम पर बनी ये दसवीं गठबंधन सरकार कितनी कामयाब होती है?

इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाय कि चौदह वर्ष पूर्व 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया झारखंड भारत के चालीस प्रतिशत खनिज पदार्थों के स्वामी होने के बावजूद अभी तक एक पिछड़ा हुआ राज्य है. बीते चौदह वर्षों में नौ सरकारों ने यहां राज्य किया और यहां तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा. इस राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य के पिछड़ेपन को और अधिक बढ़ाया और ये विकास के लिए तरसता रहा. इन सबके बीच यहां 6.54 मिलियन आदिवासी उजाड़े गए और यहां नक्सलवाद पनपता और बढ़ता रहा. ज्ञात रहे कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस राज्य के बनने से लेकर अब से पहले तक नक्सल हिंसा से संबंधित कुल 4430 घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें 399 पुलिस के जवान शहीद हुए. 395 आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. 916 नक्सलवादी मारे गए. जाहिर सी बात है कि इन सब घटनाओं से राज्य में खौफ का माहौल बरकरार रहता है.

यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने इस बार जनता से भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताने के अपील की थी ताकि राज्य को राजनीतिक स्थिरता एवं मजबूती दी जा सके और फिर यहां की समस्याएं हल हों और यह राज्य अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो सके. इस अपील के नतीजे में 81 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा को 37 सीटें मिली और यह सदन में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी मगर यह अपने बल पर 41 के मैजिक नंबर तक पहुंच नहीं पाई. गौरतलब है कि इसने चुनाव पूर्व 28 वर्ष पुरानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन(आजसू) और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी(एलजेपी) से एनडीए के तहत गठबंधन कर रखा था. अतएव आजसू को 5 सीटें प्राप्त होने से एलजेपी को शून्य सीट मिलने के बावजूद इस गठबंधन की कुल 42 सीटें हो गई. इस प्रकार भाजपा पूर्ण बहुमत के मैजिक नंबर से 1 सीट अधिक हासिल करके आजसू के साथ सरकार बनाने के योग्य हो गई.

28 दिसंबर को भाजपा, आजसू गठबंधन सरकार ने मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत पांच लोगों ने बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टोडियम रांची में शपथ ग्रहण भी कर लिया अन्य चार मंत्रियों में भाजपा के तीन नीलकंठ सिंह मुंडा(खुंती), चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह(राची) और लुईस मरांडी(दुमका) एवं आजसू के एक

रघुवर दास एक आदिवासी राज्य के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं. इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि खरसवां एसटी असेंबली विधानसभा क्षेत्र से चार बार नुमाइंदगी करने वाले गत 14 वर्षों में तीन बार मुख्यमंत्री रहे भाजपा के हेवी-वेट अर्जुन मुंडा के झारखंड मुक्तिमोर्चा(जेएमएम) के दशरथ गगराई के हाथों हार जाने के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जाना पहचाना आदिवासी चेहरा हाथ से निकल गया और फिर गैर आदिवासी हेविवेट रघुवर दास पर भाजपा को संतोष करना पड़ा.

चंद्रप्रकाश चौधरी शामिल हैं. इस राज्य में मुख्यमंत्री समेत अधिक से अधिक एक दर्जन मंत्रिगण हो सकते हैं. आशा है कि और सात मंत्री जल्द ही रघुवर दास मंत्रिमंडल में शामिल होंगे देखना ये है कि आजसू के कितने विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार के समय और लिया जाता है. आजसू उस क्षण की प्रतिक्षा कर रही है.

रघुवर दास एक आदिवासी राज्य के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं. इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि खरसवां एसटी असेंबली विधानसभा क्षेत्र से चार बार नुमाइंदगी करने वाले गत 14 वर्षों में तीन बार मुख्यमंत्री रहे भाजपा के हेवीवेट अर्जुन मुंडा के झारखंड मुक्तिमोर्चा(जेएमएम) के दशरथ गगराई के हाथों हार जाने के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जाना पहचाना आदिवासी चेहरा हाथ से निकल गया और फिर गैर आदिवासी हेविवेट रघुवर दास पर भाजपा को संतोष करना पड़ा. आश्चर्य की बात यह भी है कि जहां एक ओर अर्जुन मुंडा की शक्ल में यह जाना पहचाना चेहरा भाजपा को परेशान कर गया वहीं दूसरी ओर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से 15 वर्षों तक नुमाइंदगी करने वाले भाजपा के सहयोगी दल आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो भी हार कर अपनी पार्टी को दुख दे गए.

इस प्रकार सत्तारूढ़ भाजपा एवं आजसू के लिए यह आजमाइश के क्षण हैं. मोदी लहर ने तो 37 सीटें दिलाकर भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है. मगर इसे चार सीटें कम रहने के कारण पांच सीटें जीतने वाली आजसू, जिससे इसका चुनाव पूर्व गठबंधन था, पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

काबिले गौर है कि आजसू असम राज्य कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के अंदाज पर 1986 में बनी एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड राज्य के गठन के आंदोलन में आगे–आगे रही है. 1990 से इसने बिहार विधानसभा के लिए झारखंड के मुक्ति मोर्चा के निशान पर चुनाव लड़ा और फिर बाद में अपने नाम पर लड़ने लगी 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसका भाजपा से गठबंधन था मगर एक वर्ष बाद 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए संबंध तोड़ लिया और एलजेपी से गठबंधन कर लिया फिर 2014 चुनाव से पूर्व इसका एनडीए के तहत भाजपा से गठबंधन हो गया.

इस लिहाज से ऐसा महसूस होता है कि भाजपा एवं आजसू का एनडीए के तहत गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो कि बीते दिनों में टूटा भी है और इसके टूटने की वजह इन दोनों पार्टियों के बीच आपसी मतभेद थे. जाहिर है कि आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो वर्तमान सरकार से बाहर रहकर अपनी पार्टी के अधिक से अधिक स्वार्थों को पूरा करना चाहेंगे एवं भाजपा के लिए गियर या एक्सीलेटर के तौर पर भूमिका अदा करने को कहेंगे. अगर यह स्थिति रहती है तो वैचारिक तौर पर अलग इन दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा होगी कि यह गठबंधन को हर हाल में बरकरार रखें ताकि राज्य में राजनीतिक स्थिरता और मजबूती कायम रहे और राज्य विकास करे. ज्ञात रहे कि झारखंड वह क्षेत्र जहां 1908 से गैर आदिवसियों को आदवासी जमीन को बेचने से बचाने के लिए एवं आदिवसियों के दिगर स्वार्थों के लिए छोटा नागपुर टेनेन्सी ऐक्ट एवं अन्य कानून संविधान के तहत लागू है. इसके अलावा यह बात भी है भाजपा का कोई नेता इस राज्य का पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बना है. इसके वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा इस राज्य के तीन बार और उनसे पहले बाबू लाल मरांडी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं. पहली बार राज्य के गठन से कुछ माह पहले 2000 के चुनाव में भाजपा ही 32 सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी.

2014 से पूर्व राज्य में कुल 9 सरकारों में भाजपा की 4 बार सरकार रही है. इस दौरान तीन बार तो यह सबसे बड़ी पार्टी और एक बार दो बड़ी पार्टियों में शामिल थी. बहरहाल इतना जरूर है कि इस बार इसे एक पार्टी को ही विश्वास में लेकर चलना पड़ेगा. अब देखना है विकास का अपना मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने वाली भाजपा आखिर अपने वायदों पर कितना खरा उतर पाती है? ■

feedback@chauthiduniya.com

खुद को विश्व योग गुरु घोषित करने की लड़ाई

राजकुमार शर्मा

21 जून के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित होने के बाद से खुद को विश्व योग गुरु घोषित करने को लेकर उत्तराखंड में चार से अधिक योग गुरुओं के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है. नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही योग को जो प्रतिष्ठा दिलाई उसके परिणामस्वरूप ही वैश्विक स्तर पर योग को सम्मान हासिल हुआ है.

नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर ही दुनिया के ज्यादातर देशों ने 21 जून को विश्व योग दिवस बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इसी के साथ ही विभिन्न देशों में पतंजलि योगपीठ की इकाईयों ने कमर कस ली है. योग गुरु बाबा रामदेव, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष चिदानन्द मुनी जी महराज, श्रीश्री रविशंकर जी महराज एवं विदेशी शिष्याओं के लिए चर्चा में रहे पायलट बाबा की नज़र योग को पूरी दुनिया के कोने–कोने तक पहुंचाने पर है. वहीं परमार्थ निकेतन के योगी चिदानन्द मुनी जी भी अमेरिका के सेंट्रल पार्क में अपने विदेशी शिष्यों को योग कराएंगे. जिस दिन भारत को योग के क्षेत्र में मोदी जी के प्रयास से यह महान उपलब्धि मिली, उसी दिन से योग की मार्केटिंग कर अरबों–खरबों की कमाई जुटाने की लालसा की वजह से धर्मनगरी के इन मुनियों की लार टपक रही है.

पतंजलि योगपीठ में पत्रकारों से वार्ता में बाबा रामदेव ने कहा कि न्यूयार्क टाइम्स स्क्वायर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, राष्ट्रपति बराक ओबामा और संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों के स्थायी प्रतिनिधि योग करने आएंगे. इसी दिन विश्व की सभी राजधानियों में योग शिविर लगाए जाएंगे. देश के कई योगी कार्यक्रम में भाग लेंगे. जहां तक भारत का सवाल है, बाबा का दावा है कि 21 जून को हर गांव और शहर में योग कराया जाएगा.

परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष चिदानंद मुनि ने जानकारी दी कि 21 जून को अमेरिका के सेंट्रल पार्क में भी निकेतन के योगी योग कराएंगे. संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से योग दिवस घोषित करने पर भारत के योगियों का दायित्व और बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि फिलहाल अमेरिका में ही 10 हजार केंद्रों पर योग सिखाया जा रहा है. ये सभी केंद्र 21 जून के आयोजन से जुड़ेंगे.

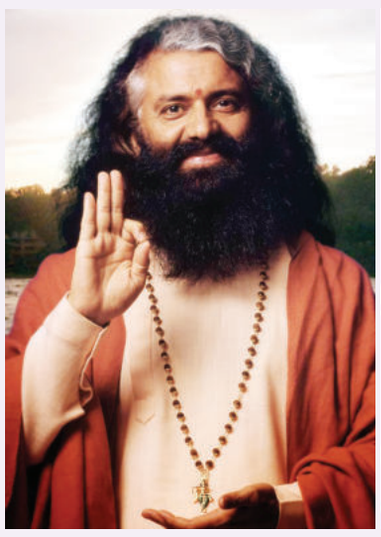

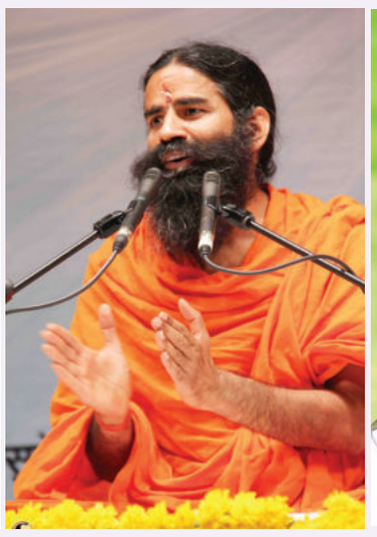

नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर ही दुनिया के ज्यादातर देशों ने 21 जून को विश्व योग दिवस बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इसी के साथ ही विभिन्न देशों में पतंजलि योगपीठ की इकाईयों ने कमर कस ली है. योग गुरु बाबा रामदेव, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष चिदानन्द मुनी जी महराज, श्रीश्री रविशंकर जी महराज एवं विदेशी शिष्याओं के लिए चर्चा में रहे पायलट बाबा की नज़र योग को पूरी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने पर है. वहीं परमार्थ निकेतन के योगी चिदानन्द मुनी जी भी अमेरिका के सेंट्रल पार्क में अपने विदेशी शिष्यों को योग कराएंगे.

योग दिवस घोषित होने पर जो मुनीगण विजय दिवस मनाते दिखे थे, वे ही अब अपने राजनीतिक आकाओं की मदद से विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे है. जिसमें अब तक योग गुरु बाबा राम देव सबसे आगे दिख रहे हैं. बाबा को स्थापित करने में विदेशी शिष्याओं के लिए चर्चित पायलट बाबा ने रामदेव की मदद करने का भरोसा दिया है. रामदवे ने इसी अपेक्षा से अपनी गंगोत्री यात्रा के समय ही वापसी के समय पायलट बाबा के उत्तरकाशी आश्रम पर रात्रि विश्राम करके गहन मंत्रणा के साथ अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई थी. योग गुरु को अपने मोदी जी से भी कुछ ज्यादा ही उम्मीद है. उनका विश्वास है कि संघ परिवार, जिसकी बाबा ने मुक्त कंठ से प्रसंशा की है, उनके साथ रहेगा.

इसी के साथ पर्यारण संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले चिदानन्द मुनी जी भी ताल ठोंक रहे हैं. मुनी जी पूरे देश में ही नहीं, बल्कि विश्व में अपने भक्तों, समर्थकों के लिए जाने जाते हैं. परमार्थ निकेतन ने सर्वाधिक विदेशियों में सनातन धर्म, गंगा और योग के प्रति भाव भरा है, जो निरर्थक नहीं सिद्ध होगा. राजनीति में वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा तक कई दिग्गज उनके यहां ही रुक कर अपनी राजनीति की थकान दूर करते रहे हैं. जो उन्हें स्थापित होने में मदद करेंगे. धर्म नगरी की पूरी मुनियों की मंडली दो गुटों में बंट गई है.

एक गुट में योग गुरु बाबा रामदेव हैं, तो दूसरी ओर चिदानन्द मुनी जी हैं. चिदानन्द को स्थापित करने में श्रीश्री रविशंकर जैसे देश के कई दिग्गज संत हैं. कल तक जो साथ में मिठाइयां बांट रहे थे वही अब आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं. अब योग का जो होना था, वह तो होगा ही. योग के बाजारीकरण से तिजोरी कितनी भर ली जाय, यह भी चर्चा का विषय बना है.भारत विश्व गुरु बनेगा या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है. धर्मनगरी के ये चर्चित संत अपने को विश्व योग गुरु के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नही छोड़ना चाहते.

योग,संस्कृत एंव संस्कृति के लिए धर्मनगरी में अपनी अलग पहचान रखने वाली जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी का मानना है कि योग का व्यापार फैलाने से योग और योगी दोनों की प्रतिष्ठा चोटिल होगी. प्रधानमंत्री मोदी के सार्थक प्रयास से विश्व में योग को सम्मान मिला है. इस सम्मान को बचाते हुए योगियों को स्वस्थ समाज की संरचना के साथ युवकों को स्वाभिमानी एंव स्वावलंबी बनाने का प्रयास सभी को मिल कर करना चाहिए. उल्लेखनीय है कि ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा से धर्मनगरी ऋषिकेश में योग की शिक्षण संस्थाएं संचालित होती हैं. इस संस्था से निकली कई योग की प्रतिभाओं ने योग का नाम रोशन किया है. संत का मत है कि मुनियों को गरिमा का ध्यान रखना चाहिए. इसी तरह का विचार विन्ध्य क्षेत्र के प्रख्यात पुरोहित पंडा समाज के अध्यक्ष भगवान दत्त पाठक ने धर्मनगरी के संतों को जोश में होश न खोने की बात कहते हुए कहा कि व्यक्ति से बड़ा देश है, प्रधानमंत्री देश को प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं, हमारे मुनियों को आत्म प्रलोभन में देश के गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. गीतास्वामी दिव्यधाम के पिठाधीश्वर स्वामी कमलेशानन्द जी मोदी के सार्थक प्रयास के लिए मन से गद–गद हैं और चाहते हैं कि योग के मामले में संतों को राजनीति और व्यापार न करके देश को विश्वगुरु का सम्मान दिलाने का संपूर्ण प्रयास करना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

आज़ाद देश के गुलाम क़ानून कब खत्म होंगे

शफीक आलम

क्या आप इंडिया ट्रेजर ट्रोव एक्ट-1878 के बारे में जानते हैं? इस क़ानून के मुताबिक, अगर किसी को सड़क पर 10 रुपये या इसके बराबर मूल्य का ज़मीन के अंदर दबा कोई खज़ाना मिलता है, तो उसे इसकी सूचना वरिष्ठ स्थानीय अधिकारी को देनी होगी, क्योंकि इस पर केवल इंग्लैंड की मलिका का अधिकार होगा. उसी तरह दि बंगलौर मैरिजेज वेलिडेटिंग एक्ट-1934 एक पादरी द्वारा कराई गई शादियों को मान्यता देने के लिए बनाया गया था. दि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट-1898 के तहत संघीय सरकार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र भेजने के विशेषाधिकार दिए गए थे, लेकिन अब भारत में कुरियर कंपनियों ने चिट्ठियों की बजाय दस्तावेज़ भेजने शुरू कर दिए. दि संथाल परगना एक्ट-1855, दि शेरिफ फीस एक्ट-1852, कॉफी एक्ट-1942 और रबर एक्ट आदि इसी तरह के दूसरे क़ानून हैं. दि न्यूजपेपर (प्राइस एंड पेज) एक्ट-1956 अख़बारों की क़ीमत, पृष्ठ और समाचार एवं विज्ञापन का अनुपात तय करने के लिए बना था, जिसका आज कोई औचित्य नहीं है. इसी तरह यंग पर्सन्स (हार्मफुल पब्लिकेशंस) एक्ट-1956 युवाओं के लिए हानिकारक समझे जाने वाले प्रकाशनों के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था. आज़ादी के बाद के आपात स्थिति से निपटने के लिए भी कुछ क़ानून बनाए गए थे, जिन्हें आज की तारीख में बरक़रार रखने का कोई औचित्य नहीं है. मिसाल के तौर पर एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एक्ट-1948, विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम-1948 और इंडियन इंडिपेंडेंस पाकिस्तान कोर्ट्स (पेंडिंग प्रोसेडिंग्स) एक्ट-1952, जो आज बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए हैं.

वास्तव में उक्त क़ानून अनावश्यक हैं, जिनका इस्तेमाल न केवल आम लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है, बल्कि ये हमारे देश में चलने वाली लंबी क़ानूनी प्रक्रिया को और जटिल बना देते हैं. ये क़ानून भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आम लोग लंबी क़ानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए किसी अधिकारी-कर्मचारी को रिश्वत देना ज़्यादा आसान समझते हैं. खुद पूर्व क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बात को मानते हैं कि ये ऐसे क़ानून हैं, जो हास्यास्पद हैं. लेकिन, अभी तक मोदी सरकार ने जो दो निरस्त एवं संशोधन विधेयक-2014 पेश किए हैं, उनमें ये क़ानून शामिल नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में पुराने, अप्रासंगिक, विकास में बाधक और जनता को परेशान करने वाले क़ानूनों से पीछा छुड़ाने की बात की थी. उन्होंने सत्ता संभालते ही अपने मंत्रियों को पहले 100 दिनो के कार्य का लक्ष्य निर्धारित करने का आदेश दिया था. इसके तहत उन्होंने तत्कालीन क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क़ानूनों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी, जो बेकार हो चुके हैं. इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बीते साल अगस्त महीने में आर रामानुजम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जिसे पिछली एनडीए सरकार द्वारा 1998 में गठित प्रशासनिक क़ानूनों की समिति द्वारा सूचीबद्ध किए गए 1,382 अप्रासंगिक क़ानूनों की समीक्षा का काम दिया गया था. इन 1,382 क़ानूनों में से अब तक केवल 415 क़ानून ही रद्द किए जा सके हैं. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने विधि आयोग को भी पत्र लिखकर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने के लिए कहा था. वर्ष 2014 में 19वें और 20वें विधि आयोग ने संयुक्त रूप से अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने 72 अप्रासंगिक हो चुके क़ानून रद्द करने की सिफारिश करते हुए 261 क़ानून समाप्त करने पर विचार किए जाने की बात कही थी. निजी तौर पर भी लोगों ने इस संबंध में अपनी तरफ़ से ऐसे क़ानूनों की सूची प्रकाशित की, जो आज अप्रासंगिक हो चुके हैं.

बहरहाल, सरकार की इसी प्राथमिकता के मद्देनज़र वर्ष 2014 में लोकसभा में दो विधेयक पेश किए गए. निरस्त एवं संशोधन विधेयक-2014 पेश करते समय तत्कालीन क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि इस देश में कुछ ऐसे क़ानून भी हैं, जो न केवल अप्रासंगिक हैं, बल्कि हास्यास्पद हैं. उस वक्त उन्होंने ऐसे कई क़ानून गिनाए. लेकिन, पेश किए गए विधेयक में कुल 36 क़ानून शामिल थे, जिनमें 32 संशोधन अधिनियम और केवल चार मूल अधिनियम थे. फिलहाल यह विधेयक संसद की स्थायी समिति के पास है. उसके बाद सरकार ने निरस्त एवं संशोधन (द्वितीय) विधेयक-2014 लोकसभा में पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. इस विधेयक में 88 ऐसे संशोधन अधिनियमों को क़ानून की किताब से हटाने की बात कही गई है, जो अप्रासंगिक हो चुके हैं और जिन्हें एक अलग अधिनियम के तौर पर रखना ज़रूरी नहीं है. कांग्रेस और सीपीआई (एम) इस विधेयक के मसौदे को भी संसद की स्थायी समिति को भेजे जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि चूंकि इस विधेयक में किसी मूल अधिनियम को हटाने की बजाय अधिनियम संशोधनों को हटाने की बात कही गई है, इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है. सरकार का स्पष्टीकरण तर्कसंगत लगता है.

अब तक अप्रासंगिक और अनावश्यक क़ानूनों को ख़त्म करने के लिए जो दो विधेयक पेश किए गए, वे बुनियादी तौर पर बेकार हो चुके संशोधन अधिनियमों को ख़त्म करने की वकालत करते हैं. चूंकि इनमें से ज़्यादातर संशोधन अधिनियम पहले से ही मूल अधिनियम में शामिल किए जा चुके हैं, इसलिए इसे अधिक से अधिक भर्ती के क़ानूनों से छुटकारा और क़ानून की भाषा में सुधार कहा जा सकता है. जिन क़ानूनों की अप्रासंगिकता की बात रविशंकर प्रसाद कर रहे थे, उनमें से ज़्यादातर को नहीं छेड़ा गया है. पूर्व क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और वर्तमान क़ानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, दोनों ने अपने-अपने विधेयक पेश करते हुए कहा कि बेकार हो चुके क़ानून समाप्त करने के लिए जल्द ही दूसरा विधेयक लाया जाएगा. सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर फिलहाल तक़रीबन 1,400 क़ानून रद्द करने का लक्ष्य रखा है. कुछ विधि विशेषज्ञ तक़रीबन 3,000 कानूनों को अनावश्यक क़ानून के दायरे में रख रहे हैं. लेकिन, अब तक की कार्यवाही से नतीजा यह निकलता है कि सरकार इन क़ानूनों से छुटकारा हासिल करना तो चाहती है, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं दिखा रही, जो अच्छी बात है. बावजूद इसके सवाल यह है कि ब्रिटिश हुकूमत के जमाने के उन क़ानूनों को, जिनमें इंग्लैंड की मलिका को संबोधित करके बात की बात गई हो, हटाने पर विचार करने की क्या ज़रूरत है?

बहरहाल, जिस गति से अप्रासंगिक क़ानून रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है, उससे लगता है कि 1,000 क़ानून रद्द करने के लिए सरकार अपने पूरे कार्यकाल के दौरान यह कार्यवाही जारी रखना चाहती है या फिर जैसा कि अपने जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड-टेपिज्म (लाल फीताशाही) को रेड कार्पेट में बदलने की बात कही थी. आशंका तो यह है कि इस रेड कार्पेट के चक्कर में कहीं मज़दूरों और किसानों के अधिकार वाले क़ानून भी इन व्यर्थ क़ानूनों के साथ समाप्त न हो जाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

मध्य प्रदेश

सरकारी योजनाओं में जमकर लूट-खसोट

चौथी दुनिया ब्यूरो

जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और सुशासन को अपनी सरकार का मूलमंत्र बताया था. वह अपने भाषणों में भाजपा शासित राज्यों के सुशासन की बात कहते हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है. सुशासन के नारे को लेकर ही दिसंबर-2013 में भाजपा तीसरी बार मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज़ हुई और शिवराज सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन सूबे के सीधी ज़िले में जिस तरह सरकारी योजनाओं को लूट और बंदरबांट का ज़रिया बना लिया गया है, उससे शिवराज सरकार का सुशासन का दावा खोखला साबित होता है.

मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में मनरेगा (महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना) सहित विभिन्न योजनाओं में जमकर धांधली और सरकारी पैसों की बंदरबांट की शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें सरपंच, पंचायत सचिव से लेकर जनपद सीईओ, ज़िला पंचायत सीईओ और कलेक्टर आदि के शामिल होने के आरोप लग रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मनरेगा में धांधली करके आदिवासी मज़दूरों का हक़ छीनने वालों के ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री ऑनलाइन, समाधान ऑनलाइन और कलेक्टर जन-सुनवाई में कई बार शिकायतें कीं. मज़दूर और स्थानीय निवासी अपने शिकायती आवेदन की पावती लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी गुहार सुनने के लिए तैयार नहीं है. शिकायतों पर कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है. अपनी आवाज़ उठाने के लिए आदिवासी मज़दूरों ने धरना-प्रदर्शन का रास्ता भी अपनाया. हर बार आरोपियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के आश्वासन के अलावा उनके हाथ अब तक कुछ नहीं लगा. इस वजह से आदिवासी मज़दूर आक्रोशित हैं. आज स्थिति यह है कि सीधी ज़िले के मज़दूर और प्रशासन आमने-सामने हैं.

पिछले साल फर्जी तरीके से जॉब कार्डधारकों के खातों से मज़दूरी की राशि आहरित कर ली गई. इसके विरुद्ध ग्राम सेमरिया के आदिवासी समुदाय के लोगों ने बीते 25-26 नवंबर को सेमरिया पुलिस चौकी के सामने धरना दिया और आरोपियों के ख़िलाफ़ वित्तीय धांधली और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की. टोको-ठोको-रोको क्रांतिकारी मोर्चा के तत्वावधान में हुए हल्ला बोल, जॉबकार्ड फर्जीवाड़ा की पोल खोल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले उमेश तिवारी ने बताया कि ज़िले की पांच जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली 402 पंचायतों में यही हाल है. उन्होंने कहा, हम आपके सामने कुछ सुबूत पेश कर सकें हैं, यही दस्तावेज़ हमने शिकायती पत्रों के साथ भी भेजे हैं, लेकिन सरकार ने आरोपियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की. तिवारी ने कहा, इससे जाहिर होता है कि बिना वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत के ऐसे कामों को अंजाम नहीं दिया जा सकता. नीचे से लेकर ऊपर तक, सारे अधिकारी इस धांधली में शामिल हैं.

इसी तरह ग्राम पंचायत क्षेत्र रामगढ़ नं-1 में हितग्राही मूलक योजना में मेड़ बंधान का कार्य कृषि विभाग की भूमि पर कराया जाना बताकर तक़रीबन 17 लाख रुपये आहरित कर लिए गए. सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें जिन लोगों द्वारा कार्य करना बताया गया है, उनमें से एक की मृत्यु कार्य प्रारंभ होने के पहले हो चुकी थी. ग्राम पंचायत क्षेत्र क्रमांक-1 के देउक्षा टोला निवासी स्वर्गीय वीरभान केवट का जॉब कार्ड क्रमांक 47 है, उनके द्वारा मेड़ बंधान कार्य में 25 जून से 30 जून, 2011 तक कार्य करना बताया गया है, जबकि उनकी मृत्यु 25 जनवरी, 2010 को हो चुकी है. एक अन्य मामले में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरिहा के चंद्रशेखर तिवारी ने अपनी पैतृक भूमि पर मेड़ बंधान अपने खर्चे पर जेसीबी मशीन के ज़रिये कराया, लेकिन पंचायत ने इस कार्य को मस्टररोल में श्रमिकों द्वारा करना बताया और अधिकारियों की मदद से मेड़ बंधान की राशि निकाल ली. ग्राम पंचायत उमरिहा, पोस्ट धनहा, ब्लॉक रामपुर नैकिन के सचिव राजाराम विश्वकर्मा और सरपंच उदयराज सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़क से लेकर सावित्री सिंह के घर तक सड़क का निर्माण करना बताया. इसके बाद माध्यमिक विद्यालय उमरिहा से भैयालाल के घर तक सड़क का निर्माण करना बताया गया. दोनों बार नाम बदल कर निर्माण राशि निकाल ली गई, जबकि वह सड़क एक ही है. दो बार निर्माण कार्य होने के बावजूद नाली का निर्माण अब तक अधूरा है. इन्हीं सरपंच और सचिव की साझेदारी में समग्र स्वच्छता अभियान के तहत 3.33 लाख रुपये आहरित कर लिए गए, लेकिन गांव में इस मद से एक भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया. दोनों मामलों के संबंध में चंद्रशेखर तिवारी ने जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर सीधी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज तक न तो किसी मामले की जांच हुई और न किसी आरोपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई.

जॉब कार्डधारक मज़दूरों के नाम से फर्जी तरीके से राशि निकाली गई, मृत लोगों एवं सरकारी कर्मचारियों के नाम से राशि निकाली गई. यही नहीं, शौचालय निर्माण के बगैर ही शौचालय निर्माण की राशि आहरित कर ली गई, जबकि जिस शख्स के नाम उक्त योजना स्वीकृत हुई, उसे ही उसकी कोई जानकारी नहीं है. मज़दूरों के फर्जी हस्ताक्षर से उनके बैंक खाते से राशि निकाली जा रही है. शिकायत दर्ज कराने और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वालों का कहना है कि सरपंच एवं सचिव जैसे छोटे पदाधिकारी बड़े अधिकारियों की मदद और शह के बिना ऐसे काम अंजाम नहीं दे सकते. ग्राम पंचायत क्षेत्र रामगढ़ क्रमांक-1 के सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध कमिश्नर रीवा द्वारा 14 सितंबर, 2012 को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई.

एक अन्य मामले में बेल्हद गांव निवासी सुदामा प्रसाद ने जनपद पंचायत रामपुर अंतर्गत आने वाली पंचायत बेल्हद की सरपंच अर्चना यादव और सचिव दया शंकर मिश्र के ख़िलाफ़ गबन की शिकायत दर्ज कराई थी. उप पुलिस अधीक्षक राजमणि त्रिपाठी ने जांच के उपरांत 11 नवंबर, 2014 को शिकायतकर्ता को पत्रांक-2509/14 के माध्यम से जानकारी दी है कि सरपंच एवं सचिव के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 38 के अवयव विद्यमान पाए गए हैं. उनके विरुद्ध अपराध पंजीकृत करने के लिए जांच प्रतिवेदन भेजा गया है. इसी तरह ग्राम

कार्यालय, मंत्री,
सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास,
मध्यप्रदेश शासन

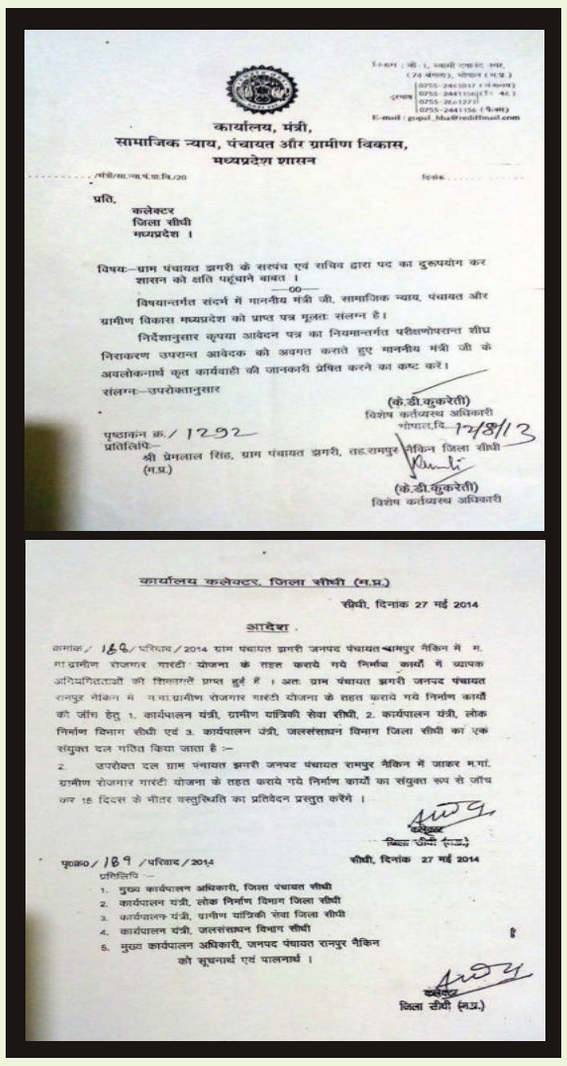

प्रति,
कलेक्टर
जिला सीधी
मध्यप्रदेश ।

विषयः—ग्राम पंचायत झगरी के सरपंच एवं सचिव द्वारा पद का दुरूपयोग कर शासन को क्षति पहुंचाने बाबत ।

विषयान्तर्गत संदर्भ में माननीय मंत्री जी, सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश को प्राप्त पत्र मूलतः संलग्न है।

निर्देशानुसार कृपया आवेदन पत्र का नियमान्तर्गत परीक्षणोपरान्त शीघ्र निराकरण उपरान्त आवेदक को अवगत कराते हुए माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ कृत कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(के.डी.कुकरेती)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
भोपाल,दि. 12/8/13

पृष्ठांकन क्र./ 1292
प्रतिलिपि:—
श्री प्रेमलाल सिंह, ग्राम पंचायत झगरी, तह.रामपुर नैकिन जिला सीधी (म.प्र.)

(के.डी.कुकरेती)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

कार्यालय कलेक्टर, जिला सीधी (म.प्र.)

सीधी, दिनांक 27 मई 2014

आदेश

क्रमांक/ 188/परिवाद/2014 ग्राम पंचायत झगरी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में म.गा.ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कराये गये निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । अतः ग्राम पंचायत झगरी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में म.गां.ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कराये गये निर्माण कार्यों की जांच हेतु 1. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीधी, 2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सीधी एवं 3. कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग जिला सीधी का एक संयुक्त दल गठित किया जाता है :—

2. उपरोक्त दल ग्राम पंचायत झगरी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में जाकर म.गां. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कराये गये निर्माण कार्यों का संयुक्त रूप से जाँच कर 15 दिवस के भीतर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

कलेक्टर
जिला सीधी (म.प्र.)

पृ.क्र./ 189 /परिवाद/2014 सीधी, दिनांक 27 मई 2014
प्रतिलिपि —
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी
2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग जिला सीधी
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला सीधी
4. कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग सीधी
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामपुर नैकिन
को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

कलेक्टर
जिला सीधी (म.प्र.)

पंचायत नैकिन में मनरेगा में हुई धांधली की जांच के लिए कलेक्टर सीधी ने एक जांच दल गठित किया था और उसे 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन आज तक उसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आया. इसी तरह कई अन्य मामलों में पुलिस जांच के दौरान फर्जीवाड़े के संबंध में मिली शिकायतें सही पाई गई हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के कथित गठजोड़ की वजह से आगे की कार्रवाई अटकी पड़ी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

संविधान ने बेहतरीन काम किया है. हमने पाकिस्तान की तरह काम नहीं किया. उसके रास्ते पर हम इसलिए नहीं गए, क्योंकि हमारी संस्था मजबूत है और इस तरह का व्यवहार इसे कमजोर बनाएगा. प्रत्यक्ष तौर पर न सही, लेकिन इसी तरह का संबंध आर्टिकल 370 के साथ भी है. देश में इस पर चर्चा कराने से कश्मीरी लोगों के मन में फिर से असुरक्षा का भाव पनपेगा.

रोज़गार न मिलने से लोगों का मोहभंग होगा

नया साल आ गया है. अब सरकार और विपक्ष, दोनों के लिए समय आ गया है कि वे अगर अपने लिए वर्ष 2015 का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखना चाहते हैं, तो कम से कम एक व्यापक एजेंडा ही तय कर लें. जहां तक सरकार का सवाल है, तो वह वास्तव में भाग्यशाली है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल (पेट्रोल) सस्ता हो गया है और ख़राब मानसून के बावजूद खाद्यान्न का भी पर्याप्त भंडार मौजूद है. यह स्थिति वित्त मंत्री को थोड़ी आज़ादी देगी कि वह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ जोखिम उठा सकें. ब्याज दरों में कटौती पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की असहमति को समाचार-पत्रों में बहुत ज़्यादा जगह दी गई. मुझे नहीं लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रास्फीति पर आरबीआई के अलग मापदंड हैं. और, मैं समझता हूं कि उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए.

वित्त मंत्री ने फरवरी 2015 में पेश किए जाने वाले बजट में अर्थव्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए उपायों की घोषणा करने का वादा किया है, लेकिन यहां समस्या यह है कि सरकार को नौकरशाही का साथ लेना पड़ेगा और आम तौर पर नए साहसिक प्रस्ताव देना नौकरशाहों के लिए संभव नहीं है. वे बहुत कम बदलाव के साथ पुराने फॉर्मूले पर चलना पसंद करते हैं. ऐसे में, अगर वित्त मंत्री साहसिक फ़ैसले लेते हैं, जैसा कि वीपी सिंह ने वर्ष 1985 में लिया था, तो जहां जोखिम होगा, वहां राजस्व का नुक़सान हो सकता है. लेकिन, अगर उसे ठीक ढंग से लागू किया जाए, तो अंतत: कराधान आसान होगा और राजस्व का भी फ़ायदा होगा. वर्ष 1985 में वीपी सिंह ने सिर्फ़ इतना किया था कि उन्होंने आयकर विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय मांगी थी कि कैसे कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कर इकट्ठा किया जा सकता है.

हमें अगले बजट का इंतज़ार करना है. बजट के अलावा प्रधानमंत्री को एक सामाजिक एजेंडा भी अपनाना होगा, ताकि भाजपा के पैतृक संगठन जो आज कर रहे हैं, उसे रोका जा सके. ऐसे संगठन केवल माहौल खराब कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के काम को मुश्किल बना रहे हैं, उनके रास्ते में कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं. इस कथित धर्मांतरण से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला. सरकार समाज का निर्माण नहीं करती, समाज खुद अपना विकास करता है. इस देश में हिंदूकरण जैसी बातें करके और अल्पसंख्यकों को डराकर इस विकास को हासिल नहीं किया जा सकता है. सभी जानते हैं कि इस देश में 80 फ़ीसद हिंदू हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म सरकार के कामकाज का हिस्सा बन जाए. हम अपनी पसंद से धर्म निरपेक्ष बने थे. धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है. हरेक आदमी का अपना धर्म है. वह कोई भी धर्म अपना सकता है. यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी को अपना धर्म त्याग देना चाहिए. केवल हिंदू ही इस देश को, इस समाज को चला सकता है. यह सब ग़लत है. दूसरों के विश्वास को, आस्था को नुक़सान नहीं पहुंचाया जा सकता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. पिछले 64 सालों में जो कुछ हमने हासिल किया है, उसे हम एक बार में अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा करके खो बैठेंगे.

संविधान ने बेहतरीन काम किया है. हमने पाकिस्तान की तरह काम नहीं किया. उसके रास्ते पर हम इसलिए नहीं गए, क्योंकि हमारी संस्था मजबूत है और इस तरह का व्यवहार इसे कमजोर बनाएगा. प्रत्यक्ष तौर पर न सही, लेकिन इसी तरह का संबंध आर्टिकल 370 के साथ भी है. देश में इस पर चर्चा कराने से कश्मीरी लोगों के मन में फिर से असुरक्षा का भाव पनपेगा. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को सही सलाह दी जानी चाहिए कि एक अच्छा नेता बनने के लिए ज़रूरी है कि लोगों के मन से असुरक्षा की भावना ख़त्म की जाए. इस तरह असुरक्षा की भावना पैदा करके शासन करना उन संगठनों की शैली है, जो दुर्भाग्य से भाजपा से संबंधित है.

जबरन बाबरी मस्जिद गिराकर क्या हासिल हो गया? उलटे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हमारा रिश्ता और कटु हो गया, जो 1992 तक ठीक था. उन्हें यह विश्वास था कि क़ानून के बिना ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुसंख्यकों ने उन्हें ग़लत साबित कर दिया. पाकिस्तान की तरह हमारा भी यह रवैया कि हम पूरे देश को हिंदू बना दें, ठीक नहीं है. यह देश के लिए ठीक नहीं है. ऐसा करते ही हमारी सीमा पर, कश्मीर में समस्याएं पैदा हो जाती हैं. पाकिस्तान एक ऐसा देश नहीं है, जिसकी नकल की जाए. अगर आप किसी की नकल करना चाहते हैं, तो उनकी करें, जो हमसे बेहतर हैं. हमारे जैसे एक समग्र समाज, जिसके पास बड़ा दिल, व्यापक और गहरी दृष्टि है, उसे ऐसा काम करना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यकों में आत्मविश्वास पैदा हो. तभी यह समाज टिक पाएगा. यही बात दलितों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के साथ लागू होती है. उन्हें संवैधानिक प्रावधान के तहत टिकट आदि मिलते हैं. लेकिन, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?

पिछले 23 सालों में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से क्या हुआ, आप जानते हैं? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, संगठित क्षेत्र के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में महज 32 लाख लोगों को रोज़गार मिला. दूसरी ओर, हमने इस क्षेत्र को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों से हज़ारों करोड़ रुपये निकाल कर दे दिए हैं. यह तो डॉ. मनमोहन सिंह या उन लोगों का भी, जो अमेरिकी अथवा यूरोपीय मॉडल की नकल करना चाहते हैं, उद्देश्य नहीं था. जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं, रोज़गार सृजन के अलावा कोई विकल्प नहीं है. दूसरी ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्रों में इस वक्त देश भर में 5.8 करोड़ उद्यमी काम कर रहे हैं. आगरा और कानपुर में जाकर देखें, वहां पारंपरिक वैश्य या ब्राह्मण वर्ग के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों के भी उद्यमी मिलेंगे. उन्होंने रोज़गार पैदा किया है. मुख्य रोज़गार अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्रों में है, जिसे चीनी टीवीटी टाउन और विलेज एंटरप्राइजेज (ग्रामीण उद्यम) कहते हैं.

चीन में शी जिनपिंग के आने के बाद देश पूरी तरह इसी टीवीटी टाउन पर निर्भर हो गया. उनकी सफलता की कहानियां इन्हीं टीवीटी टाउन से निकलती हैं. हमारे यहां भी जब तक भारत अपने भीतर नहीं देखेगा, हम छोटे और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी. दुर्भाग्य से हम पैसों के लिए उधारदाताओं पर निर्भर कर रहे हैं. बैंकों से ऐसे उद्यमियों को पैसे उधार नहीं मिलते. बैंक सिर्फ़ व्यापारिक घरानों को पैसे उधार देने में व्यस्त हैं और इसी के साथ एनपीए बढ़ता जा रहा है. छोटे उद्यमी उधार लिया गया एक-एक पैसा चुकाते हैं, रोज़गार पैदा करते हैं, लेकिन दु:ख की बात यह है कि उन्हें ही बैंक उधार नहीं देता. सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक मंत्रालय है. कलराज मिश्र उसके मंत्री हैं. मुझे लगता है कि उन्हें वित्त मंत्रालय से समर्थन दिए जाने की ज़रूरत है. यही वह असल क्षेत्र है, जहां रोज़गार पैदा होगा. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास बड़े सार्वजनिक प्लांट न हों, लेकिन रोज़गार सृजन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र ज़्यादा उपयुक्त हैं. चीन में भी बड़े उद्यम हैं, लेकिन रोज़गार वहां के टाउन और विलेज एंटरप्राइजेज (शहरी एवं ग्रामीण उद्यम) से ही आता है.

इस नए साल में प्रधानमंत्री का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अधिकतम संस्थागत ढांचा बनाना होना चाहिए, ताकि रोज़गार पैदा हो सके, स्थिरता आ सके. लोग पहले से ही महंगाई से परेशान हैं और अब अगर उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा? ग्रामीण इलाकों में लोगों का मोहभंग बहुत तेजी से होता है. इसलिए यह ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री इसे समझें, इस सच को स्वीकार करें. ■

feedback@chauthiduniya.com

जेपी जनता की नब्ज पहचानते थे

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

जब जेपी नहीं रहे, तो रविवार व संडे ने उन पर कवर टू कवर अंक निकाल कर अपनी श्रद्धांजलि दी. मेरे दोनों पत्रिकाओं में अलग-अलग लेख छपे. यहां सभी एक साथ इसलिए देने की कोशिश की है, ताकि आप भावनाओं की, सत्य की व उनके बिखरे सपनों के दर्द की झलक पा सकें, उसे महसूस कर सकें. कई सारे अंक नहीं मिल सके, जिनमें जेपी से जनता सरकार को लेकर बातचीत की थी. आख़िरी दिनों में जेपी बहुत ही निराश थे व अपने को घायल सिपाही कहते थे. मुझसे उन्होंने कई बार कहा था कि अगर तबियत ठीक होती, तो पुन: आंदोलन प्रारंभ कर देता. मैंने गंगाशरण सिंह से, जो प्रसिद्ध साहित्यकार व जेपी के अभिन्न मित्र थे, बातचीत की थी, उसे लेख के रूप में उन्हीं के नाम से दिया था. जेपी ने उनसे जब कहा होगा कि मृत्यु का कोई उपाय कीजिए, तो कैसा क्षण रहा होगा. जेपी अप्रतिम योद्धा थे. कभी उन्होंने हारना सीखा ही नहीं था. वह बहुत बड़े शिक्षक भी थे. आज भी उन्हें याद करके प्रेरणा ही मिलती है.

जयप्रकाश जी के निधन के तीसरे दिन अचानक पहली बार ध्यान आया कि जेपी से मेरा परिचय दस साल लंबा हो चुका था. जब खुद पर निगाह डालता हूं, तो इस संयोग के ऊपर आश्चर्य होता है कि कैसे मैं उनके संपर्क में आ गया, उनके स्नेह का पात्र बन गया. शायद 8 अक्टूबर, 79 तक मन में यह गरूर भी था कि मैं कुछ हूं, क्योंकि जेपी को जानता हूं, उनके कमरे में सीधा घुस जाता हूं. लेकिन आज मैं बहुत कमजोर और एकाकी महसूस कर रहा हूं. हां, नियति के कारण इस बात का संतोष अवश्य है कि मैंने न केवल जयप्रकाश जी को जाना, बल्कि उनके कारण इतिहास के एक टुकड़े का प्रत्यक्षदर्शी हो सका. संभवत: अगस्त 1969 को वाराणसी में उनसे मुलाकात हुई थी. जयप्रकाश जी ने उन दिनों पहली बार यह कहा था कि जिनका इस शिक्षा व्यवस्था में भरोसा नहीं है, उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए और मैं उनकी ओर महज इसीलिए खिंच गया था. अमरनाथ भाई ने मुझे वाराणसी में जेपी से मिलाया था. तब तक जेपी अपना प्रसिद्ध मुसहरी अभियान प्रारंभ कर चुके थे. जयप्रकाश जी ने मुझसे गिनी-चुनी बातें कीं तथा कहा, मुसहरी आइए, वहीं बातें करेंगे. मैं पहली बार चमत्कृत हुआ था. अक्सर लोग कमरे में बैठकर सुनहरे स्वप्नों को दिखाते हैं. इस आदमी ने सीधे गांव, अपने कार्यक्षेत्र में आकर परिस्थिति को बिल्कुल नज़दीक से देखने का आमंत्रण दिया था. मैंने इसे जेपी की क्रांतिकारिता को समझने का पहला क़दम माना.

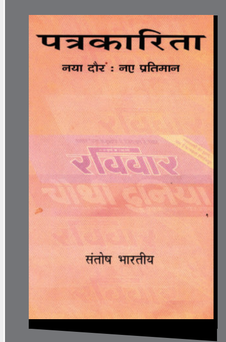

> बांग्लादेश का युद्ध आया. जेपी उसमें पूरी तरह शामिल हुए. उन्होंने किसी भी सर्वोदय नेता से नहीं कहा कि वे लोग इसमें मदद करें. पता नहीं कौन-सी ताकत थी, जो बांग्लादेश के संग्राम में संगठित रूप से मदद कर रही थी. मेरे एक मित्र ने उसे जेपी की ब्लैक फोर्स नाम दिया था. अकेला आदमी संसार में अलख जगा आया. अक्सर घटनाएं सुनाते थे कि कौन, क्या, कैसे मदद कर रहा है बांग्लादेश की. उसी समय विनोबा ने ग्रामदान आंदोलन के लिए कह दिया, या तो एक साल में काम पूरा करो या ताला लगाओ.

मुसहरी, मुजफ्फरपुर ज़िले का एक विकास खंड है, जहां ग़रीबी इतनी ज़्यादा थी कि लगता ही नहीं था कि वहां आदमी भी रहते हैं. नक्सलवादियों ने इसे देश के पांच कार्यक्षेत्रों में से एक चुना था. यहीं काम कर रहे दो सर्वोदय कार्यकर्ताओं को जब नक्सलवादियों ने मारने की धमकी दी, तो जेपी उत्तराखंड से दौड़े आए, जहां वह आराम कर रहे थे. और इस घटना के बाद ही उन्होंने गंभीरता से निर्णय लिया था कि उन्हें बाकी ज़िंदगी गांव के लिए ही काम करना है. मैं मुसहरी पहुंचा, तो जेपी ने स्वागत किया. उन्हें भरोसा नहीं था कि शहर छोड़कर गांव में काम करने भी लोग आ सकते हैं. जेपी ने पहले हफ्ते कुछ कहा नहीं, केवल गांव घूमने के लिए कहा. गांवों में बारह आने, एक रुपये पूरे परिवार की मज़दूरी थी उन दिनों. मैंने जितना गांव देखा, उतना ही रोमांचित हुआ तथा जितना जेपी को देखा, उतना

> जयप्रकाश जी के निधन के तीसरे दिन अचानक पहली बार ध्यान आया कि जेपी से मेरा परिचय दस साल लंबा हो चुका था. जब खुद पर निगाह डालता हूं, तो इस संयोग के ऊपर आश्चर्य होता है कि कैसे मैं उनके संपर्क में आ गया, उनके स्नेह का पात्र बन गया. शायद 8 अक्टूबर, 79 तक मन में यह गरूर भी था कि मैं कुछ हूं, क्योंकि जेपी को जानता हूं, उनके कमरे में सीधा घुस जाता हूं. लेकिन आज मैं बहुत कमजोर और एकाकी महसूस कर रहा हूं.

ही चमत्कृत हुआ. रोज जेपी आसपास के गांवों में जाते थे, सभा करते थे. दस आदमियों की टुकड़ी को दो घंटे तक ग्राम स्वराज्य का विचार समझाते हुए जेपी को मैंने स्वयं देखा है. उन दिनों इसका मतलब समझ पाना मेरे लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि अब तक मैंने हज़ारों की भीड़ में ही भाषण के बारे में सुना था. कोई अकेला भी आ गया, तो जेपी उसे भी पूरा वक्त देते थे. एक दिन सुबह लगभग तीन बजे नींद खुली, तो देखा कि जयप्रकाश जी अपने बिस्तर का कोना मोड़े, लालटेन की रोशनी में मच्छरदानी के अंदर डायरी में कुछ लिख रहे हैं. उन दिनों जेपी गांव से बाहर प्राथमिक विद्यालय की कच्ची इमारत में रह रहे थे. उन्हें इस तरह रहते देखना अपने आप में उत्तेजक था. शहर के युवक अक्सर उनके पास जाते थे, जिनसे वह काफी उत्साहपूर्वक बातें करते थे. जेपी के करिश्मे की आंशिक झलक मुसहरी में अब भी देखी जा सकती है.

बांग्लादेश का युद्ध आया. जेपी उसमें पूरी तरह शामिल हुए. उन्होंने किसी भी सर्वोदय नेता से नहीं कहा कि वे लोग इसमें मदद करें. पता नहीं कौन-सी ताकत थी, जो बांग्लादेश के संग्राम में संगठित रूप से मदद कर रही थी. मेरे एक मित्र ने उसे जेपी की ब्लैक फोर्स नाम दिया था. अकेला आदमी संसार में अलख जगा आया. अक्सर घटनाएं सुनाते थे कि कौन, क्या, कैसे मदद कर रहा है बांग्लादेश की. उसी समय विनोबा ने ग्रामदान आंदोलन के लिए कह दिया, या तो एक साल में काम पूरा करो या ताला लगाओ. सहरसा ज़िला राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया. जेपी इस रणनीति से असहमत थे, लेकिन जी-जान से इसे पूरा करने में लग गए. एक तरफ़ बांग्लादेश का युद्ध, दूसरी तरफ़ सहरसा, जेपी दोनों कार्यों में पूरी शक्ति से जुटे रहे.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

महानायक बनिए महा-खलनायक नहीं

आप 2015 की शुरुआत में ये शब्द पढ़ रहे हैं. हमारा यह कर्तव्य है कि हम आपको उन बातों से आगाह करें और आगाह करने के कारण भी बताएं कि क्या हो सकता है, अगर सावधानियां न रखी जाएं तो. दरअसल, हमारा भी वही कर्तव्य है, जो एक डॉक्टर का होता है. डॉक्टर अपने मरीज को उसकी खूबसूरती नहीं बताता, बल्कि असावधान रहने पर क्या-क्या रोग हो सकते हैं, इसकी जानकारी देता है. उसी तरह पत्रकारिता का बुनियादी धर्म है कि वह किसी भी स्थिति में तारीफ़ों की कसीदे पढ़ने की जगह समाज और देश के सामने क्या-क्या परेशानियां आ सकती हैं, उन्हें बताए. और, न बताने की स्थिति में वह वैसा ही अपराध भी कर बैठती है, जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को बजाय ठीक करने के, उसे ठीक करने के लिए ज़्यादा पैसे की मांग कर बैठे.

गाड़ी पटरी से कब उतर गई, इसका विश्लेषण अलग-अलग हो सकता है, लेकिन विकास के दायरे से जनता धीरे-धीरे अलग होती चली गई और विकास मुट्ठी भर लोगों के लिए होने लगा, यह तो दिखाई दे रहा है. 1991 के बाद बाज़ार ने विकास को अपने नियंत्रण में ले लिया और आज हालत यह है कि देश की 70 या 75 प्रतिशत जनता को सिर्फ़ जीने लायक सुविधाएं कैसे मिलें, इसकी योजना बनती है. उसे रोज़गार के सपने कैसे दिखाए जाएं, इसकी योजना बनती है. वह विद्रोह न करे, इसके लिए उसे कितनी सुविधाएं चाहिए, इसकी योजना बनती है और शोषण का एक लंबा मानचित्र तैयार किया जाता है. इसी मानचित्र के ऊपर पिछली सरकारें चलीं और इसी मानचित्र के ऊपर यह सरकार भी चल रही है. कहा जा रहा है कि इस सरकार के पास वक्त नहीं था कि यह आर्थिक नीतियां बदले, इसलिए 2015 के बजट सत्र का इंतज़ार करना चाहिए. 2015 के बजट सत्र में सिर्फ़ चंद महीने बाकी हैं, उसे भी हम देख लेंगे. लेकिन, जिस तरह के वक्तव्य सामने आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि बाज़ार आधारित आर्थिक नीतियां और विकास का मॉडल ही और ज़्यादा सशक्त बनाया जाएगा, बजाय इसके कि जनता आधारित विकास का मॉडल बनाया जाए. अगर ऐसा होता है, तो क्या-क्या हो सकता है, इसकी कल्पना बजट सत्र के बाद करेंगे. लेकिन, अभी एक चेतावनी हम आपको और एक संकेत सरकार को अवश्य देना चाहते हैं.

हम जब पानी को गरम होने के लिए आग पर रखते हैं, तो वह काफी समय लेता है, तब वह धीरे-धीरे गुनगुना होता है, लेकिन जब वह एक बार गुनगुना हो जाता है, तो उसे उबलने में बहुत देर नहीं लगती. मनमोहन सिंह ने बाज़ार आधारित आर्थिक नीतियों की रोशनी में जिन विकास के चिन्हों को अपनाया था, उसके तहत उन्होंने पानी गुनगुना कर दिया और सरकार सामाजिक दायित्वों से मुक्त हो गई. सड़क, अस्पताल, स्कूल, रोज़गार, पानी और शिक्षा यानी सब कुछ सरकार की ज़िम्मेदारी से मुक्त हो गया. इसका नतीजा यह हुआ कि अब कहीं से ये ख़बरें नहीं आतीं कि लोग भूख से मर रहे हैं,

ये ख़बरें भी नहीं आतीं कि कहीं ज़मीन को लेकर संघर्ष हो रहे हैं, लोग जल-जंगल-ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं. इसका सीधा मतलब है कि मीडिया को भी बाज़ार ने अपने हाथ में ले लिया है और जनता इन संघर्षों के बारे में अपने दायरे से अलग जान ही नहीं पाती. क्या ये संघर्ष ख़त्म हो गए हैं, क्या हम सुख और चैन से जी रहे हैं? ये सारे सवाल भी आज नहीं उठाए जा रहे हैं.

पर जिस एक चीज के बारे में न यह सरकार समझ रही है और न आपके पास उसकी सूचना जाने दे रही है, वह यह है कि देश के सात प्रमुख राज्यों, जहां पर असंतोष है, जहां विकास नहीं पहुंचा है और जहां लोग बिना रोटी के, बिना दवाओं के घिसटते हुए मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं, वहीं से हमारी सेना में सबसे ज़्यादा सिपाही आते हैं. इन राज्यों में ग़रीब, शोषण, बेकारी और संघर्ष की बात करना नक्सलवाद का समर्थन करना माना जा रहा है. मौजूदा सरकार इन तमाम समस्याओं को क़ानून व्यवस्था की समस्या मानती है, विकास की ग़लत नीतियों को इसका कारण नहीं मनाती. इसलिए अब गृह मंत्रालय यह फ़ैसला ले चुका है कि अगर आप शहरों में नक्सलवादियों का समर्थन करेंगे, तो आप जेल भेजे जा सकते हैं. मतलब यह कि अगर कोई ग़रीबी के कारणों का विश्लेषण करे, अगर कोई वंचितों के हितों की बात करे, अगर कोई भूमि संघर्ष की बात करे और अगर कोई सरकारी दमन के ख़िलाफ़ बात करे, तो वह नक्सलवादियों का समर्थक माना जा सकता है. क्योंकि, नक्सलवादी भी कमोबेश इन्हीं बातों को अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश के 272 से ज़्यादा ज़िले उनके प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं.

> क करने के लिए ज़्यादा पैसे की मांग कर बैठे, गाड़ी पटरी से कब उतर गई, इसका विश्लेषण अलग-अलग हो सकता है, लेकिन विकास के दायरे से जनता धीरे-धीरे अलग होती चली गई और विकास मुट्ठी भर लोगों के लिए होने लगा, यह तो दिखाई दे रहा है. 1991 के बाद बाज़ार ने विकास को अपने नियंत्रण में ले लिया और आज हालत यह है कि देश की 70 या 75 प्रतिशत जनता को सिर्फ़ जीने लायक सुविधाएं कैसे मिलें, इसकी योजना बनती है. उसे रोज़गार के सपने कैसे दिखाए जाएं, इसकी योजना बनती है. वह विद्रोह न करे, इसके लिए उसे कितनी सुविधाएं चाहिए, इसकी योजना बनती है और शोषण का एक लंबा मानचित्र तैयार किया जाता है.

मौजूदा सरकार से हम विनम्रतापूर्वक 2015 की शुरुआत में यह अपील करते हैं कि वह अपने सोचने का तरीका थोड़ा-सा बदले. विकास की धारा में उस जनसंख्या को लाना ज़रूरी है, जिसे आज़ादी के पैंसठ सालों ने धीरे-धीरे विकास के दायरे से बाहर कर दिया. पानी गुनगुना हो चुका है, पानी को उबलने में बहुत देर नहीं लगेगी. आप राज्यों में, शहरों में, गांवों में उन संवेदनशील लोगों को पकड़ कर जेल में अवश्य डाल सकते हैं, जो बदलाव की बातें करते हैं. शायद सरकारों का यह धर्म हो जाता है कि वे सत्ता में आने से पहले सबके लिए सब कुछ करने का वादा करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे बड़ी आसानी के साथ उन चीजों को परे छिटक देती हैं और सिर्फ़ बाज़ार की बात करती हैं.

श्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी इस रास्ते पर है. पर हमारा धर्म उन्हें यह बताना है कि अगर वह कृषि आधरित उद्योग-धंधों को, कृषि आधारित अर्थनीति को अपना मार्गदर्शक नहीं बनाएंगे, तो वह पांच साल बीतते-बीतते मनमोहन सिंह से ज़्यादा खराब प्रधानमंत्री माने जाएंगे. वह प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, वह तानाशाह भी बन सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों के महानायक नहीं रह पाएंगे. नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से स्वयं को देश के सामने प्रस्तुत किया है, वह सिनेमा के पर्दे पर 5 फीट के आदमी को 16 फीट का आदमी दिखाने जैसा है. महान नायक अथवा महान खलनायक बनना, यह विलक्षण चुनाव 2015 ने हमारे सामने रख दिया है. देश में लोकतंत्र को सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली मानने वाले लोगों के लिए 2015 खुशियां भी ला सकता है और अपार दु:ख भी ला सकता है. पर आशा करनी चाहिए कि इस विलक्षण चुनाव में महानायक की जीत होगी, महा-खलनायक की नहीं. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

सभी राजनीतिक दलों को वैचारिक रूप से सहमति रखने वाली अपनी छोटी-छोटी इकाइयों से परेशानी रहती है. उक्त लोग पार्टी के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, ताकि वे अपना मुख्य एजेंडा लागू करा सकें. प्रत्येक पार्टी को पता रहता है कि बहुमत हासिल करने के लिए इन इकाइयों को खामोश रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हें आम स्वीकार्यता नहीं होती.

ऐसे साथियों के होते दुश्मनों की क्या ज़रूरत

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में ट्रेड यूनियन ब्रिटेन में बहुत शक्तिशाली थीं. वे सरकारी नीतियों (खास तौर पर लेबर सरकार की नीतियों) को प्रभावित कर सकते थीं. साठ के दशक में जब हेरोल्ड विल्सन प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक ट्रेड यूनियन नेता के बारे में अपना मशहूर वक्तव्य दिया था, गेट योर टैंक्स ऑफ माई फ्रंट लॉन (अनुचित दबाव का उपयोग करने की कोशिश मत करो). उनकी बेचैनी की वजह यह थी कि महंगाई कम करने की उनकी विवेकपूर्ण नीति पर ट्रेड यूनियन ने विरोध करना शुरू कर दिया था. विल्सन का यह आग्रह एक ऐसे नेता की कशमकश को प्रतिबिंबित करता था, जो अपने उग्र समर्थकों को नियंत्रित न कर सकता हो. लेकिन, लेबर पार्टी की हिमायती समझी जाने वाली ट्रेड यूनियन की इसी हेकड़ी की वजह से जब मार्गरेट थैचर ने उनका मुकाबला करना शुरू किया, तो लेबर पार्टी और यूनियन को लगातार कई बार पराजय का सामना करना पड़ा.

विल्सन की बेचैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वह समावेशी विकास और सामाजिक सद्भाव के वादे के साथ सत्ता तक पहुंचे थे, लेकिन उनके सहयोगी एवं साथी कुछ और ही सोच रहे हैं. उन्हें सबक की बात कौन कहे, सबके विकास से भी कोई मतलब नहीं है. स्वच्छ भारत उनके लिए अप्रासंगिक है. मेक इन इंडिया का पर्याय उनके लिए यह है कि भारत के सभी अल्पसंख्यकों को हिंदू बना दिया जाए. उन्हें अपना एजेंडा पूरा करने की जल्दी है. इसलिए वे मोदी को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक कमल का राज है, हंगामा करते रहो. यदि मोदी के पास ऐसे साथी होंगे, तो उन्हें दुश्मनों की आवश्यकता नहीं होगी. यही वजह है कि विपक्ष को संसद की कार्रवाई बार-बार बाधित करने का मौक़ा मिल गया. यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट पर अपने पद का खौफ पैदा करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पिछली बेंच पर बैठने वाले सदस्य ज़्यादा समस्या पैदा कर रहे हैं. यह अमित शाह की चुनावी रणनीति का करिश्मा था, जिसकी वजह से उनमें से बहुतों को लोकसभा में बैठने के लिए एक सीट मिल गई. इससे पहले उन्हें इस तरह का कोई मंच नहीं मिला था. वे अपने एजेंडे पर काम कर रहे थे, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था. पर अब ऐसा करने से संसद की कार्रवाई बाधित होगी.

सभी राजनीतिक दलों को वैचारिक रूप से सहमति रखने वाली अपनी छोटी-छोटी इकाइयों से परेशानी रहती है. उक्त लोग पार्टी के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, ताकि वे अपना मुख्य एजेंडा लागू करा सकें. प्रत्येक पार्टी को पता रहता है कि बहुमत हासिल करने के लिए इन इकाइयों को खामोश रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हें आम स्वीकार्यता नहीं होती. किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता हासिल करने और सत्ता पर बने रहने का मकसद यह होना चाहिए कि वह मतदाताओं एवं उनके परिवार की स्थिति में सुधार के लिए कारगर क़दम उठाए. उसे लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क़ पैदा करने वाले ठोस काम करके उनका विश्वास हासिल करने की ज़रूरत होती है. यह सौ मीटर की दौड़ के बजाय एक मैराथन दौड़ की तरह है. लेकिन, किसी समूह के विचारक व्यवहारिक मामलों की परवाह नहीं करते. वे भविष्य को लेकर काफी आशांवित रहते हैं और उन्हें बहुत जल्दी भी रहती है. बिजली, सड़क, शिक्षा एवं मकान जैसे मुद्दे इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों का हिंदू धर्म में धर्मांतरण उनके लिए अधिक आवश्यक होता है. बुनियादी ढांचे का विकास या बुलेट ट्रेन रोक कर राम मंदिर उनकी तरजीह होती है. सबका साथ का अब कोई मतलब नहीं है. मुसलमानों से मुक्ति उनका वर्षों से सपना रहा है.

भाजपा की एक जटिल समस्या है. उसने हाल में पूर्ण बहुमत हासिल किया है. विधानसभा चुनावों में भी उसने अपनी स्थिति मजबूत की है. अगर वह अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित कर ले, तो कांग्रेस की तरह सत्ता पर एकाधिकार हासिल कर लेगी. लेकिन, भाजपा भी अपनी मर्ज़ी की मालिक नहीं है. किसी संयुक्त हिंदू परिवार की तरह वह कमाऊ सदस्य तो ज़रूर बन सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि परिवार चलाने के लिए वह क़ानून भी बना सके. घर के बड़े- बुजुर्ग और दूर के रिश्तेदार अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं. परिवार एक समस्या है. उनके पास एक सांस्कृतिक एजेंडा है, जिसके लिए वे सड़कों पर उतरने को तैयार हैं. हैरानी इस बात की नहीं कि उनका कोई एजेंडा है, बल्कि यह कि वे अपना एजेंडा लागू करने के लिए आतुर हैं. यहां यह भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि वे क़ानून का सम्मान करना नहीं चाहते हैं. नरेंद्र मोदी अपने सपनों का भारत बनाने के लिए दस साल का समय चाहते हैं. फिलहाल कोई ऐसा विपक्ष नहीं है, जो संसद के वेल में पहुंचने के अलावा कुछ कर सकता है. जिस तरह से वह एक राज्य के बाद दूसरे राज्य को जीतते जा रहे हैं, राज्यसभा पर भी उनका नियंत्रण हो जाएगा. इसके बावजूद भाजपा जम्मू-कश्मीर में तीन सीटों की कमी की वजह से सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई. क्या ऐसा नहीं है कि साध्वी के बयान की वजह से पार्टी की उक्त सीटें कम हो गईं? यदि इस तरह के कुछ और मामले सामने आए, तो पार्टी के राज्यसभा में बहुमत पाने के सपने सिर्फ़ सपने ही रह जाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्वाइन फ्लू : डरें नहीं इलाज और बचाव आसान है

मोनिशा भटनागर

स्वाइन फ्लू श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी है, जो ए टाइप के इनफ्लुएंजा वायरस से होती है. यह वायरस एच1 एन1 के नाम से जाना जाता है और मौसमी फ्लू में भी यह वायरस सक्रिय होता है. 2009 में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, उसके साल के मुकाबले इस बार का स्वाइन फ्लू कम पावरफुल है.

कैसे फैलता है : जब आप खांसते या छींकते हैं तो हवा में या जमीन पर या जिस भी सतह पर मुंह और नाक से निकले द्रव कण गिरते हैं, वह वायरस की चपेट में आ जाता है. यह कण हवा के द्वारा या किसी के छूने से दूसरे व्यक्ति के शरीर में मुंह या नाक के जरिए प्रवेश कर जाते हैं.

शुरुआती लक्षण:

- नाक का लगातार बहना, छींक आना, नाक जाम होना.
- मांसपेशियां में दर्द या अकड़न महसूस करना.
- सिर में भयानक दर्द.
- कफ और कोल्ड, लगातार खांसी आना.
- बहुत ज्यादा थकान महसूस होना.
- बुखार होना, दवा खाने के बाद भी बुखार का लगातार बढ़ना.
- गले में खराश होना और इसका लगातार बढ़ते जाना.

किसे है ज्यादा खतरा:

5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, फेफड़ों, किडनी या दिल की बीमारी वाले लोग, मस्तिष्क संबंधी (न्यूरोलॉजिकल) बीमारी मसलन पर्किंसन, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, डायबीटीज जैसी बीमारियों के शिकार.

बचाव और इलाज:

- साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए और फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही सावधानी बरती जाए, तो इस बीमारी

के फैलने की आशंका न के बराबर हो जाती है.
- जब भी खांसी या छींक आए तो रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें.
- इस्तेमाल किए मास्क या टिश्यू पेपर को ढक्कन वाले डस्टबिन में फेंकें.
- थोड़ी-थोड़ी देर में हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें.
- लोगों से मिलने पर हाथ मिलाने, गले लगने या चूमने से बचें.
- फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें.
- अगर फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरों से 1 मीटर की दूरी पर रहें.
- फ्लू के लक्षण दिखने पर घर पर रहें. ऑफिस, बाजार, स्कूल न जाएं.
- बिना धुले हाथों से आंख, नाक या मुंह छूने से परहेज करें.

आयुर्वेद के मुताबिक भी आप कुछ नुस्खे आजमा कर इससे बचाव कर सकते है :

- 4-5 तुलसी के पत्ते, 5 ग्राम अदरक, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर और इतनी ही हल्दी को एक कप पानी या चाय में उबालकर दिन में दो-तीन बार पिएं.
- गिलोय (अमृता) बेल की डंडी को पानी में उबाल या छानकर पिएं.
- गिलोय सत्व दो रत्ती यानी चौथाई ग्राम पौना गिलास पानी के साथ लें.
- 5-6 पत्ते तुलसी और काली मिर्च के 2-3 दाने पीसकर चाय में डालकर दिन में दो-तीन बार पिएं.
- आधा चम्मच हल्दी पौना गिलास दूध में उबालकर पिएं. आधा चम्मच हल्दी गरम पानी या शहद में मिलाकर भी लिया जा सकता है.
- आधा चम्मच आंवले पाउडर को आधा कप पानी में मिलाकर दिन में दो बार पिएं. इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

योग

शरीर के प्रतिरक्षा और श्वसन तंत्र को मजबूत रखने में योग मददगार साबित होता है. अगर यहां बताए गए आसन किए जाएं, तो फ्लू से पहले से ही बचाव करने में मदद मिलती है. स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले अभ्यास करें: कपालभाति, ताड़ासन, महावीरासन, उत्त-ानपादासन, पवनमुक्तासन, भुजंगासन, मंडूकासन, अनुलोम-विलोम और उज्जायी प्राणायाम तथा धीरे-धीरे भस्त्रिका प्राणायाम या दीर्घ श्वसन और ध्यान.

खान-पान: घर का ताजा बना खाना खाएं. पानी ज्यादा पिएं. ताजे फल, हरी सब्जियां खाएं. मौसमी, संतरा, आलूबुखारा, गोल्डन सेव, तरबूज और अनार अच्छे हैं. सभी तरह की दालें खाई जा सकती हैं. नींबू-पानी, सोडा व शर्बत, दूध, चाय, सभी फलों के जूस, मट्ठा व लस्सी भी ले सकते हैं. बासी खाना और काफी दिनों से फ्रिज में रखी चीजें न खाएं. बाहर के खाने से बचें.

मास्क

मास्क पहनने की जरूरत सिर्फ उन्हें है, जिनमें फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे हों. फ्लू के मरीजों या संदिग्ध मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को भी मास्क पहनने की सलाह दी जाती है. भीड़ भरी जगहों मसलन, सिनेमा हॉल या बाजार जाने से पहले सावधानी के लिए मास्क पहन सकते हैं. मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल में काम करने वाला दूसरा स्टाफ. एयरकंडीशंड ट्रेनों या बसों में सफर करने वाले लोगों को ऐहतियातन मास्क पहन लेना चाहिए.

किस तरह का मास्क पहने: स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सामान्य मास्क कारगर नहीं होता, लेकिन थ्री लेयर सर्जिकल मास्क को चार घंटे तक और एन-95 मास्क को आठ घंटे तक लगाकर रख सकते हैं. ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क लगाने से वायरस से 70 से 80 पर्सेंट तक बचाव रहता है और एन-95 से 95 पर्सेंट तक बचाव संभव है. वायरस से बचाव में मास्क तभी कारगर होगा जब उसे सही ढंग से पहना जाए. जब भी मास्क पहनें, तब ऐसे बांधें कि मुंह और नाक पूरी तरह से ढक जाएं क्योंकि वायरस साइड से भी अटैक कर सकते हैं. एक मास्क चार से छह घंटे से ज्यादा देर तक न इस्तेमाल करें, क्योंकि खुद की सांस से भी मास्क खराब हो जाता है. सिर्फ ट्रिपल लेयर और एन 95 मास्क ही वायरस से बचाव में कारगर हैं. सिंगल लेयर मास्क की 20 परतें लगाकर भी बचाव नहीं हो सकता. मास्क न मिले तो मलमल के साफ कपड़े की चार तहें बनाकर उसे नाक और मुंह पर बांधें. यह सस्ता व सुलभ साधन है. इसे धोकर दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

मास्क की कीमत : थ्री लेयर सर्जिकल मास्क : 10 से 12 रुपये, एन-95 : 100 से 150 रुपये. ■

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली में इलाज

- जीटीबी अस्पताल, दिलशाद गार्डन
- एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली गेट
- सफदरजंग अस्पताल, रिंग रोड
- राम मनोहर लोहिया अस्पताल, बाबा खड़क सिंह मार्ग
- दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरिनगर
- संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मंगोलपुरी
- लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, खिचड़ीपुर
- पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल, मालवीय नगर
- चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, गीता कॉलोनी

महिला जासूस

अन्ना ने सुंदरता को बनाया हथियार

अरुण तिवारी

अन्ना को नौ अन्य लोगों के साथ रूस के लिए जासूसी करने के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था. बाद में एक समझौते के तहत उन्हें मॉस्को भेज दिया गया था. अन्ना चैपमैन अमरीका में गुप्त रूप से रह रही थीं. अन्ना चैपमैन (न्यूयॉर्क पोस्ट ने उन्हें रेड हॉट ब्यूटी' कहा था) समेत दस रूसी जासूसों को अमरीका से निकाल दिया गया था. बदले में रूस ने ऐसे चार कैदियों को देश छोड़ने की इजाज़त दी थी, जिन्हें राजद्रोह का दोषी पाया गया था. अन्ना को बाद में सत्ताधारी रूसी पार्टी में युवा कमान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. वे रूस के प्रधानमंत्री ब्लादिमीर पुतिन की चहेती हैं. इससे पहले अन्ना को सांसद बनाया गया था. अन्ना अमेरिका से वापस आने के बाद अपनी खूबसूरती के कारण काफी चर्चित हुई है. उन्हें कई ग्लैमर पत्रिकाओं ने कवर पेज पर जगह दी.

31 वर्षीय अन्ना चैपमैन रूस की उन जासूसों में से हैं जिन्होंने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था. रूस के लिए जासूसी करने वाली अन्ना चैपमैन को अमेरिका ने 2010 में गिरफ्तार कर लिया था आगे चलकर रूस में बंद अमेरिकी जासूसों के बदले उन्हें छोड़ा गया. अमेरिका से रिहाई के बाद वापस स्वदेश भेज दी गईं रूसी जासूस अन्ना चैपमैन ने अपनी रोमांचक जासूसी कहानी उजागर करने के लिए 2,50,000 डॉलर का सौदा किया. वह इस पैसे को अपने एक सहयोगी के स्विस बैंक खाते में मंगवाना चाहती हैं. अन्ना अमेरिकी समाज में अपनी घुसपैठ की कहानी से पैसा कमाना चाहती हैं. उन्होंने अपने लंदन के एक मित्र से इस कहानी को बेचने के लिए एक सौदा कराने के लिए कहा. समाचार पत्र न्यू यॉर्क पोस्ट के मुताबिक अन्ना को डर है कि अमेरिका और रूस के नियमों के चलते उन पर इस कहानी के लिए एक

31 वर्षीय अन्ना चैपमैन रूस की उन जासूसों में से हैं जिन्होंने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था. रूस के लिए जासूसी करने वाली अन्ना चैपमैन को अमेरिका ने 2010 में गिरफ्तार कर लिया था.

मित्र के जरिए सौदा करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. एक सूत्र के हवाले से यह खबर दी गई कि अन्ना की कमाई बंद हो गई है. उन्हें अपना अचल संपत्ति का कारोबार छोड़ना पड़ा और उन्हें रूसी सरकार से कोई पैसा नहीं मिल रहा है. वह जानती हैं कि मीडिया से सौदा करके ही वह पैसा कमा सकती हैं. उन्हें यह कहानी प्लेबॉय पत्रिका को बताने का भी सुझाव दिया गया था. सूत्र ने कहा कि उन्हें इस कहानी पर आधारित किताब लिखने और फिल्म बनाने के अधिकार बेचने हैं लेकिन उन्हें पैसा लेने में सावधानी बरतनी होगी. उन्हें सीधे खुद पैसा लेने की बजाए एक मित्र के स्विस खाते में पैसा मंगाने की सलाह दी गई. अमेरिकी अधिकारियों के साथ अपनी दलील में अन्ना इस बात पर सहमत हो गई थीं कि वह अपनी कहानी से लाभ नहीं कमाएंगी और उन्होंने कहा था कि इससे मिलने वाला पैसा संघीय सरकार का होगा.

रूस की सबसे तेज़ गुप्तचरों में से एक अन्ना चैपमैन ने सीआईए के पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन से विवाह का प्रस्ताव भी रखा है. स्नोडेन बीते 8 दिनों से रूस के शेरेमेतवा हवाई अड्डे के पारागमन क्षेत्र में शरण लिये हुये है. स्नोडेन ने भारत सहित देश के करीब तीन दर्जन देशो से शरण मांगी थी लेकिन अमेरिका से अपने रिश्ते खराब न हो इस वजह से इन देशों ने एडवर्ड स्नोडेन को शरण नहीं दी. अब रूस की टॉप गुप्तचर एजेंसी की पूर्व एजेंट चैपमैन ने अपने ट्वीटर एकाउंट पर स्नोडेन से विवाह का प्रस्ताव कर सनसनी फैला दी. 30 वर्षीय स्नोडेन ने अमेरिका द्वारा दूसरे देशों जासूसी संबंधी खुफिया जानकारियों को निकाल कर जगजाहिर कर दिया था. इसी के बाद एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिका छोड़ दिया और अन्य देशों में शरण देने की मांग करने लगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तान

आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत

वसीम अहमद

वर्ष 2014 जाते–जाते एक ऐसा घाव दे गया, जिसका दर्द पूरी दुनिया ने महसूस किया. 16 दिसंबर इस वर्ष का सबसे मनहूस दिन साबित हुआ, जब 132 मासूम बच्चों समेत 141 लोगों को तालिबान के दरिंदों ने मौत के घाट इतार दिया. इस घटना पर न केवल पाकिस्तान, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया ने शोक मनाया. ऐसा पहली बार हुआ है कि मासूम बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में आतंकवाद का निशाना बनाया गया हो. पाकिस्तान में आतंकवादियों का हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी आतंकवाद को गंभीरता से नहीं लिया. हाफिज़ सईद, हक्कानी और पाकिस्तानी तालिबान उसकी ज़मीन पर फलते–फूलते रहे, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए कभी कोई गंभीर क़दम नहीं उठाया गया. अब जबकि वे भयावह रूप धारण कर चुके हैं और पाक को ही ज़ख्म दे रहे हैं, तो पाकिस्तान ने दर्द का एहसास किया, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस दर्द की दवा के लिए गंभीर हो पाएगा? सर्वदलीय बैठक में आतंकवादियों को मिटाने का जो संकल्प उसने किया है, क्या उस पर क़ायम रह पाएगा? एक अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान आतंकवाद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में आतंकवादियों का मापदंड तय करता है. अगर वह ऐसे

पाकिस्तानी उलेमाओं की एक बड़ी संख्या के अलावा तालिबानी उनके विरोधी थे, क्योंकि वह जनरल जिया की सरकार को काला दौर करार देने के अलावा ताज़ीरात-ए-पाकिस्तान में एक संवैधानिक अनुच्छेद सी-395 का विरोध करते थे. उनके हत्यारों को आज तक सजा नहीं मिल सकी, क्योंकि एक बड़ा धार्मिक वर्ग रुकावट बन रहा है. ज़ाहिर है, यह वर्ग राजनीति पर गहरा प्रभाव रखता है और इसका समर्थन हाफिज़ सईद जैसे लोगों को हासिल है. यही वजह है कि ज़कीउर्रहमान लखवी जैसे आतंकवादी को आतंकवाद निरोधी अदालत से ज़मानत मिल जाती है, जबकि मुंबई हमले में उसके शामिल होने के पुख्ता सबूत मौजूद हैं.

संगठनों को आतंकवादी नहीं मानता, जो पाकिस्तान में तो कुछ न करें, लेकिन वहां से प्रशिक्षण हासिल करके दूसरे देशों में खून की होली खेलें, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद से निपटने में सफल नहीं हो सकेगा. पाकिस्तान पहले भी ऐसी ग़लती कर चुका है. उसके विदेश मंत्रालय से संबंध रखने वाले सरताज अज़ीज़ जैसे लोग यह बयान दे चुके हैं कि हम उन्हें क्यों निशाना बनाएं, जो हमें नुक़सान नहीं पहुंचाते. तो ऐसे में, तालिबानियों का हौसला बढ़ेगा ही. अब पाकिस्तान को चाहिए कि वह आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए हर उस संगठन को निशाना बनाए, जो अपनी बात बंदूक की नोंक पर मनवाना चाहता है. बंदूक का इस्तेमाल लाल मस्जिद और पेशावर के स्कूल में हो या फिर जम्मू–कश्मीर में.

विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद ख़त्म करने के लिए न केवल लड़ाका संगठनों, बल्कि वहां की जनता, राजनीतिज्ञों और स्वयं सेना के अंदर एक विशेष वर्ग से निपटना होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो धार्मिक मामलों में कट्टर हैं. ये लोग तालिबानियों के प्रति नरमी रखते हैं. इस वर्ग का पाकिस्तान की राजनीति पर गहरा प्रभाव है. पाकिस्तान में चाहे जिसकी भी सरकार हो, इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो पाती. पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर का क़त्ल हमारे सामने है. 2011 में उन्हें उग्रवादी संगठनों ने मार दिया था. पाकिस्तानी उलेमाओं की एक बड़ी संख्या के अलावा तालिबानी उनके विरोधी थे, क्योंकि वह जनरल जिया की सरकार को काला दौर करार देने के अलावा ताज़ीरात–ए–पाकिस्तान में एक संवैधानिक अनुच्छेद सी–395 का विरोध करते थे. उनके हत्यारों को आज तक सजा नहीं मिल सकी, क्योंकि एक बड़ा धार्मिक वर्ग रुकावट बन रहा है. ज़ाहिर है, यह वर्ग राजनीति पर गहरा प्रभाव रखता है और इसका समर्थन हाफिज़ सईद जैसे लोगों को हासिल है. यही वजह है कि ज़कीउर्रहमान लखवी जैसे आतंकवादी को आतंकवाद निरोधी अदालत से ज़मानत मिल जाती है, जबकि मुंबई हमले में उसके शामिल होने के पुख्ता सबूत मौजूद हैं. लखवी की ज़मानत पर भारत ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी और संसद में निंदा की, तब जाकर पाकिस्तान सरकार ने इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने का फ़ैसला किया. ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर दबाव बनाए बिना पाकिस्तान सरकार के लिए आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना टेढ़ी खीर साबित होगा.

इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकता. अगर वह वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सच्चाई के साथ क़दम आगे बढ़ाए, तो अपनी ज़मीन को आतंकवादियों के लिए तंग कर सकता है. विशेष रूप से पेशावर स्कूल हमले के बाद फिलहाल आतंकवादियों के ख़िलाफ़ एक आम लहर है और उस लहर का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ज़र्ब–ए–अज़ब और ऑपरेशन ख़ैबर–1 को कामयाब बना सकता है. इस समय आतंकवादियों के ख़िलाफ़ सभी राजनीतिक दल भी सरकार के साथ हैं. सरकार इसका फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि वह इस संबंध में गंभीर है. अगर वह गंभीर होती, तो हाफ़िज सईद यह कहने की जुर्रत न करता कि पेशावर स्कूल कांड के पीछे भारत का हाथ है और बदले में वह भी भारत को ऐसा ही दर्द देगा. पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ का बयान भी आतंकवादियों से ध्यान भटकाने की कोशिश लगता है. उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है. पाकिस्तानी तालिबान की ओर से हमले की ज़िम्मेदारी लेने के बावजूद उसका आरोप भारत पर डालकर तालिबानियों के प्रति पाई जाने वाली नफ़रत कम करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं. इस समय पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में 500 ऐसे कैदी हैं, जो आतंकवाद के आरोप में सजा–ए–मौत पा चुके हैं, लेकिन 2008 में रोक लगने के कारण उनकी फांसी रोक दी गई थी. लेकिन, 16 दिसंबर की घटना के बाद प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के आदेश पर ब्लैक वारंट जारी करते हुए फांसी की सजा दोबारा बहाल कर दी गई. ब्लैक वारंट के बाद कई लोगों को फांसी दी जा चुकी है. 50 से अधिक कैदियों की दया याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं. लेकिन, समस्या केवल इन 500 कैदियों, ज़र्ब–ए–अज़ब और ऑपरेशन ख़ैबर में तेज़ी लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हाफ़िज सईद और हक्कानी जैसे शांति विरोधी चेहरों को भी गिरफ्त में लेने की ज़रूरत है. वरना पाकिस्तान कभी भी इस स्थिति में नहीं आ सकेगा कि अपनी ज़मीन से आतंकवाद का ख़ात्मा कर सके. हाफिज सईद और हक्कानी जैसे लोग बेशक पाकिस्तान को प्रत्यक्ष नुक़सान नहीं पहुंचाते, लेकिन उनके द्वारा अन्य आतंकवादी संगठनों को संरक्षण दिया जाता है. अब अगर वास्तव में पाकिस्तान सरकार अपनी ज़मीन से आतंकवाद को मिटाना चाहती है और यह चाहती है कि फिर से पेशावर जैसी घटना न हो, तो उसे इन तमाम संगठनों, ताकतों के विरुद्ध सख्त क़दम उठाने होंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

आईएसआईएस के पीछे कौन है

चौथी दुनिया ब्यूरो

इराक के जिन हिस्सों पर आईएसआईएस ने क़ब्जा कर रखा है, वहां महिलाओं को सरेआम बेचा जाता है, बच्चों को अलफोजा के बाज़ार में केवल 10 डॉलर में बेच दिया जाता है, सिक्लाविया में जबरन निकाह क़बूल न करने पर 150 महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, लेकिन कोई उसके ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं करता. मूसल के शिक्षण संस्थानों के भवनों पर आईएसआईएस का झंडा लहराया जाता है, लेकिन प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं कि वह एक शब्द बोल सके. शहर की गलियों में घोषणा की जाती है कि लोग अपनी बेटियों का निकाह जेहादियों से कराएं, लेकिन कोई इस फरमान के ख़िलाफ़ जुबान नहीं खोल सकता. पश्चिमी इराक में सुन्नी क़बीले बूनमर के 238 नौजवानों को लाइन में बैठाकर गोलियां मार दी जाती हैं और पूरा समाज खामोशी धारण कर लेता है. शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के नाम पर हजम कर लिया जाता है, लेकिन क्या मजाल कि कोई चूं भी कर सके. क्योंकि, जिसने भी आईएसआईएस के फरमान को नहीं माना, उसे सख्त सज़ा मिलेगी.

अभी हाल में मूसल के पश्चिम में कोह संजारा के समीप पांच लाख की आबादी वाली यज़ीदिया कौम की 150 महिलाओं को अलफोजा शहर के नज़दीक सिक्लाविया में केवल इसलिए मार दिया, क्योंकि उन्होंने जेहादियों से जबरन शादी करने से इंकार कर दिया था. इससे पूर्व मूसल शहर में 700 यज़ीदी महिलाओं को सरे बाज़ार बेच दिया गया. जिसने सबसे अधिक बोली लगाई, वही उनका हक़दार बना. एक वीडियो में इन महिलाओं को जानवरों की तरह ज़जीर में बांधकर हांकते हुए दिखाया गया था. अफ़सोस की बात तो यह है कि 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा था और उसी दौरान संजारा पहाड़ पर रहने वाली यज़ीदी क़बीले की महिलाओं को मूसल के बीच बाज़ार में सरेआम बेचा जा रहा था, लेकिन दुनिया की बड़ी ताक़तें इस जुल्म को रोकने में असफल रहीं. इसी का परिणाम है कि आईएसआईएस का हौसला बढ़ता जा रहा है. अगर कुर्द सेना अमेरिकी सेना के सहयोग से किसी क्षेत्र को आईएसआईएस से ख़ाली कराती है, तो कुछ दिनों बाद ही आईएसआईएस नई ताक़त के साथ आगे बढ़ता है और दोबारा उस क्षेत्र पर क़ब्जा जमा कर है. कुछ दिनों पहले सलाहुद्दीन सूबे के बेजी रिफाइनरी पर से आईएसआईएस का क़ब्जा हटाया गया था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही आईएसआईएस ने पुन: उस पर क़ब्जा कर लिया.

इन घटनाओं के माध्यम से यहां यह बताना है कि दुनिया में सुपर पॉवर कहलाने वाली अमेरिकी सरकार और संयुक्त राष्ट्र इस आतंकवादी संगठन के सामने बेबस हैं. अमेरिका का विदेश मंत्रालय कहता है कि आईएसआईएस को ख़त्म करने में लंबा समय लग सकता है. लेकिन, हालात का जायजा लेने से ऐसा महसूस होता है कि इस अंतराल में आईएसआईएस अधिक मज़बूत होगा, क्योंकि उसने अभी से ही अधिकृत इराक की नई नस्ल को अपनी तर्ज़ पर प्रशिक्षण देने का माहौल बनाना शुरू कर दिया है. इसके लिए उसने एक ओर आम लोगों से अपनी बेटियों का निकाह जेहादियों से करने की अपील की है, वहीं दूसरी ओर वह स्कूलों एवं मदरसों में अपनी मर्ज़ी का पाठयक्रम चलाने पर ज़ोर डाल रहा है. इराक में तालीमी सेशन शुरू हो चुका है. नया तालीमी सेशन शुरू होते ही आईएसआईएस ने शैक्षणिक संस्थानों को कुछ निर्देश भेजे और साथ ही यह धमकी भी दी कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ, तो उक्त संस्थाएं बंद कर दी जाएंगी या फिर वहां के कर्मचारियों की नौकरियां ख़त्म कर दी जाएंगी. आईएसआईएस की ओर से जारी निर्देशों से अनुमान लगाया जा सकता है कि अब वह शैक्षणिक संस्थानों पर भी अपना नियंत्रण बनाकर वहां के बच्चों को अपने अनुसार प्रशिक्षित करना चाहता है. यह भी कहा गया है कि लड़के–लड़कियों के स्कूल अलग–अलग होने चाहिए. इसके अलावा लड़कियों के लिए आवश्यक होगा कि वे काले नक़ाब से अपने चेहरे को ढंककर रखें. जो लड़कियां काले नक़ाब में नहीं आएंगी, उन्हें सज़ा दी जाएगी. आईएसआईएस ने कला–संस्कृति के सभी क्षेत्रों के अलावा राजनीति एवं विज्ञान का क्षेत्र भी बंद कर देने का निर्देश दिया है. एक विशेष निर्देश यह दिया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों की इमारतों पर आईएसआईएस का झंडा लगाया जाए और उल्लंघन करने वालों को उसका विरोधी समझा जाएगा. आईएसआईएस की ओर से जारी निर्देशों ने इराक के शैक्षणिक संस्थानों को मुश्किल में डाल दिया है. वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, क्या न करें. एक ओर कुआं है, तो दूसरी ओर खाई. अगर वे आईएसआईएस की बात मानकर उसका झंडा अपनी इमारतों पर लगाते हैं, तो बगदाद सरकार नाराज़ होगी, क्योंकि शिक्षकों के वेतन वहीं से दिए जाते हैं. और, अगर वे सरकार की नाराज़गी से बचते हैं, तो आईएसआईएस नाराज़.

मूसल क्षेत्र पर आईएसआईएस का क़ब्ज़ा है. अब ज़ाहिर है, जनता उसके फरमानों पर अमल करती है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि जनता आईएसआईएस को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि जबसे आईएसआईएस हावी हुआ है, तबसे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल बन गई है. बिजली नहीं है. अगर कभी बिजली आती है, तो बस थोड़ी देर के लिए. आईएसआईएस के क़ब्जे से पहले जिस जगह पर पीने के लिए साफ़ पानी का ज़ख़ीरा हुआ करता था, अब वहां पर गंदा पानी जमा रहता है. लोग उसी पानी को कपड़े से छानकर पीते हैं. खाना बनाने के लिए उनके पास ईंधन नहीं है. ईंधन इतना महंगा है कि आम आदमी ख़रीद नहीं सकता. परिणामस्वरूप लोग कूड़ा–कचरा जमा करके आग जलाते हैं और उस पर किसी प्रकार खाना बनाते हैं. घरों में कूड़ा–कचरा जलाने की वजह से ज़हरीला धुआं बनता है, जिससे बच्चों और बूढ़ों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है. होटलों में खाना बहुत महंगा होता है. दरअसल, होटलों को ईंधन बहुत ज़्यादा क़ीमत पर उपलब्ध होता है, क्योंकि क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट से आईएसआईएस टैक्स के नाम पर बड़ी रक़म वसूल करता है. जबरन टैक्स वसूल करने का यह सिलसिला यहीं तक नहीं है. जिन क्षेत्रों में आईएसआईएस का क़ब्जा है, वहां भी सरकारी विभागों के वेतन बगदाद से अदा किए जाते हैं. मूसल के एक हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक सैयद मोहम्मद के अनुसार, जब वेतन बंटता है, तो उस समय आईएसआईएस का एक आदमी वहां पर मौजूद रहता है और पहचान करके टैक्स वसूल करता है. अगर कोई शिक्षक किसी कारणवश वेतन लेने नहीं आ सका, तो आईएसआईएस के लोग उसका वेतन ले लेते हैं और जेहादी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं. किसी भी शिक्षक को बाद में वेतन लेने का अधिकार नहीं है. आईएसआईएस अधिकृत क्षेत्रों की सामाजिक ज़िंदगी में भी अपने आदेश जारी करता रहता है. फलूजा में नहर फरात एक पर्यटन स्थल है, जहां महिलाएं एवं पुरुष बड़े शौक से तैराकी करते थे, लेकिन जबसे आईएसआईएस का क़ब्जा हुआ है, उसने वहां महिलाओं को नहाने से मना कर दिया है. नतीजा यह हुआ कि जिस फरात पर सुबह से शाम तक चहल–पहल रहती थी, पर्यटकों की भीड़ रहती थी, अब वहां चारों ओर सन्नाटा पसरा है.

इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आईएसआईएस दुनिया के क़ानून नहीं मानता. उसका अपना क़ानून है, जिसे वह अपनी ताक़त के बल पर मनवाता है. एक बड़ा सवाल यह है कि आख़िर उसे ताक़त कहां से मिलती है? हथियार कहां से मिलते हैं और उसके तेल के ख़रीददार कौन हैं? दरअसल, आईएसआईएस अधिकृत क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में तेल निकाल कर बेचता है. एक अनुमान के अनुसार, वह प्रतिदिन लगभग तीन मिलियन डॉलर का तेल बेचता है. वह विश्व बाज़ार के मुक़ाबले बहुत सस्ती क़ीमत पर तेल बेचता है, इसलिए उसे पिछले दरवाजे से बहुत ख़रीददार मिल जाते हैं, जिनमें तुर्की का नाम विशेष रूप से लिया जाता है. चोर दरवाज़े से बेचे गए तेल के अलावा उसके पास आमदनी का एक और स्रोत है, फिरौती में बड़ी रक़म वसूल करना. वह व्यवसायियों के रिश्तेदारों को अगवा करता है और फिर बदले में मोटी रक़म ऐंठता है. कहा जाता है कि क्षेत्र में शियाओं का प्रभाव रोकने के लिए उसे सउदी अरब, क़तर, अमीरात के अलावा कुछ अन्य देशों से ख़ुफिया सहायता भी मिलती है. अगर चोर दरवाजे से ख़रीद–फरोख्त की बात सच है, तो फिर उसी दरवाज़े से उसे हथियार भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं. मूसल पर क़ब्ज़े के दौरान उसे हथियारों का एक बड़ा जख़ीरा हाथ लगा था, जिसे वह अब तक इस्तेमाल कर रहा है. अगर आईएसआईएस के जुल्म का सिलसिला नहीं रोका गया, तो उसका वायरस इराक एवं सीरिया से निकल कर अन्य देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सियार एक बार फिर जोर से बोला ओ गुफा! रोज तु मेरी पुकार का के जवाब में मुझे अंदर बुलाती है. आज चुप क्यों हैं? मैंने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी, उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा. अच्छा तो मैं चला. यह सुनकर शेर हड़बड़ा गया. उसने सोचा शायद गुफा सचमुच सियार को अंदर बुलाती होगी. यह सोचकर कि कहीं सियार सचमुच न चला जाए, उसने अपनी आवाज बदलकर कहा सियार राजा, मत जाओ अंदर आओ न.

कण-कण में साई हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

शिरडी ही साई बाबा है और साई बाबा ही शिरडी. दरअसल, एक-दूसरे का प्रत्यक्ष पर्यायवाची होने के साथ-साथ यह आध्यात्मिक भी है. साई शब्द के उच्चारण से आशा और आदर का भाव उत्पन्न होता है. साई बाबा को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. ऐसा माना जाता है कि साई बाबा 1858 में औरंगाबाद से एक शादी समारोह में शिरडी आए थे. उन्होंने सबसे पहला शिविर खंडूबा मंदिर में लगाया था. वर्तमान समय में यह मंदिर श्री साई बाबा संस्थान के सामने स्थित है. शुरू शुरू में खंडूबा मंदिर के पुरोहित थे भगत महालसापति. उन्होंने साई बाबा का स्वागत किया, आओ साई कहकर. साई एक संत के रूप में जाने जाते हैं. पश्चिम महाराष्ट्र स्थित शिरडी भारत का प्रमुख धार्मिक स्थान है. कोई भी श्री साई बाबा की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता है. साई बाबा ने महालसापति से कहा था कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें बड़ा किसी मुस्लिम फकीर ने किया था. साई लोगों के घर-घर जाकर उनसे अल्ला मालिक कहकर भिक्षा मांगा करते थे. बहुत सारे लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे. बाबा प्रत्येक व्यक्ति से न केवल रात-दिन, बल्कि सप्ताह के सातों दिन ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा करते थे, जिसे नामसप्तक के नाम से भी जाना जाता है.

साई बाबा ने 15 अक्टूबर, 1918 को देह त्याग किया. वर्तमान समय में शिरडी में साई बाबा की सफेद संगमरमर की समाधि और एक बड़ी सी मूर्ति है. इस सर्वोत्तम मूर्ति की रचना मुंबई के मूर्तिकार भाहू साहब तलिम ने 1954 में की थी. भगवान विट्ठल की मूर्ति को शिरडी स्थित दीक्षित वाड़ा संग्रहालय में रखा गया है. श्री साई बाबा संस्थान एक विशाल प्रशासकीय इमारत और आध्यात्मिक मंदिर है. यहां स्थित शांति निवास में श्री साई वेंगमे कर्कशा नामक एक पुस्तकालय भी है. समाधि मंदिर में साई बाबा की समाधि है. प्रवेश स्थान से समाधि मंदिर की दूरी लगभग 800 मीटर है. यहां आए तीर्थयात्रियों के विश्राम के लिए अनेक बेंच लगाई गई हैं. मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा रहती है. मंदिर में चार बार आरती होती है. सुबह 5.15 पर होने वाली कक्कड़ आरती सबसे प्रमुख है. शिरडी में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार गुरु पूर्णिमा, दशहरा और रामनवमी हैं. इन त्योहारों के समय 24 घंटे के लिए समाधि मंदिर खुला रहता है.

श्री साई बाबा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में द्वारकामाई में ही ठहरे थे. द्वारकामाई एक पुरानी उबड़-खाबड़ मस्जिदनुमा कोठी थी. यहां बैठकर वह लोगों की समस्याओं, बीमारियों और चिंताओं को दूर करते थे. साई बाबा इसी द्वारकामाई में आकर रहने लगे. उनका मानना था कि सबका मालिक एक है. द्वारकामाई के प्रथम तल पर बाबा की फोटो और एक बड़ा पत्थर रखा है, जिस पर बाबा बैठा करते थे. यहां दो कमरे हैं. पहले कमरे में रथ और दूसरे में पालकी रखी है. पत्थर का एक चौकोर स्टूल भी है, जिसका इस्तेमाल बाबा नहाने के लिए करते थे. द्वारकामाई मस्जिद समाधि मंदिर के प्रवेश द्वार की दाईं ओर स्थित है. गुरुस्थान एक छोटा सा मंदिर है. इसमें शिवलिंग और साई बाबा की तस्वीर है. इस मंदिर में गुरुवार और शुक्रवार को बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं. यह वह स्थान है, जहां साई बाबा ने पहली बार शिरडी में बाल योगी के रूप में प्रवेश किया था. इसीलिए इसे गुरुस्थान के रूप में जाना जाता है. यहां एक छोटी सी मस्जिद भी है. मंदिर के प्रवेश द्वार पर शिवलिंग और नंदी का चित्र बना हुआ है. इसके अलावा, मंदिर में बारह ज्योतिर्लिंगों के चित्र भी लगे हैं. द्वारकामाई से थोड़ी ही दूरी पर साई बाबा की चावड़ी है. इस स्थान का प्रयोग बाबा सोने के लिए करते थे. चावड़ी दो भागों में विभाजित है. चावड़ी के पहले हिस्से में बाबा की एक बहुत बड़ी फोटो लगी है, वहीं दूसरे हिस्से में लकड़ी का पलंग और सफेद कुर्सी भी रखी हुई है.

अब्दुल बाबा की झोपड़ी से कुछ ही दूर मारुति मंदिर है. इस मंदिर में साई बाबा देवीदास (बाल योगी) के साथ सत्संग के लिए आते थे. देवीदास इस मंदिर में साई बाबा के आगमन से दस-बारह साल पहले से रह रहे थे. इसके अलावा, यहां शिरडी शनि, गणपति और शंकर के नाम से मंदिर भी हैं. गुरुस्थान से थोड़ी सी दूरी पर लेंडी बाग है. इसे स्वयं बाबा ने बनाया था. वह हर रोज यहां स्वयं पानी दिया करते थे. बाबा ने इस बाग को नुल्लाहा नाम दिया. इस बाग में बाबा सुबह-शाम नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए आते थे. इस बाग में आठ जगहों पर संगमरमर के पत्थरों से बने दीपगृह (नंदा दीप) हैं. यहां एक तरफ पीपल का पेड़ है, दूसरी ओर नीम का. खंडूबा मंदिर मुख्य मार्ग पर स्थित है. इसी मंदिर में पुजारी महालसापति ने साई बाबा का स्वागत आओ साई कहकर किया था. इस मंदिर में खंडूबा और महलसाई की मूर्तियां हैं. ■

साई बाबा ने 15 अक्टूबर, 1918 को देह त्याग किया, वर्तमान समय में शिरडी में साई बाबा की सफेद संगमरमर की समाधि और एक बड़ी सी मूर्ति है. इस सर्वोत्तम मूर्ति की रचना मुंबई के मूर्तिकार भाहू साहब तलिम ने 1954 में की थी. भगवान विट्ठल की मूर्ति को शिरडी स्थित दीक्षित वाड़ा संग्रहालय में रखा गया है. श्री साई बाबा संस्थान एक विशाल प्रशासकीय इमारत और आध्यात्मिक मंदिर है.

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

युवाओं को हुनरमंद बनाएं

मैगजीन में छपे एक चित्र में मैंने देखा कि एक 13 साल का लड़का चीन से आयात किए गए एके 47 के पुर्जों को असेंबल कर रायफल का रूप दे रहा है. जापान में 15 साल बेटा स्कूल भी जाता है और स्कूल के बाद प्रतिदिन तीन घंटे पिता के व्यवसाय में मदद भी करता है. सौभाग्य से भारत में सबसे अधिक युवा हैं. अगर सरकार उन्हें हुनरमंद बना दे तो हम पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे. सिर्फ बी.ए, बी.कॉम, की पढ़ाई से कुछ नहीं हासिल होने वाला. स्किल्ड लोगों की पूरी दुनिया में भारी मांग है. आज के अधिकांश स्नातक एक त्रुटिहीन प्रार्थनापत्र तक नहीं लिख पाते हैं. सरकार युवाओं को प्रोफेशनल व तकनीकि शिक्षा देकर उन्हें हुनरमंद बनाए.

-राजकिशोर पाण्डेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

केजरीवाल उड़ेगे या बचेंगे

अन्ना आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी के लिए आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अस्तित्व का सवाल है. आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अन्ना का साथ आंदोलन के बीच में ही छोड़ दिया. केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी(आम आदमी पार्टी) बना ली और 2013 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर जीत हासिल कर दूसरी सबसे पड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई. उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने. लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रही. केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दे दिया. केजरीवाल की महात्वाकांक्षा बड़ी थी और वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे. इसलिए उन्होंने जन लोकपाल बिल के बहाने दिल्ली मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. आम आदमी पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और केवल चारों सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई. दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 28 सीटें जीतकर दूसरे नंबर रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई. केजरीवाल ने वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए. आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करने की बात कर रही है. जब उसकी लोकप्रियता चरम पर थी तो उसने 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीती थी. लेकिन देखना होगा कि अब उसकी लोकप्रियता दिल्ली के साथ पूर देश में कम हुई है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने सीटें जीतती है. इसी के साथ यह भी पता चल जाएगा कि मोदी के आंधी में केजरीवाल उड़ जाते हैं या बच पाते हैं.

-कल्पना यादव, पालम, दिल्ली.

पत्रिकाएं ऐसी ही होनी चाहिए

गया जी तीर्थ(बिहार) की यात्रा से वापसी करते समय रेलवे बुकस्टॉल से आपकी साप्ताहिक पत्रिका चौथी दुनिया की एक प्रति प्राप्त हो गई और देखते ही मन पत्रिका की ओर आकर्षित हो गया. चौथी दुनिया पत्रिका खरीदी पढ़ी और आनन्द आ गया. वास्तव में साप्ताहिक पत्रिकाएं ऐसी ही होनी चाहिए. पूरी पत्रिका में ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो पढ़ने योग्य न हो. 10 नवंबर-16 नवंबर 2014 का अंक पढ़ा. प्रथम पृष्ठ से ही(मेरठ दंगा-सरकारी जांच का सबसे शर्मनाक अध्याय है) को पढ़कर ज्ञान में बृद्धि हुई. बहुत कठिन है डगर पनघट की(सांसद आदर्श ग्राम योजना), मांझी को डर लगता है, चुनाव ही बेहतर विकल्प है(दिल्ली), क्यों लाचार हो गई पुलिस, जम्मू-कश्मीर अगली सरकार भाजपा-पीडीपी की होगी, स्थायी सरकार सबसे बड़ा मुद्दा(झारखंड), दावेदारी की भरमार(औरंगाबाद), सपा की बेचैनी भढ़ा रहा है एमआईएम(दीनबंधु कबीर), राजनीतिक दलों का अराजनीतिक व्यवहार, देश के अंदर दबा पैसा कब वापस होगा, हिटलर की जासूस थी माताहारी और निराली है साई बाबा की महिमा. क्या-क्या गिनाऊं इतनी ढ़ेरों सारे विशिष्ट आलेख एंव सामग्री कहीं मिलेगी?

-सुदर्शन पराशर, होशियारपुर, पंजाब.

सबसे अच्छा समाचार पत्र

चौथी दुनिया सामाचार पत्र(15 दिसंबर-21 दिसंबर 2014) पढ़ा. इस अंक में प्रकाशित सभी खबरें काफी विचारोत्तेजक है. चौथी दुनिया समाचार पत्र पढ़ने के बाद कोई और समाचार पत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसमें सभी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं. इसमें प्रकाशित सभी आलेख तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद नई-नई जानकारियां हासिल होती हैं. इसमें कवर स्टोरी से लेकर सियासी दुनिया, विविध दुनिया, बाकी दुनिया, साहित्य दुनिया, साई महिमा और जगमग दुनिया यानी सभी पृष्ठों पर प्रकाशित सामग्री काफी अच्छी होती है. खासकर इसमें संतोष भारतीय, मनीष कुमार एवं कमल मोरारका का आलेख हमेशा नए मुद्दों पर होता है. चौथी दुनिया समचार पत्र आज के समय का सबसे अच्छा साप्ताहिक समाचार पत्र है.

-कमलेश सिंह, पटना, बिहार.

जनता से जुड़े मुद्दों पर हो चर्चा

जब तोप मुकाबिल हो-संसद को देशद्रोह के कलंक से बचाइए(15 दिसंबर-21 दिसंबर 2014) पढ़ा. तथ्यपरक संपादकीय है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि हमें सासंदों पर टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. इसके बारे में अब फैसला कर लेना चाहिए. पहले सांसद संसद में बहस करते थे, जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाते थे और उस पर चर्चा होती थी, लेकिन अब संसद में सासंदों का एक ही काम नजर आता है वह केवल हल्ला मचाना. सासंदों को चाहिए कि वह जनता से जुड़े मुद्दो को संसद में उठाएं और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें.

-इंद्रजीत मौर्या, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

कहानी

एक चतुर सियार

एक समय की बात है कि जंगल में एक शेर के पैर में कांटा चुभ गया और शेर के लिए दौडना असंभव हो गया. वह लंगड़ाकर मुश्किल से चलता. शेर के लिए तो शिकार करने के लिए दौड़ना जरुरी होता है. इसलिए वह कई दिन कोई शिकार न कर पाया और भूखों मरने लगा. कहते हैं कि शेर मरा हुआ जानवर नहीं खाता, लेकिन मजबूरी में सब कुछ करना पडता है. लंगड़ा शेर किसी घायल अथवा मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा. यहां भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया. कहीं कुछ हाथ नहीं लगा.

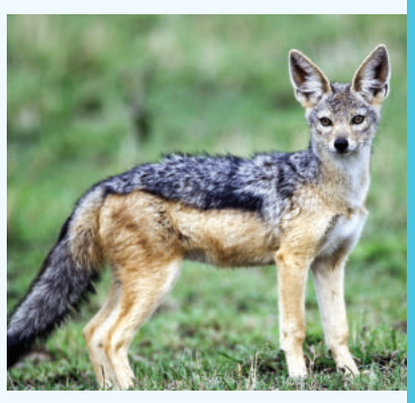

धीरे-धीरे पैर घसीटता हुआ वह एक गुफा के पास आ पहुंचा. गुफा गहरी और संकरी थी, ठीक वैसी जैसे जंगली जानवरों के मांद के रुप में काम आती हैं. उसने उसके अंदर झांका मांद खाली थी पर चारों ओर उसे इस बात के प्रमाण नजर आए कि उसमें जानवर का बसेरा है. उस समय वह जानवर शायद भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था. शेर चुपचाप दुबककर बैठ गया ताकि उसमें रहने वाला जानवर लौट आए तो वह दबोच ले. सचमुच उस गुफा में सियार रहता था, जो दिन को बाहर घूमता रहता और रात को लौट आता था. उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वह लौट आया. सियार काफी चालाक था. हर समय चौकन्ना रहता था. उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखें तो चौंका उसे शक हुआ कि कोई शिकारी जीव मांद में उसके शिकार की आस में घात लगाए न बठा हो. उसने अपने शक की पुष्टि के लिए सोच विचार कर एक चाल चली. गुफा के मुहाने से दूर जाकर उसने आवाज दी गुफा! ओ गुफा. गुफा में चुप्पी छायी रही उसने फिर पुकारा अरी ओ गुफा, तु बोलती क्यों नहीं? भीतर शेर दम साधे बैठा था. भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था. सियार एक बार फिर जोर से बोला ओ गुफा! रोज तु मेरी पुकार का के जवाब में मुझे अंदर बुलाती है. आज चुप क्यों हैं? मैंने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन तु मुझे नहीं बुलाएगी, उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा. अच्छा तो मैं चला. यह सुनकर शेर हड़बड़ा गया. उसने सोचा शायद गुफा सचमुच सियार को अंदर बुलाती होगी. यह सोचकर कि कहीं सियार सचमुच न चला जाए, उसने अपनी आवाज बदलकर कहा सियार राजा, मत जाओ अंदर आओ न. मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी. सियार शेर की आवाज पहचान गया और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहां से चला गया और फिर लौटकर नहीं आया. मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा-प्यासा मर गया. ■

शिक्षा : सतर्क व्यक्ति जीवन में कभी मार नहीं खाता.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

मेहनत की कमाई बेटा इस तरह गंवा रहा है, यह देखकर नारायण को चिंता होने लगी. उसकी इच्छा थी कि राजू बेटा बड़ा होकर सारा कारोबार संभाल ले और वह अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाए. बेटे को समझ आने की आस लगाए बैठा नारायण बुढ़ापे की तरफ़ बढ़ रहा था. फिर उसने गांव के ही एक विद्वान गृहस्थ से सलाह लेने की सोची.

ऑनलाइन बुक स्टोर के ख़तरे और चुनौतियां

अनंत विजय

दो हज़ार चौदह को किताबों की दुनिया या कहें कि प्रकाशन के कारोबार के लिहाज से भी अहम वर्ष के तौर पर देखा जाएगा. किताबों की दुनिया में दो ऐसी घटनाएं घटीं, जिन्होंने भारत में कम होती जा रही किताबों की दुकानों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है. पहले मशहूर लेखक चेतन भगत के उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड के लिए उसके प्रकाशक ने ऑनलाइन वेबसाइट फ्लिपकार्ट से समझौता किया. उस करार के मुताबिक प्रकाशक ने फ्लिपकार्ट को यह अधिकार दिया था कि पहले कुछ दिनों तक चेतन भगत की किताब सिर्फ़ फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन बुक स्टोर पर ही मौजूद रहेगी. बदले में फ्लिपकार्ट ने भी प्रकाशक को एकमुश्त साढ़े सात लाख प्रतियों का ऑर्डर दिया. चेतन भगत के उपन्यास की प्री–बुकिंग ही जमकर हुई. इस एक्सक्लूसिव करार की वजह से भारत में चेतन के लाखों प्रशंसकों ने फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन स्टोर से जाकर किताब खरीदी. जब तक उनका उपन्यास किताबों की दुकान तक पहुंचता, तब तक उसके पाठक उसे खरीद चुके थे. चेतन भगत के ज़्यादातर पाठक इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हैं, लिहाजा उनके लिए फ्लिपकार्ट से खरीद करना सुविधाजनक भी रहा था.

उस वक्त भारत के प्रकाशन जगत के लिए यह बिल्कुल नई घटना थी, लिहाजा देश के किताब विक्रेता खामोश रहे. अब इसी तरह का करार भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की नई किताब–द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स का भी सामने आया है. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब के प्रकाशक ने एक बार फिर एक दूसरी बड़ी ऑनलाइन कंपनी अमेजन से करार किया. इस करार के मुताबिक किताब के जारी होने के इक्कीस दिनों तक यह सिर्फ़ अमेजन पर उपलब्ध होगी. मतलब यह है कि इक्कीस दिनों तक कोई पाठक प्रणब मुखर्जी की यह किताब एक्सक्लूसिव तौर पर इसी वेबसाइट से खरीद सकता था. उसके बाद यह देश भर के पुस्तक विक्रेताओं के पास पहुंचेगी. इसका नतीजा यह हुआ कि प्री–बुकिंग के दौर में ही महामहिम की यह किताब लोकप्रियता के लिहाज से चेतन भगत और सचिन तेंदुलकर की किताब के बाद तीसरे पायदान पर पहुंच गई.

प्री–बुकिंग के आंकड़ों को देखकर तो यही लग रहा था कि इससे पुस्तक विक्रेताओं को खासा नुक़सान हुआ होगा. यहां भी एक अलग तरह का तंत्र है. वेबसाइट ने प्रणब मुखर्जी की इस किताब की प्री–बुकिंग शुरू की. जैसे–जैसे किताब रिलीज होने की तारीख नज़दीक आने लगी, तो ऑनलाइन स्टोर ने इसके मूल्य में भी कमी करनी शुरू की. किताब पर छपे मूल्य 595 रुपये की बजाय प्री–बुकिंग में इसका मूल्य 446 रुपये रखा गया था. रिलीज वाले दिन इस किताब का मूल्य घटाकर 399 रुपये कर दिया गया. यह बिक्री का अपना गणित भी है और मुनाफ़े का अर्थशास्त्र भी. इस खेल का एक और पक्ष भी है, वह यह कि अमेजन पर एक ग्राहक प्रणब मुखर्जी की किताब की सिर्फ़ एक ही प्रति खरीद सकता था. अगर किसी को दो या उससे अधिक प्रतियां चाहिए, तो उसे उतने ही ग्राहक प्रोफाइल या एकाउंट बनाने होंगे. यह बाज़ार में थोक बिक्री के आसन्न ख़तरे के मद्देनज़र किया गया है. इसी तरह से मार्केटिंग के दांव चेतन की किताब की बिक्री के वक्त भी खेले गए. चेतन की किताब ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. प्रकाशन जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रणब मुखर्जी की किताब भी खूब बिक रही है. एक तो प्रणब मुखर्जी का लेखन, दूसरे किताब के केंद्र में इंदिरा गांधी. इन दोनों को मजबूती प्रदान करने के लिए जबरदस्त मार्केटिंग के तौर–तरीके.

प्री-बुकिंग के आंकड़ों को देखकर तो यही लग रहा था कि इससे पुस्तक विक्रेताओं को खासा नुक़सान हुआ होगा. यहां भी एक अलग तरह का तंत्र है. वेबसाइट ने प्रणब मुखर्जी की इस किताब की प्री-बुकिंग शुरू की. जैसे-जैसे किताब रिलीज होने की तारीख नज़दीक आने लगी, तो ऑनलाइन स्टोर ने इसके मूल्य में भी कमी करनी शुरू की.

अंग्रेजी में किताब बिक्री के इस नए चलन से एक सवाल भी उठा है. क्या दुकान पर जाकर किताब खरीदने वालों को अब कुछ खास किताबों के लिए इंतज़ार करना होगा या फिर उन्हें भी किताबों की दुकान से मुंह मोड़कर ऑनलाइन स्टोर की ओर जाना पड़ेगा. भारत में कम हो रही किताबों की दुकान के लिए बिक्री का यह नया अर्थशास्त्र एक गंभीर चुनौती है. वक्त बदला है, वक्त के साथ प्रकाशन जगत के कायदे–क़ानून भी बदल रहे हैं, लेकिन बदलाव की इस बयार में ऑनलाइन स्टोर्स की एक्सक्लूसिविटी किताबों की दुकान में पूंजी लगाने वालों को हतोत्साहित करने वाली है. इसे रोकने के लिए दिल्ली के मशहूर खान मार्केट में मौजूद एक बुक स्टोर और दिल्ली एवं अन्य महानगरों में बुक स्टोर की शृंखला के मालिकों ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. इन दोनों ने तो चेतन भगत और प्रणब मुखर्जी की किताबों के प्रकाशकों की अन्य किताबें उन्हें वापस भेजने का फ़ैसला लिया है. उनका कहना है कि यह पाठकों के साथ धोखधड़ी है. उनका एक तर्क यह भी है कि इस तरह से किताबों का कारोबार नहीं चलता है. अगर किसी भी प्रकाशक को ऑनलाइन बुक स्टोर पर जाना है, तो फिर उसे सारी किताबें वहीं बेचनी होंगी. यह नहीं हो सकता है कि चर्चित शख्सियतों एवं लेखकों की किताबें ऑनलाइन बेची जाएं और कम चर्चित एवं गंभीर किताबें दुकानों के माध्यम से बेची जाएं.

कुछ अन्य बुक स्टोर्स ने भी प्रकाशकों को पत्र लिखकर विरोध जताया है और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी है. चेतन भगत और प्रणब मुखर्जी की किताबों की मार्केटिंग के बरक्स अगर हम हिंदी प्रकाशन की दुनिया को देखें, तो हमारे हिंदी के प्रकाशक मित्र अभी इस स्तर पर बाज़ार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. बाज़ार के इस खेल को समझने और लागू करने की दिशा में अगर सोच भी रहे हों, तो मैदान में उतरने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं. हिंदी के प्रकाशकों का अभी इन ऑनलाइन बुक स्टोर से राफ्ता कायम नहीं हो सका है. हिंदी की कुछ गिनी–चुनी किताबें ही इन वेबसाइट्स के ऑनलाइन बुक स्टोर पर मौजूद हैं. उसमें भी कई बार लिंक क्लिक करने पर एरर ही आ जाता है, जिससे पाठकों को कोफ्त होती है. हिंदी के प्रकाशकों को बाज़ार के इस खेल में शामिल होना पड़ेगा. इसका एक फ़ायदा यह होगा कि हिंदी में लिखने वाले लेखकों की पहुंच ज़्यादा होगी और हिंदी की किताबों के संस्करणों की जो संख्या लगातार कम होती जा रही है, उसमें बढ़ोत्तरी होगी. बाज़ार के अपने ख़तरे भी हैं, लेकिन पाठकों तक पहुंचने के लिए इन ख़तरों का उठा लेना चाहिए.

हमारे देश में पुस्तक विक्रेताओं का अभाव है. इस कमी को पूरा करने के लिए भी क़दम उठाने होंगे. विशाल हिंदी पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि ऑनलाइन स्टोर के साथ–साथ हिंदी के प्रकाशक इस तरह की कोई योजना बनाएं, जिससे वे पाठकों तक पहुंच सकें. छोटे शहरों में तो फिर भी किताबें मिल जाती हैं, लेकिन बड़े शहरों और मेट्रो में किताबों की अनुपलब्धता पाठकों को खिन्न करती है. अभी हाल में साहित्य अकादमी ने दिल्ली मेट्रो के साथ स्टेशनों पर किताबों की दुकानें खोलने के लिए करार किया है, लेकिन दो मेट्रो स्टेशनों पर किताबों की दुकानों से काम नहीं चलने वाला है. साहित्य अकादमी को इस दिशा में और पहल करनी होगी, साथ ही भारत सरकार को इसमें सहयोग करना होगा. साहित्य अकादमी के माध्यम से अगर किताबों की दुकानें शुरू करने का प्रयोग सफल होता है, तो भारत सरकार को अकादमी को इस मद में बजट देना होगा. इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार एक नई पुस्तक नीति बनाए. पुस्तकों को लेकर सरकार का रुख नरम है. अभी जिस तरह से पुस्तकों के कारोबार को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है, वह संकेत उत्साहजनक है.

सरकार को राष्ट्रीय पुस्तक नीति बनाने से पहले इस पर राष्ट्रव्यापी बहस कराने की ज़रूरत है. इस व्यवसाय से जुड़े और इसे जानने वाले सारे पक्षों की बातें सुनकर, समझ कर नीति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन प्राथमिकता किताबों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर तय होनी चाहिए. हमारे देश में हर तरह की नीति बनती है, लेकिन किताबों को लेकर एक समग्र नीति के अभाव में आज़ादी के इतने सालों बाद भी पुस्तक संस्कृति का विकास नहीं हो पाया है. सरकार के अलावा ग़ैर–सरकारी संस्थाओं को भी पुस्तक संस्कृति विकसित करने की दिशा में कोशिश करनी होगी. सबकी सामूहिक कोशिशों से ही किताबों को लेकर नई पीढ़ी में ललक पैदा करनी होगी. अगर यह हो सकता है, तो फिर ऑनलाइन स्टोर पर एक्सक्लूसिव किताबें बेचने की मार्केटिंग के तरीकों पर रोक भी लग सकती है और मुनाफ़े का समावेशी वितरण हो सकेगा. दूसरा फ़ायदा हिंदी के लेखकों को भी होगा और उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी. अब तक बाज़ार से भागने वाले लेखकों को बाज़ार के तौर–तरीके अपनाने ही होंगे. अगर ऐसा हो पाता है, तो यह पुस्तक प्रकाशन कारोबार के लिए अच्छे दिन लेकर आएगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

लघु कहानियां

पसीने की क़ीमत

शहालपुर में नारायण नामक एक अमीर साहूकार रहता था. उसके एक बेटा और एक बेटी थी. लड़की की शादी हुए तीन साल हो गए थे और वह अपने ससुराल में खुश थी. लड़का राजू वैसे तो बुद्धू नहीं था, लेकिन ग़लत संगत में बिगड़–सा गया था. उसे यह घमंड हो गया था कि उसके पिता के पास बहुत पैसा है. उसे दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना–फिरना ही अच्छा लगता था. जैसे–जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी पैसा खर्च करने की आदत बढ़ती गई और वह अपने दोस्तों के कहने पर पानी की तरह पैसा बहाने लगा.

मेहनत की कमाई बेटा इस तरह गंवा रहा है, यह देखकर नारायण को चिंता होने लगी. उसकी इच्छा थी कि राजू बेटा बड़ा होकर सारा कारोबार संभाल ले और वह अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाए. बेटे को समझ आने की आस लगाए बैठा नारायण बुढ़ापे की तरफ़ बढ़ रहा था. फिर उसने गांव के ही एक विद्वान गृहस्थ से सलाह लेने की सोची. दोनों ने मिलकर सलाह–मशविरा किया, खूब बातें हुईं.

दूसरे दिन नारायण ने राजू को बुलाया और कहा, बेटा राजू, घर से बाहर जाकर शाम होने तक कुछ भी कमाई करके लाओगे, तभी रात का खाना मिलेगा. राजू डर गया और रोने लगा. उसे रोता देखकर मां की ममता आड़े आ गई. मां ने राजू को एक रुपया निकाल कर दे दिया. शाम को जब नारायण ने राजू से पूछा, तो उसने वह एक रुपया दिखाया. पिता ने वह रुपया राजू से कुएं में फेंकने के लिए कहा. राजू ने बिना हिचकिचाहट वह रुपया फेंक दिया. अब नारायण को अपनी पत्नी पर शक हुआ. उसने पत्नी को उसके भाई के यहां भेज दिया.

दूसरे दिन राजू की वैसे ही परीक्षा ली गई. इस बार राजू मायके आई हुई अपनी बहन के सामने गिड़गिड़ाया. तरस खाकर उसकी बहन ने भी उसे पांच रुपये दे दिए. उस दिन भी पिता के कहने पर राजू ने पैसे कुएं में फेंक दिए. फिर से नारायण को लगा कि दाल में कुछ काला है. उसने अपनी बेटी को ससुराल वापस भेज दिया.

अब तीसरी बार राजू का इम्तिहान होना था. अब उसका साथ देने के लिए न मां थी, न बहन थी और न कोई दोस्त सामने आया. राजू सारा दिन सोचता रहा. मेहनत करके पैसे कमाने के अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा था. भूख भी लगने लगी थी. रात का खाना बिना कमाई के मिलने वाला था नहीं. राजू काम ढूंढने निकल पड़ा. पीठ पर बोझ उठाकर दो घंटे मेहनत करने के बाद उसे एक रुपया नसीब हुआ. भूख के मारे वह ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहा था. शरीर भी थक कर जवाब देने लग गया था. सो पसीने से भीगा हुआ राजू एक रुपया लेकर घर पहुंचा.

राजू को लग रहा था कि पिता को उसकी हालत पर तरस आएगा, लेकिन नारायण ने उससे सबसे पहले कमाई के बारे में पूछा. राजू ने अपना एक रुपया जेब से निकाला. पहले की भांति नारायण ने उससे वह एक रुपया कुएं में फेंकने के लिए कहा. अब राजू छटपटाया. उसने अपने पिता से कहा, आज मेरा कितना पसीना बहा है एक रुपया कमाने के लिए. इसे मैं नहीं फेंक सकता. जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे

अपनी ग़लती का एहसास हो गया. नारायण खुश हुआ, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी. अब राजू को पैसों की क़ीमत पता चल गई है, ऐसा सोचकर नारायण भी तीर्थ यात्रा की तैयारी में जुट गया. कहने का आशय यह कि मेहनत का मोल ऐसा होता है. पसीने की क़ीमत पसीना बहाकर ही पता चलती है और मेहनत से की गई कमाई ही खरी कमाई है.

–(0)–

शरारती बच्चे

दो भाई थे. एक की उम्र आठ साल थी और दूसरे की दस साल. दोनों बड़े शरारती थे. उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग था. माता–पिता रात–दिन इसी चिंता में डूबे रहते कि आज पता नहीं, वे दोनों क्या करें.

एक दिन गांव में एक साधु आया. लोगों का कहना था कि वह बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, जिसे आशीर्वाद दे दें, उसका कल्याण हो जाए. पड़ोसन ने बच्चों की मां को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को उन साधु के पास ले जाओ. शायद उनके आशीर्वाद से उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए. मां को पड़ोसन की बात ठीक लगी. पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ मत ले जाना, नहीं तो क्या पता, दोनों मिलकर वहीं कुछ शरारत कर दें और साधु महाराज नाराज़ हो जाएं.

अगले ही दिन मां छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास पहुंची. साधु ने बच्चे को

राजू को लग रहा था कि पिता को उसकी हालत पर तरस आएगा, लेकिन नारायण ने उससे सबसे पहले कमाई के बारे में पूछा. राजू ने अपना एक रुपया जेब से निकाला. पहले की भांति नारायण ने उससे वह एक रुपया कुएं में फेंकने के लिए कहा. अब राजू छटपटाया. उसने अपने पिता से कहा, आज मेरा कितना पसीना बहा है एक रुपया कमाने के लिए. इसे मैं नहीं फेंक सकता.

अपने सामने बैठा लिया और मां से बाहर जाकर इंतज़ार करने के लिए कहा.

साधु ने बच्चे से पूछा, बेटे, तुम भगवान को जानते हो न? बताओ, भगवान कहां है? बच्चा कुछ नहीं बोला. बस मुंह बाए साधु की ओर देखता रहा. साधु ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला. अब साधु को कुछ चिढ़–सी हो आई. उसने थोड़ी नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा, मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जवाब दो, भगवान कहां है?

बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया. बस मुंह बाए साधु की ओर हैरानी भरी नज़रों से देखता रहा. अचानक जैसे बच्चे की चेतना लौटी. वह उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा. साधु ने आवाज़ दी, पर वह रुका नहीं और सीधे घर जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे छिप गया. बड़ा भाई, जो घर पर ही था, ने उसे छिपते हुए देखा, तो पूछा, क्या हुआ, छिप क्यों रहे हो?

भैया, तुम भी जल्दी से कहीं छिप जाओ, बच्चे ने घबराए हुए स्वर में अपने बड़े भाई से कहा.

पर हुआ क्या? बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा.

अबकी बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. भगवान कहीं गुम हो गया है और लोग समझ रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ है! बच्चे ने मासूमियत के साथ जवाब दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

ओप्पो आर5 ऑक्टा–कोर क्वालकॉम एमएसएम 8939 स्नैपड्रैगन 615 चिपसेट से लैस है, जबकि इसमें 5.2 इंच का ओलेड स्क्रीन लगा है, जो 1080 गुणा 1920 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. फोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है. यह एंड्रॉयड 4.4.4 किकैट पर आधारित है. इसमें क्वॉड–कोर 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है और साथ ही इसमें 2जीबी रैम है. इसमें 16 जीबी की इंटरनल मेमोरी है. इस फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

इंटरनेट इस्तेमाल के लिए शॉर्टकट

श्याम सुन्दर प्रसाद

हम और आप प्रतिदिन कम्प्यूटर, इंटरनेट और ब्राउजर का प्रयोग करते हैं पर उससे जुड़ी कुछ छोटी–छोटी बातें हम नहीं जानते हैं या हमनें उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया. आइये जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में, जिसका प्रयोग कर हम अपने काम करने की गति को और भी तेज कर सकते हैं.

- अगर आप किसी ब्राउजर पर कोई काम कर रहे हों और गलती से वो टैब बंद हो जाये तो अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है आप केवल CTRL + Shift +T बटन को दवाएं और वह टैब वापस आ जाएगा. ब्राउजर कोई भी हो आप इसका प्रयोग कर एक से ज्यादा बार प्रेस करके एक से ज्यादा टैब को वापस ला सकते हैं.
- आप इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग कर रहे हैं और बिना माउस का प्रयोग कर एड्रेस बार में जाना चाहते हैं तो (F6 या ALT + D या CTRL +L) इनमें से किसी एक शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं. अगर आप ओपेरा ब्राउजर का प्रयोग कर रहे हैं तो आप F6 के जगह पर F8 की को दबाएं.
- आप ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और माउस का बिना इस्तेमाल किए एक टैब से दूसरे टैब में जाना चाहते हैं तो CTRL के साथ TAB बटन को दबाएं. इस प्रकार आप एक टैब से दूसरे टैब में जा सकते हैं.
- आप अपने कम्प्यूटर की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं वो भी बिना माउस का इस्तेमाल किये तो आप विंडो बटन और PAUSE बटन को एक साथ दबाएं और डायरेक्ट प्रॉपर्टीज देखें.
- आप सभी सामान्यतः कंटेंट को कॉपी करने के लिए CTRL+C बटन और पेस्ट करने के लिए CTRL+V बटन का प्रयोग करते हैं. इसके अलावा आप कॉपी करने के लिए CTRL+ INSERT बटन और पेस्ट करने के लिए SHIFT+INSERT बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- आपने बहुत सारे फाइल्स फोल्डर्स या प्रोग्राम्स खोल कर रखा है और आप बिना माउस इस्तेमाल किए एक फोल्डर्स, फाइल्स या प्रोग्राम्स से दूसरे में जाना चाहते हैं तो ALT के साथ TAB बटन दबाएं और टास्क बार में खुले प्रोग्राम्स के बीच स्विच करते रहिये.
- आप किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को माउस इस्तेमाल किए बिना बैक और फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ALT बटन के साथ लेफ्ट या राइट की को दबाएं. जैसे आप किसी बैक लिंक पर जाना चाहते हैं तो ALT के साथ लेफ्ट ऐरो की और फॉरवर्ड में जाना चाहते हैं तो ALT के साथ राइट की को दबाएं.
- आप ब्राउजर में किसी पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके फॉन्ट्स को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा करना है तो आप ALT बटन को दबाकर रखें और अपने माउस के व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएं जिससे फॉन्ट्स बड़ा होगा और व्हील्स को नीचे के तरफ करने से फॉन्ट्स छोटा होगा. इसलिए आप अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हैं.
- आइए हम जानते हैं गूगल के कुछ ट्रिक्स जिसके प्रयोग से हम अपने सर्च को और आसान बना सकते हैं. अगर आप दिल्ली में हैं और आप यहां किसी जगह, किसी मेडिकल स्टोर या रेस्टूरेंट को सर्च कर रहें हैं तो आप सीधा गूगल में लिखते हैं. आप जिस लोकेशन पर हैं वहां का नजदीकी पता जानने के लिए आप पहले अपने जीमेल के किसी अकाउंट में लॉगिन करें और फिर Google Local Serach टाइप करें उसके बाद अपना करंट लोकेशन सेलेक्ट कीजिये और फिर अपनी जरुरत के हिसाब से किसी भी मेडिकल स्टोर, रेस्टूरेंट को सर्च खोंजे इससे आपके आस–पास का ही रिजल्ट्स आएगा.
- आप किसी एक जगह के मौसम का तापमान जानना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च में टाइप करें weather और शहर का नाम जैसे आपको नोएडा के मौसम का हाल जानना है तो टाइप करें weather noida और एंटर कर दें. इस प्रकार आपको नोएडा के मौसम और तापमान की जानकारी प्राप्त हो जाएगी.
- आपको गूगल में किसी एक विशेष प्रकार के फाइल फॉर्मेट में ही सर्च रिजल्ट चाहिए तो आप दो कोट के अंदर सर्च कीवर्ड और फाइल टाइप लिखकर कोलन देकर फाइल फॉर्मेट लिख कर एंटर करें और सर्च रिजल्ट में उसी फाइल फॉर्मेट के टाइप का रिजल्ट आएगा. जैसे आपको Resume format केवल वर्ड फॉर्मेट में सर्च करना है तो गूगल सर्च में "resume format"fileType:doc लिख कर एंटर करें प्राप्त रिजल्ट केवल डॉक्यूमेंट फाइल का ही आएगा.
- आप गूगल सर्च बॉक्स को कैलकुलेटर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं. अगर आपको कोई आंकड़ा हल करना है तो आप वो सारे प्रश्न (आंकड़ा) को सर्च बॉक्स में लिख दें और एंटर कर दें उत्तर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा. उदहारण के तौर पर आपको 500+200/2–250 को सॉल्व करना है तो इसको सर्च बॉक्स में लिख कर एंटर कर दें. इसका उत्तर 300 आपके स्क्रीन पर होगा.
- अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में, उसके ग्राफ या उससे सम्बंधित लिंक्स की जानकारी चाहते हैं तो आप केवल उस कंपनी का नाम गूगल सर्च बॉक्स में लिख कर एंटर करे और सारी जानकारी खुद व खुद आपको प्राप्त हो जाएगी. अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक या ग्राफ के बारे में जानना है तो गूगल सर्च में msft लिखकर एंटर करें सारी जानकारी दांई तरफ खुद आ जायेगी.
- अगर आप यह सोच रहे हैं की कौन से वेब लिंक पर जाएं और कौन से लिंक पर नहीं. किसी लिंक के साथ कोई वायरस या कोई गलत प्रोग्राम न हो जिसको खोलते ही आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान पहुंचे तो आप अपने ब्राउजर में एक फ्री ऐड ऑन्स WOT(web of trust) इनस्टॉल कर केवल सेफ साइट्स पर विजिट कर सकते हैं, इसको इनस्टॉल करते ही ये बहुत सारे इन्फेक्टेड लिंक्स को खुलने नहीं देगा या आपको कई सारी चेतवानी देगा. इस ऐड ऑन्स को इसके ऑफिशियल साइट https://www.mywot.com/ से डाउनलोड कर सकते हैं.
- एक अक्षर को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और अगर चार या छह अक्षर से बना एक शब्द है तो उसको मिटाने के लिए आप चार से छः बार डिलीट बटन प्रेस करते हैं उसके जगह पर आप एक पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए CTRL+ Backspace बटन का प्रयोग कर एक बार में ही शब्द को डिलीट कर सकते हैं.

आप इन शॉर्टकट का इस्तेमाल कर अपने मुल्यवान समय का बचत कर सकते हैं. अब आशा हैं कि आप कम्प्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग करते समय इन शॉर्टकट का प्रयोग करके अपनी कार्य की गति में भी बृद्धि कर सकते हैं. ■

smart7973@gmail.com

इतालवी बाइक धूम मचाने को तैयार

इटली की जानी–मानी सुपरबाइक कंपनी बेनेल्ली भारत में डीएसके मोटोव्हील्स के साथ अपनी बाइक लॉन्च करेगी. कंपनी ने कहा है कि वह भारतीय बाजार में 300सीसी–1130सीसी पावर इंजन की मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी. इतालवी बाइक कंपनी बेनेल्ली भारत में टीएनटी 302, टीएनटी 600 जीटी, टीएनटी 600आई, टीएनटी 899 और टीएनटी 1130 आर के साथ अब अपनी टीएनटी 250 और कीवे ब्लैकस्टर भी लॉन्च करेगी. बीएन 250(बेनेल्ली 250टीएनटी) कंपनी की एंट्री लेवल बाइक है. ये 250सीसी, लिक्विड कूल्ड, सिंगल इंजन के साथ 24.2 बीएचपी पावर और 21एनएम टॉर्क जेनरेट करती है. कीवे ब्लैकस्टर कंपनी की एंट्री लेवल क्रूजर बाइक है. ये 250सीसी, लिक्विड कूल्ड वी–ट्विन इंजन के साथ 19बीएचपी पावर और 18.7एनएम टॉर्क जेनरेट करती है. बीएन 302 कंपनी की एंट्री लेवल बाइक है. ये 300सीसी, लिक्विड कूल्ड, पैरलेल–ट्विन इंजन के साथ 37बीएचपी पावर और 27एनएम टॉर्क जेनरेट करती है. बीएन 302 के बाद बीएन 600आई बाइक आती है. ये 600सीसी, लिक्विड कूल्ड, इनलाइन–फोर इंजन के साथ 82बीएचपी पॉवर और 52एनएम टॉर्क जेनरेट करती है. बीएन 600जीटी कंपनी की टूरयर बाइक है. इसके स्पेसिफिकेशन बीएन 600आई जैसे ही है लेकिन इसका बॉडी स्टाइल काफी अलग है. बीएन 899 नेक्ड स्पोर्ट बाइक है. ये 899सीसी, लिक्वि ड कूल्ड, बैलेंसर शाफ्ट सहित इनलाइन–थ्री इंजन के साथ 121बीएचपी पावर और 88एनएम टॉर्क जेनरेट करती है. टीएनटी 1130आर कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल है. ये 1031सीसी, लिक्विड कूल्ड, बैलेंसर शाफ्ट सहित इनलाइन–थ्री इंजन के साथ 158बीएचपी पावर और 120एनएम टॉर्क जेनरेट करती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

एलजी का दमदार बैटरी के साथ बड़े कैमरे वाला फोन

एलजी बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए एक दमदार स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है. यह फोन सभी नए फीचर से लैस होगा. बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन जी सीरीज के तहत बनाया गया है. इसमें बड़ी कंपनियों के फोन के तमाम फीचर होंगे. इसका नाम संभवतः जी4 होगा और यह फोन स्टायलस भी होगा जिससे फोन के स्क्रीन पर कमांड देने से लेकर मैसेज लिखने तक का काम किया जा सकेगा. इसका स्क्रीन क्यूएचडी डिस्पले वाला होगा. यह स्नैपड्रैगन 810 64 बिट प्रोसेसर से लैस होगा और इसका रैम 4जीबी का होगा. कहा जा रहा है कि इसका कैमरा 20.7 एमपी का होगा और इसकी बैटरी 3500 एमएएच की है. यानी कैमरा और बैटरी दोनों ही दमदार होंगे. ■

इसका नाम संभवतः जी4 होगा और इसमें स्टायलस भी होगा जिससे फोन के स्क्रीन पर कमांड देने से लेकर मेसेज लिखने तक का काम किया जा सकेगा. इसका स्क्रीन क्यूएचडी डिस्पले वाला होगा. यह स्नैपड्रैगन 810 64 बिट प्रोसेसर से लैस होगा और इसका रैम 4जीबी का होगा.

आईबॉल का ऑक्टा–कोर टैबलट

आईबॉल ने अपने पहले ऑक्टा–कोर टैबलट, स्लाइड ऑक्टा ए41 को ऑफिशयली लॉन्च कर दिया है. इस महीने की शुरुआत में कंपनी की वेबसाइट पर यह टैबलट लिस्ट कर दिया गया था. आईबॉल स्लाइड ऑक्टा ए41 टैबलट ऐंड्रॉयड 4.4 किटकैट पर चलता है. इसमें 7 इंच का आईपीएस फुल एचडी डिस्प्ले, 1.7 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा–कोर आरएम2 कॉर्टेक्स–ए7 प्रोसेसर, 2जीबी रैम, 16जीबी इंटरनल मेमरी, 32जीबी माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट जैसे फीचर्स उपलब्ध है. इस टैबलट में एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है. साथ ही इसमें 3500 एमएएच की बैटरी है. इस टैबलट में बिल्ट–इन इयर पीस है जिससे फोन कॉल्स के लिए इयरफोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसकी कीमत 14,999 रुपये रखी गई है. ■

ओप्पो 4जी स्मार्टफोन आर5 लॉन्च

चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने 4जी स्मार्टफोन आर5 लॉन्च किया है. कंपनी ने कहा है कि इस फोन को तैयार करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. यह दुनिया का सबसे पतला फोन होने के बावजूद यूजर के हाथों में बिल्कुल फिट बैठता है. इस फोन की चौड़ाई 4.85 एमएम है, जबकि इसका वजन 155 ग्राम है. ओप्पो आर5 ऑक्टा–कोर क्वालकॉम एमएसएम 8939 स्नैपड्रैगन 615 चिपसेट से लैस है, जबकि इसमें 5.2 इंच का ओलेड स्क्रीन लगा है, जो 1080 गुणा 1920 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. फोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है. यह एंड्रॉयड 4.4.4 किकैट पर आधारित है. इसमें क्वॉड–कोर 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है और साथ ही इसमें 2जीबी रैम है. इसमें 16 जीबी की इंटरनल मेमोरी है. इस फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसकी कीमत 29,990 रुपये रखी है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

धोनी का टेस्ट ख़त्म

कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ दिनों पहले ही अंतरराट्रीय क्रिकेट में एक दशक पूरे किए . उस दौरान किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि धोनी अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे. धोनी पहले भी कई बार क्रिकेट के एक फॉर्मेट को छोड़ने की बात कहते रहे हैं. इसलिए कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि वह विश्वकप के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे. धोनी की कप्तानी के दौरान भारतीय टीम घर में शेर बनी रही और विदेश में ढेर होती रही. इसी वजह से बतौर टेस्ट कप्तान उनकी आलोचना होती रही. इस वजह से उनके ऊपर टेस्ट कप्तानी छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था.

नवीन चौहान

अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने-जाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक से टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर सबको चौंका दिया. ऑस्ट्रेलिया दौरे में मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग-डे टेस्ट के बेनतीजा समाप्त होने के बाद धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. करियर की आखिरी टेस्ट पारी में धोनी 24 रन पर नाबाद रहे. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके संन्यास की घोषणा बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी करके की. धोनी ने अपने संन्यास के बारे में न ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन कुछ कहा और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ज़िक्र किया. धोनी ने यह बात सबसे पहले बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल को बताई. उन्होंने साथी खिलाड़ियों को सूचित करने तक पटेल को उनके संन्यास की आधिकारिक घोषणा करने से मना किया था. धोनी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलने के दबाव को संन्यास का कारण बताया. टेस्ट से संन्यास लेने के बाद भी वह टीम इंडिया की एक दिवसीय और टी-20 टीम की कमान संभालते रहेंगे. इन दोनों फॉर्मेट का इन्हें विशेषज्ञ माना जाता है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 14 फरवरी से खेले जाने वाले विश्वकप में भी टीम इंडिया खिताब बचाने धोनी की कप्तानी में ही उतरेगी.

धोनी के इस तरह अचानक संन्यास लेने पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. इस पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का कहना है कि धोनी भले ही कप्तानी छोड़ देते लेकिन बतौर खिलाड़ी उन्हें फिलहाल टीम का हिस्सा बने रहना चाहिए था. गावस्कर को अंदाजा था कि वह टेस्ट सीरीज के बाद कप्तानी छोड़ देंगे. सवाल उनके सीरीज के बीच में संन्यास लेने के फैसले पर उठ रहे हैं. किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह सीरीज के बीच में ऐसा करेंगे. पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरापल्ली प्रसन्ना ने कहा कि धोनी को सीरीज के बाद यह निर्णय लेना चाहिए था. उन्होंने कहा कि धोवी भले ही पटौदी और गांगुली जैसे रचनात्मक कप्तान न रहे हों लेकिन उनमें कुछ अलग बात थी. उसी वजह से उनकी कप्तानी में टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंची. एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने ऑस्ट्रेलिया को कप्तानों की कब्रगाह बताते हुए लिखा कि धोनी ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद संन्यास लेने वाली लेटेस्ट खिलाड़ी हैं. इससे पहले एंड्रयू फ्लिंटॉफ, मो. युसुफ, महेला जयवर्धने और ग्रीह्म स्मिथ जैसे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद अपनी टीमों की कप्तानी छोड़ चुके हैं. लेकिन भारत के अधिकांश लोगों ने उनके फैसले का सम्मान करते हुए उन्हें एक अच्छे इंसान, संयमित और सफल कप्तान के रूप में याद किया है. साथ ही भारतीय क्रिकेट को अथाह उपलब्धियां देने के लिए धन्यवाद भी दिया है. एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में धोनी की टेस्ट टीम में कमी हर किसी को खलेगी. एक बेहतरीन विकेटकीपर-बल्लेबाज की तलाश जैसा जटिल काम चयनकर्ताओं के सामने अचानक से आ खड़ा है. कप्तानी तो विराट कोहली के हाथों में सौंप दी गई है लेकिन एक स्थाई विकेटकीपर-बल्लेबाज की खोज धोनी के टेस्ट पदार्पण से पहले की तरह एक बार फिर शुरू हो जाएगी. हालांकि रिद्दिमान साहा, दिनेश कार्तिक, संजू सैमसन और नमन ओझा को समय-समय पर चयनकर्ता इस जगह पर आजमाते रहेंगे.

धोनी ने टेस्ट करियर में 90 टेस्ट मैच खेले. वह सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय विकेटकीपर हैं. उन्होंने 90 टेस्ट मैचों की 144 पारियों में 38.09 की औसत से 4876 रन बनाये. टेस्ट करियर की आखिरी पारी में धोनी 24 रन पर नाबाद रहे. धोनी ने अपने टेस्ट करियर का दो तिहाई समय बतौर कप्तान गुजारा. धोनी ने 60 मैचों कप्तानी की जिसमें 27 मैचों में उन्हें जीत हासिल हुई. घरेलू धरती पर उन्होंने 30 मैचों में कप्तानी की जिसमें से 21 में जीत हासिल की, 3 में हार मिली और 6 मैच बेनतीजा रहे. जबकि विदेशी धरती पर खेले गए 30 मैचों में उन्हें 6 में जीत, 15 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 9 मुक़ाबले बराबरी पर छूटे. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 41 साल बाद न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुई. उनकी सरपरस्ती में टीम इंडिया 18 महीने तक विश्व की नंबर एक टेस्ट टीम रही. दिसंबर 2009 में नंबर एक पर पहुंची टीम इंडिया, 2011 में इंग्लैंड में 4-0 के अंतर से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पहले पायदान से बेदखल हुई. इसके बाद विदेशी धरती पर हार को न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ. वह आज तक बेदस्तूर जारी है. कुल मिलाकर धोनी की कप्तानी का रिकॉर्ड देखा जाये, तो वह संतोषजनक दिखाई पड़ता है. अपनी कप्तानी में धोनी विदेशी धरती पर(न्यूजीलैंड-वेस्टइंडीज के अलावा) भारतीय टीम को जीत नहीं दिला सके. उनका मैजिक टेस्ट मैचों में नहीं चल पाया. वह विदेशों में एक के बाद एक टेस्ट सीरीज हारते गए. उनके बारे में कहा जाता है कि ही वाज कैप्टन विथ लेस कंट्रोवर्सी एंड मोर प्रफॉर्मेंस. (वह कम विवादों और ज्यादा प्रदर्शन वाले कप्तान थे). क्रिकेट के सबसे पुराने और सबसे बड़े फॉर्मेट में वह अपनी कप्तानी का करिश्मा बरकरार नहीं रख पाये. धोनी ने बतौर टेस्ट कप्तान 2011 से लेकर अब तक, यानी कि पिछले तीन सालों में जितने टेस्ट हारे उतने टेस्ट मैच अन्य भारतीय कप्तान अपने पूरे करियर में नहीं हारा.

बतौर टेस्ट बल्लेबाज भी उनका प्रदर्शन औसत ही रहा. वह अपने टेस्ट करियर में एक भी शतक एशिया के बाहर नहीं लगा सके. एशिया के बाहर उनका उच्चतम स्कोर 90 रहा जो उन्होंने इसी साल इंग्लैंड दौरे पर लॉर्डस टेस्ट में बनाया था. लॉर्डस में भारत 21 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल हुआ था. वह टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान भी हैं. एक बल्लेबाज के तौर पर धोनी ने 42 घरेलू मैचों में 45.76 की औसत से 2380 रन बनाए, जबकि विदेशी धरती पर खेले गए 48 टेस्ट मैचों में 32.84 की औसत से 2496 रन बनाए. धोनी ने घरेलू धरती पर 5 शतक और 15 अर्धशतक जमाए जबकि विदेशी धरती पर केवल एक शतक और 18 अर्धशतक लगाए, विदेशी सरजमीं के नाम पर उन्होंने एक शतक पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में लगाया था.

टीम इंडिया ने मेलबर्न टेस्ट मैच तक 486 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें से केवल 122 मैचों में भारत को जीत हासिल हुई है. इनमें से 26 में धोनी की कप्तानी में जीत हासिल हुई है. जो किसी भी दूसरे भारतीय कप्तान से ज्यादा है. गांगुली ने टीम इंडिया को 21 टेस्ट में जीत दिलवाई. विदेशी धरती पर भारत ने अब तक कुल 37 टेस्ट मैच जीते हैं जिनमें से 6 जीत धोनी की कप्तानी में हासिल हुई है. गांगुली अभी भी विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा(11 टेस्ट) जीत दर्ज करने में कामयाब हुए. धोनी टेस्ट मैचों मे सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के लिहाज से नंबर वन भारतीय कप्तान हैं. टेस्ट मैचों में जीत की फेहरिस्त में सौरव गांगुली(21 टेस्ट), मो. अजहरुद्दीन(14 टेस्ट) , सुनील गावस्कर और नवाब पटौदी(9 टेस्ट) से कहीं आगे हैं. धोनी ने अपनी कप्तानी में 45 प्रतिशत मैचों में जीत दर्ज की, जबकि गांगुली 43 प्रतिशत मैचों में जीत दर्ज कर सके.

साल 2014 में धोनी का टेस्ट औसत केवल 33 रहा साथ ही उनकी विकेटकीपिंग में भी चपलता नज़र नहीं आ रही थी. दूर के कैचों के लिए हवा में छलांग लगाने से वह बचते दिखाई पड़ते हैं. साल 2011 के बाद धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 23 टेस्ट मैच खेले जिसमें से केवल 2 में जीत हासिल हुई, 6 ड्रा रहे और 15 में हार का सामना करना पड़ा. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टी-20 और एकदिवसीय मैचों में सफलता की नई इबारत लिखी है. क्रिकेट के छोटे प्रारूपों में उनका मास्टर क्लास नज़र आता है लेकिन टेस्ट मैचों में ऐसा नहीं हो पाता है. धोनी की कप्तानी में हम टेस्ट क्रिकेट में पीछे चले गये हैं. विदेशी धरती पर जीत के मामले में धोनी फिसड्डी साबित हुए. यही धोनी के एक दशक लंबे क्रिकेट करियर में एक दाग है. बतौर कप्तान धोनी को केवल यहीं पर कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और उनकी कप्तानी की क्षमता पर सवाल उठाए जा सकते हैं. धोनी ने टीम को नंबर एक बनाने से कप्तानी की शुरूआत की थी लेकिन जब वे रिटायर हुए हैं टीम इंडिया आईसीसी रैंकिंग में छठवें पायदान पर पहुंच गई है.

टेस्ट कप्तानी संयोगवश धोनी के हाथों में आ गई थी. धोनी ने पहली बार टीम इंडिया की कमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2008 में कानपुर टेस्ट में संभाली थी. उस टेस्ट से पहले कप्तान अनिल कुंबले घायल हो गए थे वह उपकप्तान थे इस वजह से उन्हें टेस्ट में कप्तानी का मौका मिल गया. टेस्ट कप्तानी के पहला टेस्ट में भी धोनी पास हो गए थे. उस मैच को टीम इंडिया ने तीन दिनों में जीत लिया था. इसके बाद अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई घरेलू सीरीज के दिल्ली टेस्ट के बाद कुंबले ने धोनी की तरह अचानक सीरीज के बीच में संन्यास की घोषणा कर दी. टीम के उप-कप्तान धोनी के हाथों में टीम की कमान सौंप दी गई. इसके पहले धोनी टी-20 और एकदिवसीय टीम की कमान सफलता पूर्वक संभाल चुके थे. धोनी की बल्लेबाजी तकनीक उन्हें एक टेस्ट खिलाड़ी नहीं बनाती थी, लेकिन उनकी सधी हुई विकेटकीपिंग और छोटे फॉर्मेटों में मिली सफलता की रहने की वजह से टेस्ट का नियमित कप्तान बना दिया गया. हालांकि उस वक्त वीरेंद्र सहवाग को कप्तान बनाने की बात हुई थी, लेकिन अंततः चयनकर्ताओं ने धोनी पर भरोसा जताया. इसके बाद धोनी की कप्तानी में देखते ही देखते टीम इंडिया दिसंबर 2009 में आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक पायदान पर पहुंच गई और साल 2011 तक वहां काबिज रही. विश्वविजेता बनने के बाद साल 2011 के इंग्लैंड दौरे में 4-0 की करारी हार के बाद धोनी की टेस्ट कप्तानी का असली टेस्ट शुरू हुआ. लेकिन धोनी उस टेस्ट में कभी पास नहीं हो सके. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम का 4-0 से सूपड़ा साफ हो गया. धोनी की टेस्ट कप्तानी को लेकर उंगलियां उठने लगी. इसके बाद विदेशी धरती पर हार का सिलसिला चलता रहा. इस बार भी मेलबर्न में भी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के हाथ से फिसल जाने के बाद ही धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की. धोनी विश्व में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने और जीत हासिल वालों की सूची में सातवें स्थान पर हैं. करियर के आखिरी टेस्ट मैच में वह बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं. उन्होंने सुनील गावस्कर के 47 मैचों में बनाए 3449 रनों के रिकॉर्ड को तोड़कर, 60 मैचों में 3454 रन बना कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इसी मैच के दौरान ही वह बतौर कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने. एक विकेटकीपर के तौर पर धोनी ने 256 कैच लपके और 38 खिलाड़ियों को स्टंपिंग कर आउट किया. विकेट के पीछे कुल 294 शिकार के साथ धोनी टेस्ट इतिहास के पांचवें सबसे सफल विकेटकीपर हैं.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और टीम इंडिया के कोच ग्रेग चैपल ने एक बार धोनी के बारे में कहा था कि मैं दुनिया भर के जितने युवा खिलाड़ियों से मिला हूं धोनी उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं. लेकिन यह वक्त ही बताएगा. महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही मजबूत व्यक्ति है और मैं आशा करता हूं कि वह इस वजह से टीम में बना रहेगा क्योंकि लोग इसे पसंद करते हैं इसलिए जरुरी है कि उसके जैसा कोई व्यक्ति टीम की कमान संभाले और टीम का नेतृत्व करे. वह केवल भारतीय क्रिकेट के लिए नहीं बल्की विश्व क्रिकेट के लिए एक धरोहर है. धोनी और गांगुली दोनों ही आक्रामक कप्तानी के लिए जाने जाते हैं. दोनों ही जीतने के लिए खेलते थे लेकिन दोनों की शैली अलग-अलग थी. गांगुली की आक्रामकता मैदान में नज़र आ जाती थी लेकिन धोनी इस आक्रामकता को मैदान पर व्यक्त नहीं होने देते थे. धोनी ने एक कप्तान के तौर पर पहले 11 टेस्ट में अविजय रहे लेकिन अपने टेस्ट करियर का वह शानदार अंत नहीं कर सके.■

navinonline2013@gmail.com

धोनी टेस्ट करियर

मैच	पारी	रन
90	144	4876
शतक	अर्धशतक	
06	33	
औसत	उच्चतम स्कोर	
38.09	224	
कैच	स्टंपिंग	विकेट
256	38	01

धोनी की कप्तानी में विदेशी धरती पर हार

साल	विरुद्ध	रिजल्ट
2014	ऑस्ट्रेलिया	2-0
2014	इंग्लैंड	1-3
2014	न्यूजीलैंड	0-1
2013	दक्षिण अफ्रीका	0-1
2011-12	ऑस्ट्रेलिया	0-4
2011	इंग्लैंड	0-4

साल-2014 में अभिनेताओं से आगे रहीं अभिनेत्रियां

प्रियंका

बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि साल 2014 अभिनेत्रियों के नाम रहा है. इस साल बॉलीवुड में अभिनेत्रियां अभिनेताओं से आगे रही हैं. इस साल प्रियंका की गुंडे और मेरीकॉम जैसी दो सुपरहिट फिल्में रिलीज हुईं.

प्रियंका ने कहा कि इस साल होनेवाले पुरस्कार समारोहों में अभिनेताओं के बीच कड़ी टक्कर नहीं है. असली टक्कर तो अभिनेत्रियों के बीच है. इसके अलावा प्रियंका ने कहा कि फिल्मों में उम्र का 40वां और 50वां पड़ाव पार कर चुके अभिनेताओं को अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करते हुए दर्शक बखूबी स्वीकार कर लेते हैं. लेकिन उम्रदराज अभिनेत्रियों से उन्हें परेशानी क्यों है?

उन्होंने कहा कि हमें ऐसी फिल्में स्वीकार करनी होंगी जिसमें 30 या 40 वर्ष से ज्यादा उम्र की अभिनेत्रियां भी रोमांस कर सकें. साथ ही शादीशुदा अभिनेत्रियों को भी फिल्म जगत को स्वीकार करना होगा. उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा अभिनेत्रियों को भी बदलते समय के हिसाब से अपने रोल चुनने चाहिए, जैसे कि डर्टी पिक्चर में विद्या बालन, क्वीन में कंगना रानावत, बर्फी में मैंने और चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया है. ऐसा करके ही अभिनेत्रियां बॉलीवुड में अपने लिए नया मुकाम बना सकेंगी.■

हमें ऐसी फिल्में स्वीकार करनी होंगी जिसमें 30 या 40 वर्ष से ज्यादा उम्र की अभिनेत्रियां भी रोमांस कर सकें. साथ ही शादीशुदा अभिनेत्रियों को भी फिल्म जगत को स्वीकार करना होगा.

कैटरीना का हाथ मांगने लंदन जाएंगे रणबीर!

रणबीर कैटरीना की मां से मिलने वाले हैं और शादी के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगने वाले हैं. गौरतलब है कि कैट का परिवार लंदन में रहता है.

बॉलीवुड के रॉकस्टार रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ बहुत जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं. दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं. इस बात से सभी वाकिफ हैं कि रणबीर हाल ही में कैटरीना के साथ बांद्रा के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं. अब खबर यह है कि दोनों ही इस रिश्ते को जल्दी ही एक नया नाम देना चाहते हैं. इसके लिए रणबीर कैटरीना की मां से मिलने वाले हैं और शादी के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगने वाले हैं. गौरतलब है कि कैट का परिवार लंदन में रहता है. कैट क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहले ही लंदन पहुंच चुकी हैं. जल्दी ही रणवीर भी लंदन जाने वाले हैं. हो सकता है नए साल में बॉलीवुड के ये स्टार शादी के बंधन में बंध जायें.■

दर्शकों को सुलताना डाकू से मिलवाएंगे तिग्मांशु

चंबल के जाने-माने डकैत के जीवन पर पान सिंह तोमर जैसी फिल्म बनाने वाले निर्देशक तिग्मांशु धूलिया बहुत ही जल्द एक और डाकू की जिंदगी लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं. यह फिल्म सुलताना डाकू के जीवन पर आधारित है. तिग्मांशु ने इस पिल्म के बारे में बताया कि यह फिल्म इंडियाना जोंस की तर्ज पर होगी. उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म बच्चों के लिए होगी और यह डॉ. हेनरी इंडियाना जोंस के साहस पर आधारित अमेरिकी पापुलर इंटरटेनमेंट फ्रैंचाइजी का भारतीय रूप होगी. दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव के दौरान तिग्मांशु ने बताया कि सुलताना डाकू फिलहाल पटकथा लेखन के चरण में है. यह फिल्म एक्शन रोमांच से भरपूर होगी और बच्चों को पसंद आएगी. यह फिल्म थोड़ी बहुत रॉबिनहुड की कहानी से मेल खाती है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

तुषार की नज़र में सनी लियोनी नंबर वन एक्ट्रेस

सनी लियोनी ने गूगल की सर्च लिस्ट में भारत के सभी सिलेब्रिटीस को पीछे छोड़ते हुए नंबर एक की पोजिशन हासिल की है. लेकिन तुषार कपूर की नज़र में सनी बॉलीवुड की टॉप ऐक्ट्रेस भी बन गई हैं. तुषार का कहना है कि सनी एक बेहतरीन ऐक्टर हैं. दरअसल सनी की तारीफों के पुल बांध रहे

तुषार आने वाली फिल्म मस्तीजादे में सनी के साथ काम कर रहे हैं. इस बारे में तुषार ने कहा कि सनी के साथ काम करने का उनका अनुभव शानदार रहा. वह बेहतरीन अभिनेत्री हैं साथ ही वह अच्छी इंसान भी हैं.

तुषार आने वाली फिल्म मस्तीजादे में सनी के साथ काम कर रहे हैं. इस बारे में तुषार ने कहा कि सनी के साथ काम करने का उनका अनुभव शानदार रहा. वह बेहतरीन अभिनेत्री हैं साथ ही वह अच्छी इंसान भी हैं. वह बॉलीवुड की नंबर वन अभिनेत्री हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी फिल्म मस्तीजादे सफल होगी. मस्तीजादे में सनी जो रोल निभा रही हैं उस किरदार का नाम लैला लिली है. इस रोल से सनी अपनी ऐक्टिंग का लोहा किस हद तक मनावा पाती हैं यह तो वक्त ही बतायेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

लिव-इन रिलेशन में हूं कंगना

तनु वेड्स मनु,फैशन और क्वीन जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपने को स्थापित करने वाली एक्ट्रेस कंगना रानावत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वह लिव-इन रिलेशन में रह रही हैं और अपने नये रिश्ते को काफी एंजॉय कर रही हैं. जब पत्रकारों ने उनसे उनके पार्टनर के बारे में पूछा तो कंगना ने कहा कि अभी इसका खुलासा करने का सही वक्त नहीं आया है. कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कंगना और रितिक रोशन डेटिंग कर रहे हैं. लेकिन अब जब कंगना ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वह रिलेशनशिप में हैं तो उनके और रितिक की डेटिंग की खबरों को एक बार फिर से हवा मिल गई है. कंगना के साथ डेटिंग की खबरें सामने आने के बाद रितिक रोशन ने ट्विट करके कहा था कि यह एक बेवकूफी भरी बात है और उन्हें इस बात पर गुस्सा भी नहीं आ रहा. इसके साथ ही रितिक ने मीडिया को ऐसी गैर-जिम्मेदाराना खबरों से बचने की सलाह दी थी. रिलेशनशिप की खबरों से इतर कंगना बॉलिवुड के सीरियल किसर इमरान हाशमी के साथ कट्टी-बट्टी नाम की फिल्म में काम करने जा रही हैं. इससे पहले दोनों गैंगेस्टर जैसी फिल्म में साथ काम कर चुके हैं.■

कंगना के साथ डेटिंग की खबरें सामने आने के बाद रितिक रोशन ने ट्विट करके कहा था कि यह एक बेवकूफी भरी बात है और उन्हें इस बात पर गुस्सा भी नहीं आ रहा. इसके साथ ही रितिक ने मीडिया को ऐसी गैर-जिम्मेदाराना खबरों से बचने की सलाह दी थी.

हॉलीवुड से

कैंपेन के लिए टॉपलैस हुईं माईली सायरस

हॉलीवुड सिंगर माइली सायरस ने एक सोशल कैंपेन फ्री द निप्पल्स के लिए अपनी टॉपलेस पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. गौरतलब है कि इस कैंपेन के जरिए इस धारणा का विरोध किया जा रहा है कि पुरुष बिना शर्ट पहने कहीं भी जा सकते हैं लेकिन महिलाओं को अपने आपको ढंक कर रखना पड़ता है. इस कैंपेन को चलाने वालों का कहना है कि वह महिलाओं के पब्लिक प्लेसेस पर टॉपलेस होकर जाने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं. गौरतलब है कि इस कैंपेन को अब तक माइली सायरस के साथ-साथ स्कॉउट विलिस और चेलसा हेंडलर का भी समर्थन मिल चुका है. हालांकि माइली सायरस की टॉपलैस पिक्चर इस समय उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट हो चुकी है. लेकिन माइली सायरस ने इस कैंपेन पर बनी फिल्म का लिंक शेयर किया है. इस लिंक के साथ माइली ने कहा कि यह फिल्म असली घटनाओं से प्रेरित है और उन लड़कियों की कहानी बताती है जिन्होंने न्यूयॉर्क की सड़कों पर टॉपलैस होकर चलने की हिम्मत दिखाई.■

चौथी दुनिया

12 जनवरी–18 जनवरी 2015

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार-झारखंड

झारखंड में गैर आदिवासी सीएम मुद्दा

अपने गिरेबां में झांकें नीतीश

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

नीतीश कुमार ने आदिवासी को मुख्यमंत्री का पद न देने के भाजपा के फैसले को झारखंड के गठन की भावना के प्रतिकूल बताया था. उनका मानना था कि इससे वहां गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है और सरकार को आदिवासी समाज का विश्वास हासिल करने में परेशानी होगी. नीतीश की इस बात की प्रतिक्रिया भाजपा में होनी ही थी और हुई भी, कड़ी हुई. भाजपा ने दावा किया कि उसने झारखंड को दो-दो आदिवासी मुख्यमंत्री दिए. इन दोनों ने तीन सरकारें दीं. यह बयान-युद्ध निरंतर जारी है. लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि झारखंड के आदिवासी समाज में भाजपा के इस फैसले की क्या प्रतिक्रिया है? वहां के आदिवासी-मूलवासी संगठनों ने एक दिकू को मुख्यमंत्री बनाए जाने के विरोध में दो दिनों के झारखंड बंद का आह्वान किया था. हालांकि इस आह्वान के कारण प्रदेश में कहीं बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई. मसालेदार मीडिया रिपोर्ट नहीं तैयार हुई और राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कहीं कोई सफाई नहीं देनी पड़ी.

सुकान्त

शताब्दी की नई सुबह के कुछ दिन पहले तक बिहार के अविभाज्य हिस्से का नाम झारखंड था. दोनों के रिश्ते में इतनी जल्दी अलगाव या तात्विक बदलाव आएगा, यह सोचना गलत है. इस प्रक्रिया के पूरी होने में अभी वक्त लगेगा. लिहाज़ा बिहार के दुख का झारखंड पर असर और झारखंड के सुख से बिहार में खुशी सहज है. राजनीति के संदर्भ में तो यह उत्कट रूप से दिखता है और यदि राजनीति चुनावी हो तो कहना ही क्या! इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बिहार पर सबक की तो पड़ताल हो ही रही है, अब वहां के मुख्यमंत्री के लिए आदिवासी बनाम गैर आदिवासी के विवाद ने बिहारी रहनुमाओं को बयान-युद्ध का नया अवसर दे दिया है. बयान-बाण दोनों तरफ से चल रहे हैं. भाजपा-विरोधी अपने तरकश से नए-नए तीर निकाल रहे हैं. इसकी शुरुआत झारखंड में गैर आदिवासी-मूलवासी के बदले बाहरी (कहिए दिकू) रघुवर दास साहु को मुख्यमंत्री बनाए जाने के भाजपा के फैसले और उस पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया से हुई है. कहते हैं, झारखंड के गठन के अघोषित उद्देश्यों में आदिवासी समाज को आर्थिक विकास और राजनीतिक सत्ता की मुख्यधारा में लाना था. इसके लिए मुख्यमंत्री का पद उसी समाज से आए नेतृत्व को सौंपने की जरूरत समझी गई थी और ऐसा करने का तय किया गया था. नीतीश कुमार और तत्कालीन वाजपेयी सरकार के अन्य बिहारी मंत्री इस समझ की असलियत की गांठें खोल सकते हैं. बहरहाल, यह उद्देश्य कितना सफल हुआ, यह कहना कठिन है. पर इस अलिखित शर्त के विरोध में झारखंड के सभी रंग के गैर आदिवासी राजनेता वर्षों से एकमत-एकजुट थे. इस शर्त के दबाव से मुक्ति-अभियान को भाजपा के ही मोदी-शाह युग में सफलता मिली.

नीतीश कुमार ने आदिवासी को मुख्यमंत्री का पद न देने के भाजपा के फैसले को झारखंड के गठन की भावना के प्रतिकूल बताया था. उनका मानना था कि इससे वहां गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है और सरकार को आदिवासी समाज का विश्वास हासिल करने में परेशानी होगी. नीतीश की इस बात की प्रतिक्रिया भाजपा में होनी ही थी और हुई भी, कड़ी हुई. भाजपा ने दावा किया कि उसने झारखंड को दो-दो आदिवासी मुख्यमंत्री दिए. इन दोनों ने तीन सरकारें दीं. यह बयान-युद्ध निरंतर जारी है. लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि झारखंड के आदिवासी समाज में भाजपा के इस फैसले की क्या प्रतिक्रिया है? वहां के आदिवासी-मूलवासी संगठनों ने एक दिकू को मुख्यमंत्री बनाए जाने के विरोध में दो दिनों के झारखंड बंद का आह्वान किया था. हालांकि इस आह्वान के कारण प्रदेश में कहीं बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई. मसालेदार मीडिया रिपोर्ट नहीं तैयार हुई और राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कहीं कोई सफाई नहीं देनी पड़ी. यह भी सही है कि इस आह्वान का रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर जैसे शहरों कोई खास असर कहीं नहीं दिखा. पर खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला, खरसांवा सहित सुदूर क्षेत्रों में इस आह्वान का प्रभाव देखा गया था. इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों में पुलिस की परोक्ष दमनात्मक सक्रियता भी काबिल-ए-तारीफ थी. यह जानकारी इसलिए कि स्थानीय बनाम बाहरी (आदिवासी-मूलवासी बनाम दिकू) का मसला झारखंड की जमीनी राजनीति की एक सच्चाई है. भाजपा का उस दौर का राष्ट्रीय और झारखंडी नेतृत्व इस सच्चाई को शायद बेहतर और संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करता था. बहरहाल, यह व्यापक सवाल है कि झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी को ही बनाया जाना चाहिए या नहीं. किसी समुदाय के सशक्तिकरण और उसे मुख्यधारा में लाने की विशेष व्यवस्था के बदले क्षमता और प्रतिभा को किस हद तक तरजीह देना चाहिए. हालांकि वोट बटोरू राजनीति के तहत जो राज-नेता या बुद्धिजीवी किसी समुदाय को विशेष राजनीतिक प्रशासनिक सुविधा के लिए अति सक्रियता दिखाते हैं, झारखंड के मामले में वे भी इस या उस कारण से गैर आदिवासी के पक्ष में खुल कर खड़े हैं.

वस्तुतः सारा कुछ राजनीति में बढ़ते छद्म के कारण है. कोई राजनेता अपना टेटर नहीं देखता और अपने किसी काम के पक्ष में सामने के विरोधी किसी काम को खड़ा कर देता है. इसका सबसे बेहतर उदाहरण खबरिया चैनलों के बहस कार्यक्रमों में देखने में आता है. बहरहाल, इतना तो है ही कि पिछले आठ-दस साल, विशेषकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद, मेंनीतीश कुमार का दिल केवल बिहार के लिए ही धड़क रहा है. बिहार की अस्मिता की पहचान के लिए वह जिस व्याकुल-भाव से नालंदा और पटना को संवारने में लगे रहे हैं, उसी तरह बिहार के विकास के लिए उसे विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सदन से सड़क तक संघर्ष करते रहे हैं. वह बिहार को सम्मान और अधिकार दिलाने के हर उपाय में लगे रहे. लेकिन बिहार की प्रतिभाओं के साथ उन्होंने पूर्ण न्याय किया, यह कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है. बिहार में साहित्यकार-कलाकारों के सम्मान का काम पिछले कई वर्षों से ठप है. और तो और, इन सम्मानों के लिए जितनी कमेटियां बनी हैं, अधिकांश बिहार के बाहर के कथित बड़े लोगों की रही हैं या उन में बहुमत उन्हीं लोगों का रहा है. बिहार दिवस या शिक्षा दिवस के नाम पर जितने कार्यक्रम होते रहे हैं, उनमें बिहारी प्रतिभाओं की निरंतर घोर उपेक्षा होती रही है. बिहार की कुछ भाषाओं, कुछ कला विधाओं और कुछ भौगोलिक क्षेत्रों की अघोषित अनदेखी नीतीश-राज (एनडीए-1 और 2 के वर्षों सहित) का सांस्कृतिक वैशिष्ट्य रहा है.

नीतीश कुमार नीचे से राजनीति करते यहां तक पहुंचे हैं. इसीलिए उनके सत्ता में आने के साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बांछें खिल गईं. लेकिन हुआ क्या, यह बताने की जरूरत नहीं है और नीतीश कुमार का पराभव उसका प्रमाण है. आदिवासियों के हितों के लिए आवाज बुलंद करनेवाले नीतीश कुमार ने जिन लोगों को राज्यसभा भेजा, यह बताने के लिए सूची ही पर्याप्त है. हालांकि हम ऐसे लोगों की सूची में जॉर्ज फर्नांडीज और शरद यादव या एसएस अहलूवालिया का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनकी कर्मभूमि बिहार रहा है. इसमें गैर बिहारियों और अ-राजनीतिकों की संख्या काफी है. जिन पवन कुमार वर्मा और गुलाम रसूल बिलयावी के कारण पार्टी किश्तों में अपने विधायकों की विधायकी खत्म करवा रही है, वे सभी बिहारी क्या हैं? केसी त्यागी और हरिवंश नारायण सिंह भी बिहारी नहीं हैं. लेकिन इन सभी को बिहार से सांसदी दी गई. इतना ही नहीं जिस जनता परिवार की एका की बात हो रही है उसने आईके गुजराल को बिहार से राज्य सभा भेजा था. लालू प्रसाद के राज में प्रेमचंद गुप्त, श्रीमती सरोज दूबे, कपिल सिब्बल आदि को भी सांसदी बिहार से ही मिली थी. भाजपा भी इसमें किसी से पीछे नहीं है. केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बिहार से ही सासंद हैं. इतना ही नहीं. शिवानंद तिवारी या ऐसे अनेक पुराने समाजवादियों और निष्ठावान राजनेताओं व राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर नीतीश कुमार ने नौकरशाहों को यह मौका देने और उन्हें राजनेता बनाने में बड़ी उदारता बरती. एन के सिंह, पवन कुमार वर्मा, आरसीपी सिंह आदि अनेक बड़े नाम हैं इस सूची में, विधानसभा मंडल के चुनावों में भी अनेक गैर राजनीतिक लोगों को राजनेता की पदवी से नवाजा गया है. ऐसा नीतीश कुमार ने भी किया और लालू प्रसाद ने भी. गैर बिहारियों को सलाहकारों के पद देने की तो बात ही दीगर है. हम ऐसे लोगों ही नहीं कर रहे हैं. अपने गिरबां में न झांकने के आचरण का दूसरा नाम राजनीति है. और इस आचरण से कोई दल अछूता नहीं है. फिर भी, हर दल सामने की पार्टी का टेटर देख रहा है और उसे नसीहत दे रहा है. नीतीश कुमार आदिवासी बनाम गैर आदिवासी के मामले में भाजपा के साथ ऐसा ही कर रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

धूमधाम से मनाया आशीर्वाद दिवस

बिहार राज्य के बक्सर जिलान्तर्गत चिलहरी कुंवर नगर में आशीर्वाद दिवस समारोह पर हजारों गरीबों को भोजन दिया गया. चिलहरी ग्राम पंचायत के मुखिया अलबेला सिंह के घर में उनकी चचेरी भाभी की मृत्यु हो गई थी, बहु की मौत सुन उनकी सास ने कुछ ही घंटे के बाद दम तोड़ दिया. इस प्रकार एक घर से दो-दो लोगों की मृत्यु से पूरे जिले में यह चर्चा का विषय बन गया. इस चर्चा के बीच विभिन्न समाचार-पत्रों में भी खबरें छपी थीं. पावदारों देवी एवं उनकी बहू कमलावती देवी की 13वीं पुण्यतिथि पर आशीर्वाद-दिवस समारोह मनाया गया. समारोह का उद्घाटन पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं लाल कार्ड के निर्माता-देवेन्द्र प्रसाद यादव के द्वारा किया गया इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कलपाती धाम वाराणसी के अभिक ब्रह्मचारी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव-राम बिहारी सिंह, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष-विद्यानन्द विकल, भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष-डॉ. चन्द्रभूषण राय, डुमरांव विधानसभा के कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी-प्रतिमा सिंह, जीतेन्द्र यादव, युवा नेता-सोनू मिश्रा, जीतेन्द्र कुमार, साधु यादव, राहुल शर्मा, सोनू सिंह जिला पार्षद दादू महेन्द्र सिंह डुमरांव गढ़ मुन्ना बाबू सिंह, अखिलेश यादव, मनोज यादव, मिथिलेश राय, कार्यक्रम के संयोजक मृत्युंजय राय मन जी ने समारोह की अध्यक्षता बाबू अनिल सिंह ने की. कार्यक्रम में इसके अलावा भी लोग मौजूद रहे. धन्यवाद ज्ञापन-छात्र जनता दल-यू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष-डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने किया.

भाजपा ने कचहरी चौक पर दिया धरना

भाजपा पंचायती राज मंच ने आज अपनी चौदह सूत्री मांगों को ले कचहरी चौक पर धरना दिया. धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पंचायत जन प्रतिनिधियों को वेतन एवं पेंशन देने की मांग राज्य सरकार से की और कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित सभी जन प्रतिनिधि अनेक चुनौतियों से जूझते हैं. धरना को संबोधित करते हुए विधायक प्रमोद कुमार ने जन प्रतिनिधियों को मान-सम्मान देने का अनुरोध अधिकारियों से किया. धरना की अध्यक्षता धर्मदेव कुशवाहा ने किया जबकि संचालन अरूण कुमार गुप्ता ने किया. मौके पर विधायक सचिन्द्र प्रसाद सिंह, अखिलेश सिंह, चन्द्रा देवी, मुजफ्फरपुर की जिला परिषद अध्यक्ष अर्चना ठाकुर, जिला पार्षद चन्द्रकिशोर मिश्रा, ई. राणा रणधीर सिंह, श्यामबाबू यादव, सुभाष कुशवाहा, रामनारायण सिंह, डॉ. लालबाबू प्रसाद, सुरेश सहनी, हरजीत सिंह, अजय उपाध्याय, अरूण कुमार, गणेश कुमार सिंह, अजय पटेल, उमेश शर्मा, संजय चौधरी, पवन यादव, चुम्मन यादव, प्रमोद गिरी, कामेश्वर चौरसिया, हरिदयाल सिंह, अखिलेश्वर झा, नवीन सिंह, कपिल मुन्नी सहनी, कन्हैया सिंह, युद्ध नारायण सिंह, प्रमिला देवी, विनोद बैठा, जवनाथ पंडित, विवेकानन्द व ओम प्रकाश सिंह आदि ने संबोधित किया. बाद में अपनी चौदह सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य पाल को सौंपा. इनकी मुख्य मांगों में मोतिहारी की मिल मालिक को अविलम्ब गिरफ्तार करने, पंचायत एवं प्रखंड महिला शिक्षकों का स्थानान्तरण इनकी स्वैच्छिक करने का आदेश देने, सांसद व विधायकों की तरह पंचायत समिति एवं जिला परिषद का कोष गठित करने आदि शामिल है.

- इन्तेजारूल हक

सीतामढ़ी

कोहरे ने ढाया मांझी के शिलान्यास पर कहर

मंचासीन सांसद, मंत्री व अन्य

चुनावी मौसम आने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को विकास की याद सताने लगी है. चुनावी घोषणाओं को भूलकर पूरे पांच साल मौज-मस्ती का समय गुजारने वाले प्रतिनिधियों की चालाकी पर अब ऊपर वाले की भी नजर शायद पड़ने लगी है. सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के वीरपुर मलाही गांव में राजकीय बालक पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास सूबे के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा 28 दिसंबर को किया जाना था. परंतु निर्धारित समय से करीब दो घंटा विलंब के बाद लोगों को आकाश में उड़न खटोले की आवाज तो सुनाई दी, लेकिन घने कोहरे के कारण किसी ने भी सीएम के उड़न खटोले का दर्शन तक नहीं किया. कार्यक्रम स्थल पर समारोह की तैयारी धरी की धरी रह गयी. इसके बाद वहां मौजूद नेता लोगों के बीच सरकार की उपलब्धि का ढोल पीट कर चलते बने...

वाल्मीकि कुमार

बीते 28 दिसंबर को सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलो मीटर की दूरी पर स्थित वीरपुर मलाही गांव में सीएम का कार्यक्रम था. मंच पर सांसद, पूर्व सांसद, विधायक व मंत्री के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे. मंच के आजू-बाजू भारी संख्या में मौजूद सुरक्षा बल का हुजूम था. मंच से बार-बार नेताओं की अपील गूंज रही थी. जानलेवा सर्दी के बीच गांव की गलियों से लेकर शहर तक से पहुंच रहे लोगों का काफिला मौजूद था. सीएम को राजकीय बालक पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास करना था. सूबे के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग व विधि विभाग के मंत्री शाहिद अली खान इस क्षेत्र से जदयू विधायक हैं. बताया जाता है कि पुरानी तैयारी को अमलीजामा पहनाने की नियत से ही उक्त कॉलेज का शिलान्यास कराया जाना था. ऐसा अंदाजा लगाया जाना भी सही है. कारण कि बीते सालों में केवल शिलान्यास का कार्य ही अब तक जोर पकड़ता रहा है. परंतु पूर्व से लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने की दिशा में अब तक आवश्यक पहल नहीं की जा सकी है. लोगों की मानें तो ऐसी योजनाओं में फेहरिस्त व अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण व संचालन, पुपरी अनुमंडल कार्यालय भवन का निर्माण, पुपरी में स्टेडियम का निर्माण समेत अन्य शामिल हैं.

अब सवाल यह उठता है कि मंत्री जी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चर्चा कैसी रही. कार्यक्रम में भागीदारी को लेकर पहुंच रहे राम इकबाल राय, मोहन मंगल, सुरेश सहनी, नागेंद्र पासवान, नथुनी राम, रघुवर मांझी, राम प्रबोध ठाकुर, मंगली देवी, जुलेखा खातून, रफीना खातून, नरगीस, फरहाना खातून, रफीक अहमद समेत कुछ अन्य की बातों पर यकीन करें तो एक ओर खुशी इस बात की थी कि क्षेत्र में कॉलेज का शिलान्यास होना था तो दूसरी ओर इस बात की आशंका भी सही रही कि कहीं चुनावी पकवान तो नहीं परोसा जा रहा है. जब पार्टी स्तर पर जदयू के संबंध में पूछा गया तो तकरीबन सभी का एक ही जवाब था कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हैं. चुनाव की चर्चा पर राजनीति के सफल खिलाड़ी की तरह अधिकांश ने कुछ भी बोलने तक से परहेज किया. कहा कि अब समय बतायेगा, पहले वाली बात नहीं है. बहुत दिनों तक नेताओं ने उल्लू बना कर अपना काम निकाला है. अब ऐसा नहीं होगा. भीड़ के बीच जब कुछ लोगों से विकास के सवाल पर चर्चा की गयी तो लगभग अधिकांश ने गुमनामी की शर्त पर अपनी चुप्पी तोड़ दी. लोगों का कहना था कि जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलने वाला है, इस गांव में अब तक हाई स्कूल व स्वास्थ्य केंद्र नहीं है. छात्र-छात्राओं को करीब साढ़े चार किलोमीटर की दूरी तय कर हाई स्कूल में जाना पड़ता है. मामूली तबियत खराब होने की स्थिति में प्रखंड मुख्यालय होते तो सीतामढ़ी जाना पड़ता है. आधी-अधूरी बिजली व्यवस्था वर्षों से पड़ी है. परंतु किसी को नजर नहीं आ रही है. सीएम जीतन राम मांझी की बावत लोगों का कहना था कि करीब से देखने आये हैं. अखबार में पढ़ता हूं कि अनर्गल बयान देते हैं. परंतु जिले में कई महत्वपूर्ण कार्यों का श्रीगणेश सीएम करने वाले हैं तो रहना मुनासिब लगा है.

समारोह स्थल पर कार्यक्रम के दौरान सांसद राम कुमार शर्मा, पूर्व सांसद नवल किशोर राय, गन्ना उद्योग मंत्री डॉ. रंजू गीता, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नौशाद आलम, पूर्व मंत्री सह नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू, विधायक गुड्डी देवी, जदयू नेता राजेश चौधरी, राणा रंधीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक नागेंद्र प्रसाद यादव, किरण गुप्ता, सुनील कुमार सुमन, शंकर बैठा, प्रो. अमर सिंह, प्रमुख गीता देवी, जिप अध्यक्ष इंद्राणी देवी, जिला पार्षद जव्वार अंसारी व मो जियाउद्दीन खां समेत अन्य थे. सरकार के अपने द्वारा आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैद रहा. मौसम खराब रहने के कारण सीएम के न आने की जानकारी मिलते ही कुछ लोगों का सुर बदलने लगा. कहने लगे कि अच्छा ही हुआ. कारण कि शिलान्यास के बाद निर्माण के लिए स्थानीय लोगों को ही आंदोलन करना पड़ता. यहां कोई काम बिना आंदोलन के होता ही नहीं है. जब बाढ़ आये तो राहत, बांध टूटा तो निर्माण और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आंदोलन करने के बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकलता है. मतलब यह की अब लोगों को तनिक भी भरोसा नहीं रह गया है. परंतु सवाल यह खड़ा होता दिख रहा है कि आखिर क्षेत्र के लोग अगले चुनाव में किस की नौका पर सवारी करना चाहते हैं. वर्तमान में एक ओर बिहार का विकास तो दूसरी ओर देश का नव निर्माण का प्रवाह चुनावी चर्चा का केंद्र बना है. कल तक साथ-साथ एक मंच से विकास व सुशासन की बात करने वाली जदयू व भाजपा अब आमने-सामने ताल ठोंक रही हैं. ऐसी स्थिति में विकास के जनचर्चा की चुनावी धारा क्या होगी? पुपरी से सुरसंड विधानसभा क्षेत्र परिवर्तित हो गया है. तो क्या इस क्षेत्र की जनता अगले चुनाव में स्थानीय समस्याओं को चुनावी मुद्दा बना पायेगी? क्या जाति व पार्टी की राजनीति के बीच किसी व्यक्ति को स्थान मिल सकेगा ? फिलहाल इन सवालों का जवाब मिलना मुश्किल प्रतीत होता है.

लगाया गया शिलापट्ट

फिलहाल तो कोहरा ने सीएम के शिलान्यास कार्यक्रम पर कहर ढा दिया है. इन शिलापट्टों का क्या होगा, जिसका पर्दा मुख्यमंत्री के कर कमलों से हटाया जाना था. अब अगली निर्धारित तिथि इस सरकार के कार्यकाल की होगी अथवा अगली सरकार की, कहना मुश्किल हो गया है. वैसे चर्चा यह भी है कि स्थानीय विधायक सह मंत्री शाहिद अली खान इस कार्य को अपनी जामा पहनाने को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है. अब देखना यह है कि मंत्री पुनः मुख्यमंत्री को कब बुला कर इन योजनाओं का पर्दा हटाने में कामयाब होते हैं. अगर समय रहते मंत्री अपनी योजना में सफल होते हैं तब क्षेत्र में चुनावी पीचला सजाना कुछ आसान हो सकता है अन्यथा सुरसंड विधानसभा सीट पर पैनी नजर रखने वाली भाजपा सीएम के इस कार्यक्रम को चुनावी अखाड़े में लाकर ताल ठोंकने से बाज़ नहीं आयेगी. अगर ऐसा होता है तो मंत्री जी की चुनावी परेशानी में इजाफा की आशंका से इंकार नही किया जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

अपने पूर्व नेता मरांडी को मनाने में जुटे हैं अमित शाह

मंगलानंद

विधानसभा चुनाव में करारी मात खाने के बाद अब झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा में जाने को तैयार हैं. झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता बाबूलाल मरांडी को अमित शाह मनाने में जुटे हैं. अभी रघुवर दास कैबिनेट में सात मंत्री पदों की जगह खाली है.

मरांडी के विलय की बात साफ होने के बाद ही दास कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा. भाजपा झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी. झारखंड की 81 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है. आजसू पार्टी के साथ बीजेपी ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था और इसी की पांच सीटों के दम पर रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनी है. पूरे देश में झारखंड राजनीति अस्थिरता के लिए जाना जाता है. ऐसे में भाजपा चाहती है कि वह आजसू पार्टी के भरोसे न रहे. इसी रणनीति के तहत भाजपा अपने पूर्व नेता बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा(प्रजातांत्रिक) का विलय कराने में जुटी है. भाजपा प्रमुख अमित शाह और मरांडी की इस मसले पर मुलाकात भी हुई. मरांडी की पार्टी को इस चुनाव में 8 सीटों पर कामयाबी मिली है. हालांकि मरांडी ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन दोनों जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

रघुवर दास की शपथ से एक दिन पहले अमित शाह ने मरांडी को दिल्ली बुलाया था. दिल्ली में ही दोनों नेताओं की मुलाकात हुई. शाह ने मरांडी के सामने उनकी पार्टी का भाजपा में विलय करने का प्रस्ताव रखा. हालांकि मरांडी ने इस पर तत्काल अमल करने से इनकार कर दिया. लेकिन कहा जा रहा है कि मरांडी ने शाह को आश्वासन किया है. सूत्रों ने बताया कि मरांडी सरकार में शामिल होने के लिए तैयार थे. भाजपा उन्हें दो मंत्री पद भी देने को राजी थी लेकिन रणनीति विलय पर शिफ्ट हो गई. भाजपा गठबंधन बढ़ाने के बजाय मरांडी को शामिल कर झारखंड में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है. झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है. एक भाजपा नेता ने कहा कि मरांडी ने पार्टी में शामिल होने का भरोसा दिलाया है और उम्मीद है कि ऐसा जल्द ही होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

रघुवर दास के पास

चुनौतियों को अवसर में बदलने का है मौका

मंगलानंद

सूबे के 10 वें मुख्यमंत्री के तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो चुके रघुवर दास के लिए झारखंड में चुनौतियां कम नहीं है. रघुवर दास के लिए ये चुनौतियां अब अवसरों में किस हद तक बदल पाती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन जिस प्रकार से सीएम रघुवर दास ने शपथ ग्रहण के बाद झाड़ू पकड़कर पीएम नरेंद्र मोदी की राह पर चलने का संकेत दिया है, उससे साफ हो चुका है कि रघुवरराज में भ्रष्टाचार को काबू में लाने की कवायद तेज होने वाली है. झारखंड के साथ ही अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आये छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड दोनों काफी आगे निकल गये. छत्तीसगढ़ ने तो खुद को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा लिया है. सीएम रघुवर दास ने कामकाज संभालते ही कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है. प्रशासन को पूरी तरह जवाबदेह बनाने की भी हिदायत दी है. उन्होंने सभी

सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू कर प्रदेश के युवाओं की दुखती रग पर हाथ फेरने की कोशिश की है. रघुवर सरकार ने जिस तरह पहले ही दिन राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार समेत कई अहम फैसले लिये हैं, इससे सरकार के काम करने के तौर तरीके स्पष्ट हो गये हैं.

सरकार के कामकाज में बदलाव की छाप स्पष्ट दिखाई दी. हालांकि सरकार के कामकाज की बदली हुई शैली में बहुमत का रोल अहम है. राज्य गठन के बाद प्रदेश में अब तक बनी खिचड़ी सरकारों के कारण झारखंड विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया. झारखंड में 14 वर्षों में स्थानीयता नीति नहीं बन पाई है. कई विभागों की सेवा नियमावली नहीं बनी है. तीन दशक के बाद हुये चुनाव के बाद भी पंचायत को पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं. झारखंड में तबादला सबसे बड़ा उद्योग रहा है, लिहाजा काबिल और काम करने की क्षमता वाले लोग पीछे और लक्ष्मीपुत्र सबसे आगे रहे हैं. झारखंड के विकास की दौड़ में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक अक्षमता रही है. मौजूदा सीएम रघुवर दास के समक्ष इन चुनौतियों को अवसर में बदलने की चुनौती है.

feedback@chauthiduniya.com

असली करमापा का विवाद और गहराया

सुनील सौरभ

दुनियाभर के बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए अथाह आस्था का केंद्र बोधगया इन दिनों दो धर्मगुरुओं के बीच शक्ति प्रदर्शन का स्थल बन गया है. कांग्यू मोनलम पूजा के नाम पर दोनों करमापा बोधगया में एक तरह से अपना-अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. मामला बौद्धों एवं तिब्बतियों के एक पंथ काग्यू कर्मा के धर्मगुरु 17 वें करमापा को लेकर विवाद करीब डेढ़ दशक से चला आ रहा है. लेकिन 17वें करमापा का विवाद ने तब और जोर पकड़ लिया जब इस पंथ के मुख्यगुरु समरपा रिनपोछे का गत 13 जून 2014 को निधन हो गया. समरपा रिनपोछे भारत मे रहने वाले 17 वें करमापा थे. त्रिनले दोरजे के मुख्य गुरु थे. वहीं दूसरी ओर 15 दिसम्बर 1999 को चीन से भागकर आये इग्यने थाये दोरजे को दलाई लामा ने अपना समर्थन दे दिया. क्योंकि बताया जाता है कि 17वें करमापा के रूप में पहचान होने के कारण इग्यने थाये दोरजे को चीन सरकार ने नजरबंद कर दिया था. लेकिन शारीरिक बनावट समेत अन्य कई पहलुओं के उजागर होने के बाद 17 वें करमापा इग्येन थाये दोरजे पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया.

हालांकि चीन से भाग कर आने के बाद शुरुआत में पूरे बौद्ध समुदाय का समर्थन इग्येन थाये दोरजे को 17वे करमापा के रूप में इसलिए मिला कि वह भारत में आने के बाद तिब्बत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन दलाई लामा का समर्थन मिलने के बाद भी इग्येन थाये दोरजे ने न तो कभी खुलकर तिब्बत की आजादी की वकालत की और न ही चीन की अलोचना की. इन सब बातों को लेकर विवाद चल ही रहा था कि इग्येन थाये दोरजे के हिमाचल प्रदेश मे स्थित मठ से करोड़ो की विदेशी मुद्रा, जिसमें चीनी मुद्रा युआन की बड़ी मात्रा में बरामदगी तथा सिम कार्ड से चीन से बात होने की पुष्टि ने भारतीय खुफिया एजेंसी को भी सकते में डाल दिया. इस घटना के बाद बोधगया के लोगों ने भी करमापा के हिमाचल स्थित मठ में की गई छापेमारी और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था. लेकिन बोधगया में भारतीय खुफिया एजेंसी की कड़ी नजर रखें जाने के बाद हर कोई चुप हो गया था.

15 दिसम्बर 1999 को चीन से भागकर नेपाल स्थित पोखरा के रास्ते होते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला पहुंचने पर भारत सरकार ने इग्येन थाये दोरजे को सरंक्षण दिया था. चीन से भागकर आने के कारण दलाई लामा ने भी अपना सर्मथन इग्येन को दिया था और 17वे करमापा के रूप में प्रतिष्ठित किया था. लेकिन जब अप्रैल 2000 में चंडीगढ़ के पीजीआई में इग्येन थाये दोरजे की 23 दिनों तक शारिरिक जांच की गयी, तो वहां के तत्कालीन निदेशक डॉ. एसके शर्मा की जांच रिपोर्ट के बाद इग्येन थाये दोरजे के 17वें करमापा होने पर ही संदेह खड़ा हो गया था. इसी के बाद बौद्धों के बीच 17वें करमापा इग्येन थाये दोरजे को लेकर विवाद बढ़ गया. .■

एक नज़र

गो पूजन कार्यक्रम आयोजित

पूर्वी चम्पारण जिले के संग्राम पुर प्रखण्ड क्षेत्र के पंचभिरवा गांव में गो पुजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर राष्ट्रीय गोवंश विकास मंच के संयोजक मयंकेश्वर सिंह ने गाय की रक्षा के लिए सबों आगे आने की अपील की. श्री सिंह ने कहा कि जन्म देने वाली माता, भारत माता, गंगा माता के सामान ही पूजनीय है गो माता. उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता की पहचान गाय है और इसकी देख-भाल करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है. मंच संचालन कर रहे परमानन्द पाण्डेय ने वैदिक काल की चर्चा की और कहा कि वैदिक काल से लेकर आजतक गाय की सर्वोतम धन रही है और जबतक यह धरती रहेगी तबतक गाय के बिना सुखी जीवन की कल्पना करना बेकार है. गो पूजन में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता, बाबा राम दास, कपिल देव पाण्डेय, वृजकिशोर सिंह, वकील सहनी, भृगुल पासवान सहित सैकड़ों साधू संतो सहित हजारों लोग उपस्थित थे.

इंस्पेक्टर की हुई विदाई

पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया थाना परिसर में केसरिया इन्स्पेक्टर गणेश राम का विदाई समारोह पूर्वक की गयी. समारोह की अध्यक्षता चकिया डीएसपी मुन्द्रिका प्रसाद ने की. कार्यक्रम का संचालन करते हुए थानाध्यक्ष अवधेश कुमार झा ने इन्स्पेक्टर श्री राम के कार्यकलापों पर चर्चा की और कहा कि केसरिया थाना में कार्यकाल काफी सराहनीय रहा. वे सभी पुलिस कर्मियों के साथ अभिभावक की भूमिका निभाते रहे. वहीं कार्यक्रम को जदयू नेता अभय कुमार सिंह, बीडीओ पंकज कुमार दीक्षित, सीओ अखिल कुमार मलिक, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ0 परमेश्वर ओझा, पूर्व प्रमुख सुमित्रा कुमारी यादव समेत कई नेताओं ने संबोधित किया और श्री राम को एक कुशल अभिभावक बताया. इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि विजय जायसवाल, राजद नेता बच्चूलाल यादव, युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष वसील अहमद खां, डॉ. आरके दूबे, निप्पू सिंह, मुखिया गुड्डू खां, महेन्द्र यादव, विजय कुमार शुक्ला, रंजय कुमार सिंह, अरूण सिंह, रंजन कुमार यादव समेत सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे. ज्ञात हो इसका स्थानान्तरण शिवहर जिला में हो गया है.

- इन्तेजारूल हक

कंबल वितरण किया

समस्तीपुर के मथुरापुर स्थित विद्या निकेतन स्कूल में प्रियांशी सेवा संस्थान के तत्वावधान में बच्चों व महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया गया. कार्यक्रम के दौरान दो दर्जन से अधिक जरूरतमंदों को संस्था की ओर से कंबल मुहैया कराया गया. मौके पर शिक्षाविद राजाराम प्रसाद सिंह, जिला स्वयंसेवी संस्था संघ के सचिव संजय कुमार बबलू, सरपंच विष्णुदेव शर्मा, रश्मि कुमारी, हीना कुमारी, दिप्ती कुमारी, चांदनी कुमारी, बेबी तब्बसुम, अमन कुमार, अमरनाथ कुमार, अमित कुमार, राहुल झा, कुंदन कुमार, अमर्त्य व प्रियांशी समेत अन्य थे.

बाइबल किया वितरित

क्रिसमस डे के अवसर पर समस्तीपुर के नारायणपुर डढ़िया स्थित गिफ्ट ऑफ गॉड शिक्षण संस्थान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मौके पर बच्चों को प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने की नसीहत दी गयी. साथ ही 50 बच्चों के बीच बाईबल का वितरण किया गया. मौके पर स्वीटी कुमारी, चांदनी कुमारी, गौरव कुमार, चंद्रभूषण कुमार, रवि कुमार, सूरज कुमार व बादल कुमार समेत अन्य थे. धन्यवाद ज्ञापन अमित कुमार वर्मा ने किया.

- अमृता

सांसद ने किया पुल का शिलान्यास

सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत गोगा नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास सांसद राम कुमार शर्मा व स्थानीय भाजपा विधायक राम नरेश यादव ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़ कर किया. तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाले इस पुल का निर्माण कार्य भी शिलान्यास के साथ ही शुरू करा दिया गया. मौके पर संवेदक समीर कुमार, रालोसपा के प्रखंड अध्यक्ष श्याम कुमार, पूर्व मुखिया कमलदेव महतो, विनोद राय, सुरेश पटेल, रामबाबू सिंह, आशुतोष कुशवाहा, अजय कुमार, गणेश सहनी व राधिका देवी समेत अन्य थे.

- अमरनाथ

गरीबों के बीच कंबल वितरित

सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित खादी उद्योग भवन प्रांगण में लोजपा नेता सवीह अहमद ने एक शिविर का आयोजन किया. मौके पर तकरीबन तीन दर्जन से अधिक गरीबों के बीच शीतलहर को लेकर कंबल का वितरण किया गया. प्रखंड लोजपा अध्यक्ष शिव कुमार पासवान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में लोजपा नेता सवीह अहमद ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा में सदैव लगे रहेंगे. कहा कि सर्दी के प्रकोप से लोगों को निजात दिलाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे. मौके पर जिलाध्यक्ष मोहन झा, युवा लोजपा जिलाध्यक्ष गुंजन कुमार, छात्र लोजपा जिलाध्यक्ष कुणाल गुप्ता, नेहाल अहमद, बब्लू कुमार झा, दिनेश राम, शिव कुमार राम व नरेश पासवान समेत अन्य थे.

- गोविंद

कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन

सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित राम जानकी सरस्वती शिशु मंदिर मोरसंड परिसर में बजरंग दल का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. महंत रघुवर दास की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन का संचालन जिला संयोजक रंजन कुमार सिंह ने की. कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री महंत कन्हैया दास, प्रांतीय संगठन मंत्री जवाहर झा, क्षेत्रीय संयोजक जन्मेजय कुमार, अधिवक्ता अरविंद कुमार ठाकुर, श्याम बिहारी दास, उमेश झा, जिला मंत्री अरविंद कुमार, ईश्वरदेव सिंह, परशुराम सिंह, वसंत कुमार मिश्रा, मनीषा शर्मा व शशिनाथ सिंह समेत अन्य थे. कार्यक्रम से पूर्व कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस भी निकाली.

कार्यशाला का आयोजन

सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित हिंदी भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. दासता रोकथाम एवं हितभागियों के साथ समन्वय विषय पर प्रखंड स्तरीय आयोजित संवेदनशीलता कार्यशाला का उद्घाटन बीडीओ नीरज आनंद व थानाध्यक्ष गोरख राम ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. मौके पर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष विजय कुमार पासवान, मुखिया राम शत्रुघ्न राय, मुकेश कुमार तिवारी, बीएओ रवींद्र चौधरी, महिला विकास समिति के कैलाश प्रसाद सिंह, जवाहर प्रसाद शाही, रामेश्वर साह, ममता कुमारी, नूतन देवी, माधुरी कुमारी व पीके शर्मा समेत अन्य थे.

- विभा

एक नज़र

प्रशिक्षण का आयोजन

सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड के बलहा मकसूदन गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन में प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के सहायक निदेशक, पादप सुरक्षा सतीशचंद्र झा एवं केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. रामईश्वर प्रसाद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. मौके पर पादप सुरक्षा वैज्ञानिक डॉ. दीपक सिंह, उद्यान वैज्ञानिक मनोहर पंजिकार, पशु चिकित्सक वैज्ञानिक डॉ. किंकर कुमार, मनोज कुमार, मुकेश कुमार, राम परीक्षण सिंह, विजय गिरी, बैद्यनाथ राउत, संजीव कुमार सिंह, डॉ. महेश कुमार, कृष्ण कुमार तिवारी, मुकेश सिंह, विजय सिंह, रंजीत सिंह, राकेश कुमार, प्रकाश चंद्रा व सिकन्दर राय समेत अन्य थे.

- गोविंद

लोजपा प्रत्याशी का दौरा

परबत्ता विधानसभा उपचुनाव के लोजपा प्रत्याशी रहीं प्रो. सुहेली मेहता ने जनसम्पर्क कर कई लोगों से मुलाकात किया. उन्होंनें इस कंपकपाती ठंड के बीच जमालपुर के वार्ड संख्या 15,18 एवं अन्य जगहों में जाकर लोगों का हालचाल जाना एवं समस्याओं से अवगत हुए. इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दिया. इस प्रचंड ठंड के मौसम में जनसम्पर्क करने की बात पूछने पर उन्होंने बताया कि पटना के मगध कॉलेज में प्रोफेसर होने के कारण क्षेत्र में हमेशा घूमने का मौका नहीं मिलता है. इस मौके भाजपा नेता उपेन्द्र सिंह, भाजपा नेता अनिल सिंह, संजय सिंह, लगीना सिंह, वार्ड पार्षद रीता देवी, वार्ड प्रतिनिधि शिदयानंद कुमार, हाकीम यादव, प्रियदर्शी चितरंजन, मलिकांत यादव, अजय कुमार सज्जन, अर्जुन यादव, विधानचन्द्र कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

नाट्य कला मंच का शिलान्यास

गोगरी प्रखंड के देवरी पंचायत के अररिया गांव स्थित ठाकुरबाड़ी प्रांगण में तेरहवीं वित्त मद की राशि से जिला परिषद सदस्य पिंकी देवी की अनुशंसा पर निर्माण किये जाने

वाले नाट्य कला मंच का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष कृष्ण कुमारी यादव के द्वारा शिलापट्ट का अनावरण कर किया गया. जबकि इसी गांव में तेरहवीं वित्त से परमानंद यादव के दरवाजे तक पीसीसी निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ. सड़क का उद्घाटन भी फीता काटकर किया गया. मौके पर एक सभा की गई. जिसकी अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश्वर दास ने की. सभा को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा देवी यादव ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना ही हमारा ध्येय है. वहीं अपने संबोधन में जिला परिषद सदस्य पिंकी देवी ने कहा कि मैं जबसे जिला परिषद सदस्य बनी हूं तब से मैं समानता के आधार पर विकास करने में लगी हुई हूं.

बेटी धर्म निभाने की जिम्मेदारी

गोगरी प्रखंड के सर्किल नम्बर 1 की महिलाओं ने एसपी किम को खोईछा में कोसी के आंचल की मिट्टी और मुख्य फसल धान, दूबरी एवं हल्दी देकर जहां अपनी क्षेत्रीय परंपरा से रू-ब-रू कराया. वहीं क्षेत्र में बदलाव की बयार को हवा देने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी. कोसी का हर साल विनाश लीला को झेलते हुए कई बार विस्थापित हुए परिवारों को एसपी से एक उम्मीद बंधी है कि अब दियारे का भी विकास होगा. इस दुर्गम इलाके में जहां शाम ढलते ही निकलना मुनासिब नहीं समझते थे. जहां अपराधों की खेती होती थी. वहां दुर्गा की अवतार बन एसपी किम ने अपराधियों का मां दुर्गा बनकर इनका नाश करने का काम किया किया है. इस मौके पर महादलित परिवार की सरिता देवी ने बताया कि इनके यहां बेटी एवं मां दुर्गा की विदाई के समय खोईछा दिया जाता है.

मीटर रीडिंग का गड़बड़झाला

गोगरी में बिजली बिल में गड़बड़ी से परेशान उपभोक्ताओं में अब व्यवस्था के प्रति सुधार की इम्मीद नजर आ रही है. यह इम्मीद विभाग के कार्यपालक अभियंता के आश्वासन के बाद जगी है. क्षेत्र भ्रमण के दौरान गोगरी पहुंचे कार्यपालक अभियंता को जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव राजेश खेतान के नेतृत्व में इपभोक्ताओं ने जमालपुर बाजार में घेर कर बिजली बिल गड़बड़ी को लेकर अपना विरोध जताया. बिल में सुधार की मांग के साथ नियमित व सही ढंग से मीटर रीडिंग कराए जाने की मांग की गई. इपभोक्ताओं का कहना था कि रीडिंग कर्मी द्वारा घर बैठे जैसे-तैसे की जाती है.

मैच का उद्घाटन

गोगरी. पितौंझिया मैदान में हुए फाइनल मैच में पितौंझिया ने कोलवारा को दो गोल से हराकर कम पर कब्जा जमा लिया. दोनों ही टीम निर्धारित समय में एक भी गोल नहीं कर सकी. इसके बाद अतिरिक्त समय में पितौंझिया के कप्तान निशांत कुमार ने एक गोल दागकर मैच जीत लिया. मैच का इद्घाटन जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव डा संजीव कुमार ने किया. मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष कैलाशचन्द्र यादव, अमर यादव, लालबिहारी चौरसिया, पैक्स अध्यक्ष फणिभूषण यादव, मणिभूषण सिंह, जदयू नेता राजेश खेतान, दीपक कुमार एवं नवीन कुमार सहित सैकड़ों दर्शक इपस्थित थे.

गीता कुमार

डीलर्स एशोसिएशन का गठन

सिद्ध सागर भवन फारबिसगंज में एफएमसीजी डीलरों की एक बैठक तेजनारायण अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. व्यवसाय हित में एफएमसीजी डीलर्स एशोसिएशन का गठन सर्वसम्मति से किया गया. इसमें अजातशत्रु अग्रवाल को अध्यक्ष, अंजनी मिश्रा को उपाध्यक्ष, विपुल विश्वास को महासचिव सह प्रवक्ता, सुजीत कुमार को सचिव, हरेन्द्र फिटकिरीवाला (पप्पू) को कोषाध्यक्ष तथा जय कुमार अग्रवाल, कुणाल भगत, राजू रंजन, गोपालकृष्ण, राजू खत्री को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया. बैठक में सर्व श्री प्रदीप साह, अजीत डागा, श्याम लखोटिया, रानू चैन वाला, अरविंद पांडिया, बादल जिंदल, दीपक समदरिया, श्याम लखोटिया, प्रकाश सेठिया, हरीश अग्रवाल सहित करीबन चार दर्जन डीलर्स उपस्थित थे. बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्षों तक के लिए होगा. किसी भी कंपनी एवं डीलर्स के बीच में व्यवसायिक मतांतर होने पर एशोसिएशन मध्यस्ता करेगा. किसी भी कंपनी के द्वारा अपने पुराने डीलर को बदले जाने की सुरत में एनओसी लेने की अनिवार्यता का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया. अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री अग्रवाल ने सभी डीलरों से व्यापार में ईमानदारी बरतने की अपील करते हुए विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा कंपनी और डीलर्स के हितों पर बराबर ध्यान रखा जायेगा.

मोतिझील

> प्रकाशित खबर में मोतीझील महोत्सव के नाम पर किस तरह की राजनीति की गयी थी, इसे विस्तार से रेंखाकित किया गया था. प्रकाशित खबर के बाद पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव का कड़ा रुख सामने आया और करीब तीन दर्जन अतिक्रमणकारियों पर मोतिहारी नगर थाना में मुकदमा किया गया. डीएम ने खुद अतिक्रमित क्षेत्र का भ्रमण किया और अतिक्रमणकारियों के साथ सख्ती से पेश आने का फरमान जारी किया. अब देखना है कि जिलाधिकारी के आदेश का असर कितना रहता है और कितने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होती है.

जानिए कौन हैं मोतीझील की मौत के जिम्मेदार

इन्तेज़ारुल हक

मोतिहारी शहर को दो भागों में बांटने वाली मोतीझील की कीमती जमीन पर अवैध कब्ज़ा जमाने वाले लोग आखिर कौन हैं? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? वे मुकदमों व अन्य प्रशासनिक कार्रवाईयों के बावजूद अपना अतिक्रमण क्यों नहीं हटाते? ये लोग आम जनता हैं या भू–माफिया या फिर सरकारी मुलाजिम! जो जिला प्रशासन के कड़े आदेश को खुली चुनौती देते हैं. नगर पालिका प्रशासन भी इस मामले पर स्पष्ट रूप से खुलकर क्यों नही आ रहा है और उसकी मंशा क्या है?इस मद्दे पर इन दिनों लंबी और गर्मागर्म बहसें हो रही हैं. अनेक तरह की चर्चाएं भी होने लगी हैं.

यह जानना वाकई दिलचस्प है कि आखिर कैसे सरकारी अधिकारी ही मोतीझील को बड़ी बेदर्दी से नुकसान पहुंचा रहे हैं. झील की जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि इसकी रक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है. सरकारें मोतीझील की हालत सुधारने व उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए एक तरफ मास्टर प्लान बना रही हैं और करोड़ों रुपये खर्च करने की तैयारी कर रही हैं तो दूसरी तरफ उसके अधिकारी ही उसकी जमीन की रक्षा करने के बजाये खुद अवैध तरीके से अतिक्रमित कर मोतीझील को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसके अलावा मोतीझील की इस जमीन पर अपना कब्जा जमाने में शहर के कई मशहूर चिकित्सक, राजनेता व पूर्व मंत्री भी शामिल हैं जो अपनी इमारतें यहां खड़ी कर चुके हैं. चौथी दुनिया अखबार ने जब इस बाबत तहकीकात शुरू की और नगर वासियों की भावना की कद्र करते हुए झील से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों को हासिल किया तो अनेक चौंकाने वाले तथ्य सामने आये. कुल 246.47 एकड़ भूमि में फैली इस झील के

अतिक्रमणकारियों की सूची

शिवकुमार शर्मा पूर्व (अंचलाधिकारी बंजरिया), सहदेव सहनी बेलबनवा,डॉ. तबरेज अजीज (सदर प्रखण्ड के बगल में), प्रखंड विभाग सरकारी भवानीपुर जिरात,कृष्ण सिंह महिला महाविद्यालय, रोबीन क्लब, खुशबु अली, मो. रसूल, शंकर कपूर ग्रीन पार्क, रहमान मेडिकल भवानीपुर जिरात, अशोक प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद, ध्रुव नारायण पटेल, गंगाई पटेल, पारस नाथ श्रीवास्तव, अब्दुल्लाह अंसारी, प्रबंधक चीनी मिल मोतिहारी बरियारपुर, रामेश्वर ठाकुर, रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. रहमान, टुनटुन मियां, जीमल अंसारी, इब्राहीम अंसारी, हरीशंकर सिंह, चंद्रिका राय, अशोक प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद, ललिता मिश्रा, दीपक कुमार, मुस्तफा अंसारी, विष्णुदेव ठाकुर, मिथलेश कुमार, जगरनाथ ठाकुर, तिलक ठाकुर, दीपक कुमार जायसवाल, सज्जन कुमार, रमेश प्रसाद वर्मा, सच्चिदानन्द श्रीवास्तव, सुल्तान अहमद, गंगा देवी, ललित मिश्रा, प्रखंड नर्सरी उद्यान, गायत्री मंदिर बेलबनवा, राजेन्द्र साह, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव मिस्कौट, प्राचार्य प्राथमिक कन्या विद्यालय मिस्कौट, डॉ. अतुल कुमार बलुआ टाल, गजाला प्रवीण बेलबनवा, आतिशाआनंद बेलबनवा, नजबुननेशा बेलबनवा,मो. अमीम, मो. शमशेर आलम बेलबनवा, हबीब मियां बेलबनवा, राजेश्वर प्रसाद सिंह बेलबनवा, सुरेश राय मिस्कौट, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद,विनोद रजगरिया मिस्कौट,महेन्द्र पासवान मिस्कौट,गोविन्द राय मिस्कौट,नन्द लाल राय मिस्कौट,सज्जन कुमार भवानीपुर जिरात,कैफी उजैर हाशमी मीना बाजार, गोपाल सहनी मीना बाजार,रंजन कुमार सिन्हा बेलबनवा,रमेश चौधरी ग्रीन पार्क,डॉ. जलालुद्दीन छतौनी, अंजनी श्रीवास्तव चांदमारी, दीपक कुमार भवानीपुर,पारसनाथ श्रीवास्तव भवानीपुर, शंभु जायसवाल मीना बाजार चौक, ललित मिश्रा मधुबन छावनी चौक, सुल्तान अहमद, सकलदीप प्रसाद,भवानीपुर जिरात,रमेश प्रसाद वर्मा भवानीपुर जिरात, मुकुल अस्थाना भवानीपुर जिरात, ललित मिश्रा मधुबन छावनी चौक, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, मदन चौरसिया हिरालाल साह मध्य विद्यालय,गीरजा प्रसाद मधुबन छावनी चौक,ललित मिश्रा मधुबन छावनी चौक,गिरजा प्रसाद मधुबन छावनी चौक, प्रबंधक सुलभ शौचालय, शत्रुघ्न अस्थाना बेलबनवा, सुरेन्द्र कुमार वर्मा बेलबनवा, उमेश कुमार बेलबनवा,दिनेश बेलबनवा, पंडित जी बेलबनवा, पंकज कुमार सिंह बेलबनवा,अभय कुमार शर्मा बेलबनवा,योगेंद्र साह मोतीझील के किनारे,अनिल कुमार साह मोतीझील के किनारे, सुरेश प्रसाद मोतीझील के किनारे, सुनील कुमार पांडेय, जगदीश ठाकुर अगरवा, विष्णुदेव ठाकुर अगरवा, हरिशंकर ठाकुर अगरवा, जग्रनाथ ठाकुर अगरवा,शिवजी ठाकुर अगरवा,तिलक ठाकुर बेलबनवा,कृष्णा ठाकुर, सखीन्द्र ठाकुर व इन्द्रकान्त ठाकुर गायत्री नगर, लालबाबू सहनी गायत्री नगर, अरुण कुमार मीना बाजार, अरविन्द कुमार सुभाष मार्केट, खुशबू अली होटल ग्रीन पार्क के पास,नागेन्द्र प्रसाद मिस्कौट,जगत नारायण सिंह मिस्कौट, रवींद्र पाण्डेय बेलबनवा, देवेन्द्र कुमार वर्मा, उदयनारायण वर्मा बेलबनवा,रामबचन सहनी अगरवा, लालबाबू सहनी अगरवा, कृष्णा ठाकुर अगरवा, रमेश्वर ठाकुर अगरवा, बैधनाथ ठाकुर अगरवा, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोतिहारी, मत्स्य पदाधिकारी मोतिहारी, राधेश्याम प्रसाद भवानीपुर जिरात, तारा देवी भवानीपुर जिरात, संजीव बेलबनवा, सत्यदेव प्रसाद बेलबनवा, मधु देवी मिस्कौट, उमेश प्रसाद जायसवाल मिस्कौट,मो. फिरोज जानपुल, सुनील कुमार सिन्हा भवानीपुर जिरात, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह भवानीपुर जिरात, उमेश चन्द्र सिंह भवानीपुर जिरात, व्यवस्थापक मदरसा भवानीपुर जिरात, रंजन सिंहा सुभाष पार्क के अनदर शिलापट्ट कटिंग व अन्य 16, जनक प्रसाद मिस्कौट, सत्यानारायण प्रसाद मिस्कौट, कुमर जी मिस्कौट, साईबाबा मंदिर कदम घाट, प्रेमशंकर गुप्ता सुभाष मार्केट, रवि कुमार सुभाष मार्केट, मोहन प्रसाद सुभाष मार्केट, मंकेश्वर प्रसाद सुभाष मार्केट,दिनेश प्रसाद सुभाष मार्केट,मदीना खातुन सुभाष मार्केट,सुबोध कुमार सुभाष मार्केट,कार्यपालक अधीक्षक नगर परिषद,मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव भवानीपुर जिरात,सच्चिदानन्द श्रीवास्तव भवानी पुर जिरात,पेट्रॉल पंप गायत्री मंदिर के निकट.■

मोतीझील की इस जमीन पर अपना कब्जा जमाने में शहर के कई मशहूर चिकित्सक, राजनेता व पूर्व मंत्री भी शामिल हैं जो अपनी इमारतें यहां खड़ी कर चुके हैं. चौथी दुनिया अखबार ने जब इस बाबत तहकीकात शुरू की और नगर वासियों की भावना की कद्र करते हुए झील से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों को हासिल किया तो अनेक चौंकाने वाले तथ्य सामने आये. कुल 246.47 एकड़ भूमि में फैली इस झील के अतिक्रमणकारियों की जो सूची मिली है, उसे पढ़ने व देखने के बाद एक तरफ जहां अधिकारियों की कलई खुल गयी है तो दूसरी तरफ शहर के कई मशहूर चिकित्सकों, जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, का भी कारनामा सामने आ गया है. खुद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी व कार्यपालक अधीक्षक भी मोतीझील की जमीन पर कब्ज़ा किये हुए हैं और उन पर भूमि–सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में इस बाबत केस चल रहा है.

अतिक्रमणकारियों की जो सूची मिली है, उसे पढ़ने व देखने के बाद एक तरफ जहां अधिकारियों की कलई खुल गयी है तो दूसरी तरफ शहर के कई मशहूर चिकित्सकों, जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, का भी कारनामा सामने आ गया है. खुद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी व कार्यपालक अधीक्षक भी मोतीझील की जमीन पर कब्ज़ा किये हुए हैं और उन पर भूमि–सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में इस बाबत केस चल रहा है. इसके अलावा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर सिंह, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. तबरेज अजीज,डॉ. अतुल कुमार, मोतिहारी चीनी मिल, प्रखण्ड नर्सरी उद्यान कार्यालय सदर, गायत्री मंदिर बेलबनवा, प्रबंधक सुलभ शौचालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोतिहारी सदर, मत्स्य पदाधिकारी मोतिहारी, व्यवस्थापक मदरसा, साई बाबा मंदिर कदमघाट, सच्चिदानन्द श्रीवास्तव भवानीपुर जिरात, पेट्रोल पंप गायत्री मंदिर का नाम अवैध अतिक्रमणकारियों की सूची में है. जानकार बताते हैं कि अगर इस झील की जमीन पर आम आदमी का कब्ज़ा होता तो प्रशासन ने बहुत पहले ही अपना बुल्डोजर चला दिया होता और अतिक्रमणकारी सड़क पर आ गये होते लेकिन यहां बात दूसरी है, जिससे सभी वाकिफ हैं. हालांकि पिछले अंक में चौथी दुनिया में मोती–झील की बदहाली व उसके नाम पर की जा रही राजनीति पर छपी खबर ने जिला प्रशासन की आंखें खोल दी हैं और नगरवासी भी अब इस झील के प्रति काफी जागरूक दिख रहे हैं. प्रकाशित खबर में मोतीझील महोत्सव के नाम पर किस तरह की राजनीति की गयी थी, इसे विस्तार से रेंखाकित किया गया था. प्रकाशित खबर के बाद पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव का कड़ा रुख सामने आया और करीब तीन दर्जन अतिक्रमणकारियों पर मोतिहारी नगर थाना में मुकदमा किया गया. डीएम ने खुद अतिक्रमित क्षेत्र का भ्रमण किया और अतिक्रमणकारियों के साथ सख्ती से पेश आने का फरमान जारी किया. अब देखना है कि जिलाधिकारी के आदेश का असर कितना रहता है और कितने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होती है. लेकिन जिस तरह से अतिक्रमणकारियों को बचाने का प्रयास कुछ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उसकी भी चर्चा यहां की जा रही है. वैसे 160 लोगों का अवैध कब्ज़ा इस मोतीझील की जमीन पर है और सभी को चेतावनी पत्र प्रशासन द्वारा भेजा जा चुका है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

12 जनवरी–18 जनवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

खाद की कमी से किसान बेहाल

तस्करी के जरिए खाद नेपाल जा रही है

हरिशंकर वर्मा/अजय गुप्ता

उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव की गहरी चिंता और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश के बावजूद प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से नेपाल के लिए खाद की तस्करी बेतहाशा हो रही है. इससे प्रदेश के किसानों को डीएपी, एनपीके और यूरिया खाद की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यूपी के किसानों को अपनी ही खाद महंगे दाम पर खरीदनी पड़ रही है. यूपी की सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में खाद की जबरदस्त मांग है. नेपाल सीमा से जुड़े जिलों महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के रास्ते से खाद की तस्करी की जा रही है. इसमें कई ऐसे मार्ग हैं जहां पर सीमा सुरक्षा बल की चौकियां भी हैं, लेकिन इससे खाद की तस्करी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर भारतीय खाद नेपाल भेजी जा रही है. खाद की सबसे ज्यादा तस्करी लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा, कुरियाला घाट, नेपालगंज, तुलसीपुर, कोल्हुई (खैराघाट), जोगियाबारी और सोनौली से हो रही है.

स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस इसे रोकने में फेल है. यह भी कह सकते हैं कि स्थानीय पुलिस और दोनों ओर की सीमा चौकियों की मिलीभगत से तस्करी हो रही है. नेपाल से लगे प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में खाद की किल्लत पैदा हो गई है. कृषि विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने पर किसानों को रटा-रटाया डायलॉग सुनना पड़ता है कि खाद की कोई दिक्कत नहीं है. शासन का भी कहना है कि प्रदेश में कहीं पर भी खाद की कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन दबी जुबान से शासन के आला अधिकारी तस्करी के कारण खाद की किल्लत की बात स्वीकार करते हैं.

किसान हित का रोना रोने वाली सरकार किसानों को खाद तक मुहैया कराने में नाकाम है और हर दिन खाद के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शनों की खबरें आती रहती हैं. सरकार की तरफ से किसानों के लिए भेजी जाने वाली खाद किसानों तक न पहुंच कर खाद माफियाओं के जरिए ब्लैक में बिकती है या फिर पड़ोसी देश नेपाल भेज दी जाती है. भारत-नेपाल सीमा पर यूरिया खाद की न थमने वाली तस्करी लगातार जारी है और क्षेत्र का किसान एक-एक बोरी खाद के लिए इधर-उधर भटक रहा है. सरकारी गोदामों पर ऊंचे दामों पर खाद की बिक्री करके सरकारी मुलाजिम अपनी जेबें भर रहे हैं. सीमा पर सक्रिय तस्कर कैरियरों के माध्यम से खाद को साइकिलों से मंगवाकर अपने अड्डों पर जमा कर लेते हैं. फिर सुविधानुसार उसे सीमा पार नेपाल भेज देते हैं.

नेपाल में यूरिया खाद की बढ़ी भारी मांग का फायदा उठाते हुए सीमावर्ती गांवों-कस्बों में सक्रिय तस्कर सुरक्षा एजेंसियों की साठगांठ से यूरिया खाद की तस्करी कर रहे हैं. तस्कर यहां से विभिन्न साधनों के द्वारा थोड़ी-थोड़ी खाद की बोरियां मंगाकर अड्डों पर जमा कर लेते हैं, फिर मौका पाकर उसे नेपाल सप्लाई कर देते हैं. सीमावर्ती कस्बों में हिस्ट्रीशीटर तस्करों ने तो काला धंधा छिपाने के लिए विभिन्न तरह की दुकानें भी खोल ली हैं और वहीं से बैठकर वे तस्करी के नेटवर्क का संचालन करते हैं. इसमें कजरिया, बनगवां, सेड़ाबेड़ा, बनकटी, सूंड़ा, सौनहा, चंदनचौकी, बेलापरसुआ आदि गांवों से सैकड़ों बोरी यूरिया खाद हर रोज तस्करों द्वारा नेपाल भेजी जाती है. सरकारी गोदामों पर खाद का दर्शन दुर्लभ है. ऊंचे दामों पर खुले बाजार में खाद की बिक्री हो रही है. जरूरत का मारा किसान बढ़े दामों पर खाद खरीदने को विवश है. सरकार द्वारा किसानों को उचित दाम पर खाद मुहैया कराने के लिए सहकारी समितियों के पास खाद भेजी जाती है.

कृषि विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से सहकारी समितियों पर तैनात कर्मचारी उसी खाद को माफियाओं के हाथों ऊंचे दाम पर बेच देते हैं. ऐसा कभी नहीं देखा गया कि सहकारी समितियों का आकस्मिक निरीक्षण हुआ हो और खाद वितरण में गड़बड़ी करने वाली सहकारी समितियों के विरुद्ध कभी कोई सख्त कार्रवाई की गई हो. इस दिशा में कृषि विभाग पूर्ण रूप से उदासीन है. किसानों में रोष है, लेकिन वे क्या करें. लखीमपुर खीरी के किसानों ने डीएम तथा जिला कृषि अधिकारी को पत्र भेजकर सहकारी समितियों पर यूरिया आदि खादें उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की तो कोई नतीजा नहीं निकला. खीरी जिले के बार्डर पर गौरीफंटा मंडी हटने के बाद तस्करों ने भारत-नेपाल सीमावर्ती थारूक्षेत्र के प्रमुख गांवों के साथ चन्दनचौकी तथा सूड़ा चौराहा मंडी को आखेट-स्थल बना लिया है. सीमा की सुरक्षा संभालने वाली एसएसबी की जगह-जगह चौकियां बनी हैं. इसके अलावा सिविल पुलिस, कस्टम विभाग सहित तमाम अन्य सुरक्षा एजेसियां भी सीमा की निगरानी के नाम पर फल-फूल रही हैं और तस्करी का अवैध कारोबार भी अमरबेल की तरह पनपता जा रहा है. कुछ महीने पहले एसडीएम तथा सीओ ने दलबल के साथ सूंड़ा मंडी के भूमिगत गोदामों पर छापा मारा था लेकिन वहां कुछ नहीं मिला. जबकि सूड़ा गांव से भारी मात्रा में खाद्य सामग्री बरामद की गई थी जो तस्करों ने नेपाल ले जाने के लिए गांव में छिपा कर रखा हुआ था. तस्करों ने सीमावर्ती ग्राम सेड़ाबेड़ा, बनगवां, बनकटी, सूंडा गांव एवं सूंडा चौराहा मंडी, नझोटा, सौनहा, चंदनचौकी आदि में अपने नए अड्डे बना लिए है जहां पर पलिया से सामान लाकर स्टॉक किया जाता है, फिर मौका लगते ही प्रतिबंधित सामान को सीमा पार नेपाल भेज दिया जाता है. इसमें मुख्य रूप से सीमेंट, लोहा, यूरिया, किराना सामान, खाद्यान्न, सौंदर्य प्रसाधन और स्टेशनरी समेत अन्य कई भारतीय उत्पाद शामिल हैं. इसे रोकने में सुरक्षा एजेंसियां फेल हैं. लखीमपुर खीरी जिले में खाद की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं. गेहूं, गन्ना, लाही व शाकभाजी की खेती करने वाले किसानों को खाद की आवश्यकता है. इफको जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहा है. मटर और मसूर में पोलियर स्प्रे किया जाना है. वहीं जिले से बड़ी मात्रा में खाद की तस्करी पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में की जा रही है. छिटपुट मामलों में ही बरामदगी हो रही है. तस्करी की खाद साइकिल, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर-ट्रॉली से नेपाल तक पहुंचाई जा रही है. नेपाल तक जाने वाले विभिन्न मार्गों से दुपहिया वाहनों से धड़ल्ले से तस्करी हो रही है. सीमा से सटे इलाके में संचालित खाद की दुकानों से नेपाल तक खाद पहुंचाई जा रही है. इसके लिए इन दुकानों पर कैरियर का कार्य करने वाले लोगों की लंबी फेहरिस्त है. जो सुरक्षा एजेंसियों से साठगांठ करके खाद नेपाल ता पहुंचा रहे हैं. नेपाल में खाद निर्धारित मूल्य से दूगने दामों में बिक रही है.

पलिया तहसील क्षेत्र में महंगापुर, त्रिकोलिया, गदनिया, नौरंगपुर और पलिया के अलावा पीलीभीत जिले के हजारा क्षेत्र से खाद की आपूर्ति नेपाल तक की जा रही है. इसी प्रकार बेलरायां, सगाही और तिकोनिया क्षेत्र के गांवों से भी खाद की तस्करी हो रही है. बेलरायां क्षेत्र में मारिया घाट, पत्थरशाह, खखरौला घाट, चौगुर्जी घाट, व कौड़ियाला घाट है, जहां पर बड़ी-बड़ी नावें मोहाना नदी में पड़ी हैं, इन्हीं नावों से रात में तस्करी का सामान आसानी से नेपाल जा रहा है. इसके अलावा घाट, हलौना घाट, करिया कुंडा घाट व कौआ खेड़ा घाट सहित कई घाट तस्करी के लिए जाने जाते हैं. ■

सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है

एक तरफ जमीनी हालत भयावह है तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने देने का अंध-राग आलापना छोड़ नहीं रही है. प्रदेश सरकार तस्करी के कारण हो रही खाद की किल्लत को स्वीकार करने के बजाय उसे केंद्र सरकार के कंधे मढ़ देने का सारा उपक्रम करती रहती है. प्रदेश शासन का कहना है कि राज्य सरकार यूरिया की सुचारू आपूर्ति के लिए वह भारत सरकार से लगातार अनुरोध कर रही है. इफको के फूलपुर संयंत्र को भी फिर उत्पादन प्रारम्भ कराकर यूपी को दो लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराने के बारे में कहा गया है. प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन अधिकारियों को निर्देश देने की औपचारिकता पूरी कर लेते हैं कि खाद की कालाबाजारी कतई न होने पाए. जबकि असलियत वे भी अच्छी तरह समझते हैं. इन्हीं सब वजहों से अखिलेश सरकार पर अक्षमता का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि वह नाकाम सरकार यूरिया की कमी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही है. भाजपा ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने में जुटी अखिलेश सरकार किसान-किसान तो रटती है पर किसानों की समस्या का समाधान नहीं करती. भाजपा के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि राज्य में वितरण व्यवस्था की खामियों के कारण राज्य में यूरिया का संकट गहरा रहा है. पाठक ने भी कहा कि सीमा से जुड़े जनपदों से लगातार बेधड़क रूप से खाद की तस्करी हो रही है. इस तस्करी को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है. भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि सुनियोजित तरीके से हो रही खाद की तस्करी रोकने के लिए राज्य सरकार ने कौन-कौन से उपाय किए, उसे वह जनता को बताए. उन्होंने कहा कि देश के कुल उपभोग का 18 प्रतिशत उर्वरक उत्तर प्रदेश में प्रयोग होता है, फिर भी इसका प्रबन्धन अराजकता से भरा होता है. समाजवादी पार्टी ने कहा था कि प्रदेश में उनकी सरकार बनते ही वैट की दरों को कम कर पड़ोसी राज्यों के समान कर दिया जाएगा लेकिन उत्तर प्रदेश में खाद पर वैट अन्य राज्यों से अधिक है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सिख अल्पसंख्यकों पर ढहा समाजवादी सत्ता का जुल्म

महोबा में महाबली की सरकार

इसरार पठान

पैसा, पावर और पॉलीटिक्स के दम पर महोबा में सब कुछ सम्भव है. यह वही ताकत है जिसके दम पर हर एक रसूखदार अपनी मनमानी करता है और उस मनमानी पर इतराता भी है. सोमवार 29 दिसम्बर को महोबा शहर में जो हुआ, वह इसी ताकत का नमूना था. यहां ऐसे ही एक रसूखदार ने पैसे के दम पर मीडिया का मुंह बन्द कर दिया. उसके बंगले से होती फायरिंग उसके पावर की कहानी ही बयान कर रही थी. उसकी उंगली पर नाचता प्रशासन उसकी शासन और प्रशासन पर पकड़ साबित करने के लिए काफी था. गौतम शर्मा नाम के इस रसूखदार की इन्हीं तीन खूबियों का परिणाम था कि प्रशासन ने पहले तो अल्पसंख्यक कहे जाने वाले सिख समुदाय की दुकानों पर बुलडोजर चलवाया और फिर अपने हक को लेकर सड़कों पर उतरे इस समुदाय के लोगों की आवाज को बन्दूक के बल पर घोंट दी. गौर करने वाली बात यह है कि ये सब एक ऐसे रसूखदार शख्स के इशारे पर किया गया, जो खुद को सूबे के मुख्यमंत्री का दोस्त बताता है. सपा सरकार के सत्ता में काबिज होने के बाद से लगातार किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मुख्यमंत्री के इस कथित मित्र की इस हरकत ने लोगों को हैरत में डाल दिया है. इस मामले में प्रशासन का रवैया तो बेहद शर्मनाक था ही, साथ में सत्ता पक्ष सहित विपक्षी दलों के नेताओं की भूमिका भी हैरान कर देने वाली नजर आई. 29 दिसम्बर को महोबा शहर में सिख समुदाय की दुकानों को ढहाए जाने पर खूब बवाल हुआ. सारा दिन शहर का गांधीनगर इलाका पुलिस छावनी बना रहा. कर्फ्यू जैसे हालात के बीच सिखों के बच्चों और महिलाओं ने इस कार्रवाई का बेहद दमदारी के साथ विरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें प्रशासनिक सख्ती के सामने घुटने टेक देने पड़े. मामला तब शुरू हुआ, जब उप जिलाधिकारी सदर ने उस रसूखदार कथित नेता के इशारे पर पुलिस की मदद से कुछ सिखों की दुकानों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की. आंखों के सामने अपने रोजगार को तबाह होते देख सिख समुदाय के लोग भड़क उठे और फिर जो कुछ हुआ वह किसी भी मायने में सही नहीं है. देखते ही देखते अल्पसंख्यक समुदाय के लोग महिलाओं और बच्चों के साथ सड़कों पर आ गए और पुलिस तथा प्रशासनिक अमले पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी गुस्साई भीड़ उस गौतम शर्मा के दरवाजे तक पहुंच गई, जिसे लोग भू-माफिया और खनन माफिया बताते हैं और जो सपा मुख्यमंत्री का नजदीकी व्यक्ति बताते हैं. उसी के इशारे पर प्रशासन ने इस कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया था. बताते हैं कि जो दुकानें बुलडोजर का शिकार बनीं उनका मालिकाना हक मुख्यमंत्री के उस कथित मित्र के पास है और विरोध करने वाले सिख समुदाय के लोग पिछले चालीस वर्षों से इन दुकानों पर किरायेदार की हैसियत से काबिज थे. कहा तो यह भी जाता है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था और हाल ही में माननीय जिला सत्र न्यायालय ने दुकानों को खाली कराए जाने का फैसला सुना दिया था. प्रशासनिक अधिकारियों सहित इस रसूखदार व्यक्ति की वकालत करने वाले लोगों का कहना है कि यह सब कार्रवाई नियमानुसार की गयी है, जबकि पीड़ित सिख समुदाय का आरोप है कि उनके पास ऐसे किसी भी आदेश की सूचना नहीं है. बिना किसी अग्रिम सूचना के प्रशासन ने उनकी दुकानों को ढ़हा दिया.

सवाल यह है कि प्रशासन ने परिस्थितियों को जानते और समझते हुए भी आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, जिसके चलते हालात इस कदर बिगड़ गए. प्रशासन की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने इस मामले को शालीनतापूर्वक निपटाने की जगह सख्ती का रास्ता चुना. जबकि बताया यह भी जाता है कि इस घटना क्रम के ठीक एक दिन पहले उप जिलाधिकारी सदर द्वारा बात किए जाने पर सिख समुदाय के जिम्मेदार लोगों ने बैठक कर इस मसले को सुलझाने पर अपनी सहमति दे दी थी. बावजूद इसके इस कार्रवाई को अमलीजामा पहनाकर प्रशासन ने न केवल अपने लिए मुसीबत खड़ी की, बल्कि सरकार की छवि तक पर दाग लगाया. पहले दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया और फिर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर लाठियां भांजी गईं. प्रदर्शन में शामिल सिख महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर चूड़ियां फेंककर इस बर्बतापूर्ण कार्रवाई पर विरोध प्रकट किया. जबकि सिख समुदाय के युवा और वृद्ध पुरुष भीड़ की शक्ल में सत्ता सामर्थ्यवान के घर के दरवाजे पर सारा दिन प्रदर्शन करते रहे. स्थिति तब और बिगड़ गई, जब मुख्यमंत्री के इस कथित मित्र की सुरक्षा में लगे प्राइवेट अंगरक्षकों ने बंगले के अन्दर से फायरिंग करनी शुरू कर दी. हजारों की भीड़ में यह कहते सुना गया कि जब जिले का समूचा पुलिस महकमा बंगले के बाहर मुस्तैद था तो फिर ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी. लोगों की मानें तो यह हरकत सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश करने के लिए की गई थी. पुलिस विभाग के आला अफसरों की मौजूदगी में भीड़ पर बंगले से फायरिंग होना, अपने आप में एक बड़ा सवाल है. कुछ ही अरसा पहले इसी व्यक्ति ने जिलाधिकारी आवास के ठीक सामने एक भूमि पर मालिकाना हक जताते हुए प्रशासन की मदद से घंटों उत्पात मचाया था. उस मामले में भी एक अल्पसंख्यक ही शिकार हुआ था. बताते हैं कि अनीस राईन नामक इस व्यक्ति को भी इसकी ताकत के सामने मजबूरन नतमस्तक होना पड़ा था.

जिला प्रशासन ने चाटुकारिता की हद कर दी

सत्ता के सखा गौतम शर्मा के इशारे पर नाच रहे जिला प्रशासन ने चाटुकारिता की हद कर रखी है. घटना के समय बंगले के अंदर से गौतम शर्मा के गुर्गों द्वारा की गई फायरिंग मामले में कार्रवाई करने के बजाय जिला प्रशाशन उसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बता रहा है. पुश्तों की आजीविका नष्ट किए जाने का विरोध करने वाले सिख समुदाय के लोगों पर पुलिस ने उल्टा तमाम मुकदमे ठोक दिए हैं. कोतवाली इंस्पेक्टर मुक्ता प्रसाद वर्मा ने खुद तहरीर लिखवाई है और उसमें बबली सरदार, मनमोहन सरदार, राजू उर्फ जयपाल, गुरमीत सिंह, दलीप सिंह, हरजीत पत्नी गुरमीत, राम किशुन गुप्ता व उसके दो बेटों प्रशांत व सुमंत, गिरीश और प्रदीप के साथ ही दिलीप के नाती पोतों व लगभग 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा करने, जान से मारने का प्रयास करने, मारपीट करने, सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, सड़क जाम करने के साथ-साथ उन पर 7- क्रिमिनल एक्ट के साथ ही एससी-एसटी एक्ट भी लगा दिया गया है.

महोबा का पंगु प्रशासन

महोबा में हुए इस बवाल ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और उसकी ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भले इसे नियमत: की गई कार्रवाई बताएं, लेकिन असल में इस घटना क्रम से प्रशासन की छवि को खासा बट्टा लगा है. लोगों के जहन में जो सवाल निरंतर कौंध रहा था वह ये था कि आखिर इस रसूखदार व्यक्ति के मामले में ही प्रशासन इतना कर्तव्य निष्ठ क्यों हो जाता है. शहर में दर्जनों इमारतें ऐसी हैं जो वास्तव में जर्जर भी हैं और उन इमारतों का मालिकाना हक रखने वाले लोग वर्षों से उन्हें खाली कराए जाने के लिए इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों की परिक्रमा लगा रहे हैं. उन लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करना और इस रसूखदार की बेजा मदद करना प्रशासन के पंगु होने की सनद देता है.

महोबा के चौपट नेता

सिखों के साथ हुई इस बर्बतापूर्ण कार्रवाई का आम जनमानस में जमकर विरोध हो रहा है, लेकिन इस मामले में विरोधी दलों की भूमिका बेहद संदिग्ध है. अपने हक को लेकर सड़क पर बैठे सिखों के साथ अल्प समय के लिए पहुंचकर भाजपा सांसद पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल ने जहां जलती आग में राजनीति की रोटियां सेंकने का काम किया, वहीं पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता अरिमर्दन सिंह भी इस मामले में औपचारिकता ही निभाते नजर आए. सूबे की प्रमुख विपक्षी दल कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस मामले में पूरी तरह नदारद रही. राजनीतिक दलों के अलावा यदि बात सामाजिक संगठनों की करें तो व्यापार मंडल नामक संगठन से जुड़े लोग कुछ देर के हो-हल्ले के उपरांत प्रशासनिक अमले के सामने घुटने टेकते देखे गए. हां, गुलाबी गैंग की जिला कमांडर जरूर सक्रिय नजर आईं, लेकिन वह भी केवल अकेली थीं और उनका लाव लश्कर मौके से नदारद था. आम जनता को पुलिस ने पहले ही खदेड़ दिया था और इसके बाद चारों ओर से की गई किलेबंदी ने सिख समुदाय के लोगों को बिल्कुल अकेला कर दिया था. बावजूद इसके वह न केवल अपने हक को लेकर जद्दोजहद करते रहे, बल्कि इस प्रयास में उनको प्रशासनिक बर्बता का शिकार भी होना पड़ा. इस पूरे मामले में सपा की किसी भी प्रकार से संलिप्तता को लेकर इनकार करने वाले सत्तापक्ष के स्थानीय नेता तमाशबीन की भूमिका में तो रहे पर किसी ने प्रशासन से इस मसले पर सवाल करना मुनासिब नहीं समझा. सपा नगर अध्यक्ष शाहिद राजू का कहना था कि उक्त व्यक्ति का हमारी पार्टी या मुख्यमंत्री से कोई वास्ता नहीं पर जब उनसे यह पूछा गया कि फिर सपा इस मामले में चुप क्यों है, तो वे जबाब देने से कन्नी काट गए.

महोबा का निरंकुश मीडिया

समूचे घटनाक्रम ने मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है. प्रदर्शन कर रहे सिखों ने यह मांग की थी कि घटना के कवरेज के लिए दूसरे जनपद के पत्रकारों को बुलाया जाए. यह मांग स्थानीय मीडिया के लिए तमाचे से कम नहीं थी. प्रदर्शनकारी सिखों का कहना है कि मीडिया से जुड़े कुछ लोग उक्त रसूखदार व्यक्ति के हाथों बिक गए. घटना की अखबारों में हुई कवरेज ने भी सिखों के आरोपों की पुष्टि कर दी. ■

feedback@chauthiduniya.com

कभी गरमाते हैं तो कभी भरमाते हैं नाईक

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक कभी विवादास्पद बयान देकर प्रदेश की राजनीति को गरमा देते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश के विकास की जरूरतों पर जोर देकर राजनीतिकों को भरमा देते हैं. हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी के विशेषांक उत्तर प्रदेश कल आज और कल का विमोचन करते हुए पिछले दिनों लखनऊ में नाईक ने मंच पर बैठे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रामगोविंद चौधरी के जरिए अखिलेश सरकार को सीख दी कि वे यूपी का विकास दलगत भावना से ऊपर उठकर करें और सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करें. नाईक ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की हिमायत की.

हिन्दुस्थान समाचार की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित विचार गोष्ठी में राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश को नौ प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन प्रदेश का वह विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था. अमेठी हो या रायबरेली या फिर इलाहाबाद, इन क्षेत्रों से बड़े-बड़े नताओं के होने के बावजूद उस तरह का विकास यहां नहीं हो पाया, जैसा विकास महाराष्ट्र, केरल या गुजरात का हुआ. उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ पार कर गई है, लेकिन लोगों को बेहतर सुविधाएं देने में प्रदेश पीछे ही है. नाईक ने राज्य की शिक्षा के स्तर पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ में उच्च स्तर के विश्वविद्यालय हैं लेकिन इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है. कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां 3-4 वर्षों के बाद भी छात्रों को अभी तक डिग्री नहीं मिली है. राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के चारित्रिक स्तर पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के यहां से मंत्रियों से जुड़े मामलों की जांच रिपोर्टें आती रहती हैं. उन रिपोर्टों से काफी अचरज होता है कि अच्छे-अच्छे पदों पर बैठे लोग भी इस तरह का काम करते हैं. उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राज्यपाल की वकालत पर प्रतितर्क देते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश है ही अब इसे सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की जरूरत है. हालांकि मंत्री ने यह स्वीकार किया कि प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की जरूरत है. लखनऊ के

उत्तर-प्रदेश का पिछड़ना सपा और पूर्ववर्ती बसपा सरकार की गलत, दिशाहीन और मनमर्जी से नीतियां बनाने का परिणाम है. राज्य में निवेश का वातावरण नहीं बनाया गया. बिजली संकट और कानून व्यवस्था की लगातार बिगड़ती स्थिति के कारण निवेशक प्रदेश में नहीं आए. जबकि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा गंभीरता से काम किया जा रहा है.

महापौर और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. दिनेश शर्मा ने विकास के रास्ते में राजनीतिक हस्तक्षेप कम करने की बात कही, साथ ही राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बेहतर समन्वय पर उन्होंने जोर दिया. उन्होंने माना कि प्रदेश की संस्थाओं के बीच आपसी तालमेल का आभाव है, जिस वजह से विकास के कई काम रुक जाते हैं. न्यूज एजेंसी की प्रवर समिति के संरक्षक व वरिष्ठ पत्रकार राजनाथ सिंह सूर्य और अध्यक्ष बीएस शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए. कार्यक्रम का संचालन एजेंसी के समाचार समन्वयक पीएन द्विवेदी ने किया. एजेंसी के प्रदेश प्रभारी राजेश तिवारी, विश्वनाथ खेमका, राजेश राय, नानक चंद समेत कई गणयमान्य बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम में मौजूद थे.

समाचार एजेंसी के इस कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के विकास का मसला फिर से विचारों में सुगबुगाया और एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट (एसोचैम) की वह रिपोर्ट फिर से ताजा हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में बिहार से भी पीछे बताया गया था. उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मामले में साला-ाना विकास दर (सीएजीआर) के लिहाज से प्रमुख चार पिछड़े राज्यों में सबसे नीचे है. एसोचैम ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर अध्ययन किया था. वर्ष 2004-05 से लेकर 2012-13 के बीच उत्तर प्रदेश जीएसडीपी में मात्र 6.9 फीसदी की सीएजीआर हासिल कर सका, जो चार पिछड़े राज्यों में सबसे कम है. इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी उत्तर प्रदेश 4.8 प्रतिशत सीएजीआर के साथ सबसे पीछे रहा. इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि विकास दर के मामले में

उत्तर-प्रदेश का पिछड़ना सपा और पूर्ववर्ती बसपा सरकार की गलत, दिशाहीन और मनमर्जी से नीतियां बनाने का परिणाम है. राज्य में निवेश का वातावरण नहीं बनाया गया. बिजली संकट और कानून व्यवस्था की लगातार बिगड़ती स्थिति के कारण निवेशक प्रदेश में नहीं आए. जबकि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा गंभीरता से काम किया जा रहा है.

अभी हाल ही में अखिलेश सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट में लोहिया आवास और ग्रामीण जीवन के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली और सिंचाई पर खासा ध्यान देने का प्रस्ताव दिया. राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट के जरिए 2017 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के साफ संकेत दिए. लेकिन जमीनी स्थिति इन तैयारियों के ठीक विपरीत हैं. ग्रामीणों के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं का हाल यह है कि बिजली आती ही नहीं और बिजली नहीं तो सिंचाई नहीं. किसानों को बिजली और पानी नहीं, ऊपर से खाद की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है. किसानों की फसलें उचित दाम नहीं दे पातीं. गन्ना किसान सरकार और चीनी मिल मालिकों की साठगांठ में पिस रहा है और उत्तर प्रदेश में गन्ना की पैदावार तेजी से कम हो रही है. खाद्यान्न और सब्जियों के उत्पादन में भी किसानों को लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और सरकारी अफसर, व्यापारी और दलाल मालामाल हो रहे हैं. अखिलेश सरकार ने प्रदेश भर में सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के लिए 962 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. यह धन सिंचाई विभाग को मिलेगा और ग्रामीण कहते हैं कि इस धन का इस्तेमाल कभी भी नहरों में पानी आने के लिए नहीं होता, यह नेताओं-नौकरशाहों-दलालों के जेब भरने के लिए होता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

केदारनाथ के साथ ही चारधाम यात्रा को सरकार सुगम बनाएगी

राजकुमार शर्मा

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएंगी. यात्रियों का बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. जगह-जगह पर टॉवर स्थापित किये गये हैं. केदारनाथ की यात्रा के लिए सरकार विशेष प्रबंध कर रही है और यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा. सरकार का प्रयास है कि केदारानाथ में इस बार पहले से बेहतर सुविधाएं हों. केदारनाथ में लगभग चार हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. केदारनाथ धाम में रोपवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा. इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है. लिनचोली से केदारनाथ धाम तक के साढ़े तीन किलोमीटर के दायरे में बनने वाले रोपवे से श्रद्धालुओं को धाम तक पहुंचने में काफी आसानी होगी. यहां इस बार हेलीकॉप्टर सेवा की भी व्यवस्था की जा रही है. कई स्थानों पर पीसीओ और बेहतर संचार के लिए टावर भी स्थापित किए गए हैं. चार धाम यात्रा के प्रचार-प्रसार के लिए खुद सीएम ने विभिन्न राज्यों का दौरा करने का मन बनाया है.

बीजापुर गेस्ट हाइस में चारधाम होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की और मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस साल होनी वाली चारधाम यात्रा पहले के मुकाबले बेहतर होगी. हरीश ने कहा, केदारनाथ के लिए बेहतर ट्रैकिंग रूट बनाया जा रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए हेली सर्विस की व्यवस्था भी की जाएगी. गुप्तकाशी से केदारनाथ के बीच विभिन्न स्थानों पर हेलीपैड बनाये जा रहे हैं, हवाई सेवा उपलब्ध कराये रहे. सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसडीआरएफ के जवान यात्रा मार्ग पर यात्रियों के साथ रहेंगे. संपूर्ण यात्रा मार्ग पर मेडिकल टीम साथ रहेगी. जगह-जगह पर टॉवर स्थापित किये गये हैं, जिससे कनेक्टीविटी में किसी तरह की समस्या न हो. यात्री आसानी से अपने परिजनों से बात कर सकेंगे. इसके लिए पीसीओ भी स्थापित किये जा रहे हैं. केदारनाथ में पानी व बिजली सहित अन्य सभी सुविधाएं पहले से बेहतर स्थिति में यात्रियों को मिलेंगी. चारधाम यात्रा को प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री स्वयं देश के विभिन्न प्रांतों में जाएंगे. इससे लोगों में सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश जाएगा. मुख्यमंत्री ने सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अपील की कि वे भी अपना पूरा सहयोग सरकार को देंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी चारधाम यात्रा मार्ग की सड़कें दुरुस्त कर दी जाएंगी. बीआरओ को भी इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं. तीर्थयात्रियों के लिए उत्तराखंड के चारों धाम अब और नजदीक आने वाले हैं. राज्य सरकार ने सुगम, सुरक्षित और वैकल्पिक सड़क मार्ग का खाका तैयार किया है जिससे इनकी आधी से ज्यादा दूरी घट जाएगी. इसकी परियोजना रपट भी तैयार कर ली गई है. वर्तमान मार्गों से चार धाम की कुल यात्रा 813 किलोमीटर की है. प्रस्तावित मार्ग से यह दूरी सिमट कर 389.6 किलोमीटर रह जाएगी. नए मार्ग में लंबी सुरंगें व पुल बनेंगे, जिससे खराब मौसम में भी यात्रा प्रभावित नहीं होगी. सभी धाम एक मार्ग से जुड़ जाएंगे. नया मार्ग सीमावर्ती इलाकों को भी जोड़ेगा. प्रदेश सरकार की पहल पर राज्य योजना आयोग से जुड़े अधिकारियों ने इस परियोजना की रपट भी तैयार करा ली है. आयोग से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार इस पर करीब आठ हजार करोड़ की लागत आएगी. इसके लिए देश और विदेश के कुछ विशेष सुरंग मार्गों का भी अध्ययन किया गया है. चार धाम की यात्रा मार्ग के कम होने के साथ जोशीमठ, गोपेश्वर, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बड़कोट की दूरी भी कम हो जाएगी. यात्रियों को करीब 423.4 किलोमीटर की अनावश्यक यात्रा से राहत मिलेगी. वर्तमान चार धाम मागसे होकर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. कुछ इलाकों में हर साल बाढ़ और भूस्खलन से मार्ग प्रभावित रहता है. नए मार्ग के लिए तैयार रपट में इसका भी हवाला दिया गया है कि हर साल इनकी मरम्मत पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. धन के साथ जन हानि भी होती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कैडेट आपदा प्रभावितों की मदद करेंगे

चौथी दुनिया ब्यूरो

नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेट आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे. इसके लिए राज्य में एनसीसी कैडेटों को खासतौर से प्रशिक्षित किया जाएगा. आगामी अर्ध कुम्भ-2016 में व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस के साथ एनसीसी कैडेटों को भी तैयार किया जाएगा. प्रदेश में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी बनने तक रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसके लिए खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है. मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर होने वाली आरडी परेड में शिरकत करने वाले सूबे के एनसीसी कैडेटों को विवेकाधीन कोष से दो लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की. उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय की ओर से सोमवार को अनारवाला स्थित एनसीसी प्रशिक्षण स्थल पर परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य अतिथि थे. इस अवसर पर उन्होंने कैडेटों का हौसला बढ़ाते हुए आरडी प्रशिक्षण शिविर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया. एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी के माध्यम से अनुशासन का संदेश युवा पीढ़ी में जाना चाहिए. दैवी आपदा से निपटने व अर्ध कुम्भ में व्यवस्था बनाने के लिए एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षित करने की बात भी उन्होंने कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी. अकादमी स्थापित होने तक स्पोर्ट्स कॉलेज को प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने का भरोसा भी उन्होंने एनसीसी के अधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि एनसीसी अनुशासित संस्था के साथ ही युवाओं को सैन्य सेवा में रोजगार उपलब्ध कराने का बेहतर माध्यम है. राज्य में एनसीसी को अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए. पांच सीमांत जनपदों के युवाओं को एनसीसी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का सुझाव उन्होंने एनसीसी अधिकारियों को दिया. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि एनसीसी निदेशालय की मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाया जाएगा. कैडेटों के रिफ्रेशमेंट फंड में पहले ही वृद्धि की जा चुकी है. शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी स्थापित होने से कैडेटों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण व सुविधाएं मिलेंगी. अधिक स्कूलों में एनसीसी का विस्तार करने की बात भी उन्होंने कही. ■

प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट का अस्तित्व खतरें में

हरीश सरकार में कैबिनेट मंत्री हरीशचन्द्र दुर्गापाल की राजनीतिक चाल के चलते उत्पन्न नए सियासी हालात में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) की प्रदेश सरकार में अब वह हैसियत नहीं लौट पाएगी, जो कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव से पहले थी. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदस्य रहे निर्दलीय विधायक व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के कांग्रेस में विधिवत शामिल न होने के कारण पीडीएफ सदस्यों की संख्या फिर जस की तस हो गई है. लेकिन विधानसभा में कांग्रेस के बढ़े संख्याबल के कारण प्रदेश सरकार के साथ पीडीएफ की सौदेबाजी की ताकत लगभग खत्म हो गई है. प्रदेश सरकार में पीडीएफ के मंत्री व विधायक सरकार के मुखिया के रहमोकरम पर ही हैं. वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के विधायकों की संख्या में महज एक का ही अंतर था. कांग्रेस के 32 तो भाजपा के 31 विधायक जीत कर आए थे. चुनाव में मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की अप्रत्याशित हार के कारण भाजपा दोबारा सरकार बनाने का नैतिक बल नहीं जुटा पाई और उसके रुख ने कांग्रेस को तीन निर्दलीय विधायकों मंत्री प्रसाद नैथानी, दिनेश धनै, हरीश चंद्र दुर्गापाल, उक्रांद विधायक प्रीतम सिंह पंवार व बसपा के तीन विधायकों सुरेंद्र राकेश, हरिदास व सरवत करीम अंसारी की मदद से सत्ता हासिल करने का मौका दे दिया. यह बात और है कि कहा यह भी जाता है कि उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने भी निर्दलीयों व बसपा विधायकों का समर्थन जुटा लिया था, भाजपा आलाकमान व पूर्व सीएम खंडूड़ी व भगत सिंह कोश्यारी ने उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए. बहरहाल सात विधायकों की मदद से कांग्रेस ने अपने पक्ष में 39 विधायक कर सत्ता हासिल कर ली. इसी वक्त एंग्लो इंडियन आरवी गार्डनर को विधायक मनोनीत कर कांग्रेस ने अपने पक्ष के विधायकों की संख्या 40 कर ली. इसी बीच मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भाजपा के सितारगंज विधायक किरण मंडल को तोड़ लिया और इनसे सीट खाली कराकर खुद विधायक बन गए. इस तरह कांग्रेस की खुद की संख्या 33 पहुंच गई. कांग्रेस विधायकों की बढ़ती संख्या से बेचैन निर्दलीयों, उक्रांद व बसपा विधायकों ने उनकी बैसाखी पर खड़ी प्रदेश सरकार पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए एक लुंज-पुंज मोर्चा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ)बना लिया. लोकसभा चुनाव तक इस मोर्चे को प्रदेश कांग्रेस के गुट भी कांग्रेस में अपनी ताकत बनाए रखने या दूसरे गुट की ताकत कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि पीडीएफ जिसके साथ हो जाता उसकी ताकत बढ़ जाती.

इसी बीच बसपा ने अपने दो विधायकों को पार्टी से निलंबित कर कांग्रेस को और मजबूत होने का मौका दे दिया. हरीश रावत की ताजपोशी के वक्त भी मोर्चे के रूख से यही साफ हुआ. लोकसभा चुनाव से पहले सतपाल महाराज भी अपने समर्थकों के साथ ही पीडीएफ को अपने लिए इस्तेमाल करते थे, लोकसभा चुनाव के एन मौके पर वह खुद ही कांग्रेस छोड़कर और पीडीएफ की ताकत को कम कर बैठे. लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के तीन विधायकों रमेश पोखरियाल निशंक, अजय टम्टा के जीत जाने से दो विधानसभा सीटें डोईवाला व सोमेश्वर खाली हो गई तो वहीं कांग्रेस के धारचूला सीट से कांग्रेस विधायक हरीश धानी ने सीएम हरीश रावत के लिए सीट छोड़ दी. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तीनों सीटें जीत लीं और इसकी संख्या 35 पहुंच गई. जो कि बहुमत के करीब है. ऐसे में बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस को महज एक यो दो विधायकों की जरूरत है. कांग्रेस तो पहले ही पीडीएफ से छुटकारा चाहती थी इसलिए उसने निर्दलियों पर डोरे डालने शुरू किए और हरीश चंद्र दुर्गापाल को कांग्रेस में शामिल होने को मना लिया. वह तो ऐन वक्त पर भाजपा ने सदस्यता लेने को दल-बदल कानून का उल्लंघन बता कर मसला उलझा दिया और कांग्रेस को सदस्यता पर पलटना पड़ा. कांग्रेस विधानसभा में अब जिस स्थिति में है. उसके चलते अब पीडीएफ सरकार पर दबाव नहीं बना पाएगा. अगर पीडीएफ सत्ता का सुख भोगना चाहता है, तो कांग्रेस के रहमों करम पर सरकार में बना रह सकता है. ■

-राजकुमार शर्मा

आपदा के कारण हजारों परिवार पर अजीविका का संकट

रेनू शर्मा

प्रदेश की हरीश सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद भीषण दैवीय आपदा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई चारधाम यात्रा 2014 में भी पटरी पर नहीं लौट पाई. इस यात्रा के चौपट होने के कारण हजारों लोगों की आजीविका भी प्रभावित हुई है जिससे तमाम परिवार भूखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं. 16 जून वर्ष 2013 की दैवीय आपदा के कारण चारधाम यात्रा चौपट हो गई थी, तब केदारनाथ की तबाही के साथ ही बद्रीनाथ मार्ग के भी आपदा की भेंट चढ़ जाने के कारण यह यात्रा पूरी तरह ठप हो गई. वर्ष 2013 में इस भीषण आपदा के कारण यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी आपदा का प्रभाव पड़ा था, तब से अब तक चारधाम यात्रा पटरी पर लौटने का नाम नहीं ले पा रही है. राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी पुरी सरकार सुरक्षित चार धाम का संदेश देने के लिए हर स्तर पर प्रयत्नशील है. इसके बावजूद भी केदारनाथ के हालात अब तक नहीं सुधरे हैं. इसलिए माना जा रहा था कि बद्रीनाथ, हेमकुंड, यमुनोत्री, गंगोत्री आदि धामों की यात्रा धीरे-धीरे पटरी पर लौट आएगी. इसके बावजूद अब तक के हालात निराशाजनक ही रहे हैं. इस वर्ष बद्रीनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर जिस तरह तीर्थयात्रियों की भारी आमद पहले ही दिन बदरीनाथ में देखने को मिली थी, उसके चलते इस तरह की संभावनाओं को बल मिलने लगा था कि कम से कम ग्रीष्मकाल में तो बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों की आवाजाही ठीक-ठाक रहेगी. पहले ही दिन जिस तरह लामबगड़ स्लाइड जोन पर हाईवे के दगा देने से लोग रात भर बीच रास्ते में ही फंसे रहे और उसका गलत संदेश पूरे देश में गया और इससे तीर्थयात्री इस धाम की ओर रुख करने से कतरा गए. उसके बाद भी हालातों में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए. लामबगड़ से लेकर बद्रीनाथ तक का मार्ग विकट हिमालयी परिस्थितियों के कारण राम भरोसे छोड़ दिया गया. इसी तरह के हालात गंगोत्री व यमुनोत्री में भी बने. हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी वर्ष 2013 की आपदा की दहशत की मार पड़ी और जैसी उम्मीद की जा रही थी उतनी संख्या में सिख श्रद्धालु भी हेमकुंड नहीं पहुंच पाए. बरसात में भी चारधाम यात्रा मार्ग के जगह-जगह अव्यवस्थित रहने से पूरी यात्रा लडखड़ा कर रह गई थी. बद्रीनाथ में तो लामबगड़ स्लाइड़ जोन को व्यवस्थित करने को लेकर लोग आंदोलन में भी कूदे रहे, परिस्थितियों के प्रतिकुलता के कारण सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, अब जबकि सरकार ने शीतकालीन यात्रा की शुरूआत की है तो माना जा रहा था कि इस यात्रा में लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा. बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के एक माह पूरे होने पर भी शीतकालीन यात्रा पड़ावों पर अभी तक भी यात्रियों का रुख नहीं हो पाया है. वैसे वर्ष 2012 में बद्रीनाथ में 9 लाख 85 हजार 631 तीर्थयात्री पहुंचे थे. इनसे मंदिर समिति को ही अकेले चढ़ावे के रूप में 12 करोड़ 70 लाख 80 हजार 815 रुपये की आय प्राप्त हुई थी. वर्ष 2013 के आपदा के वर्ष में 14 जून तक बदरीनाथ में 4 लाख 97 हजार 744 तीर्थयात्री रिकार्ड रूप में यहां पहुंचे थे. इनसे मंदिर समिति को 7 करोड़ 58 लाख 43 हजार की आय प्राप्त हुई थी. इसके बाद तो यात्रा पटरी से ही उतर गई. इस वर्ष एक लाख 76 हजार 421 यात्री ही पहुंच पाए. इनसे मंदिर समिति को 4 करोड 31 लाख 28हजार 976 रुपये की आय प्राप्त हुई. कहा जा सकता है कि बद्रीनाथ यात्रा आय का बड़ा स्रोत यहां के लोगों के लिए रहा है. यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चारधाम यात्रा पर भी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था निर्भर रही है. बीते दो वर्षों से यात्रा के पटरी से उतर जाने के कारण हजारों लोगों की आजीविका संकट में घिरी हुई है. तीर्थाटन व पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर बैंकों का कर्जा इस कदर चढ़ गया है कि लोगों की चैन की नींद भी उड़ कर रह गई है, अब लोग अपने भविष्य को लेकर हैरान परेशान होकर रह गए हैं. उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के भी पूरी तरह चरमरा जाने से अगले वर्षों में इसका असर सीधे-सीधे लोगों पर दिखने लगेगा, यह स्थिति भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक रूप में सामने आ सकती है. इसी वर्ष कश्मीर में जिस तरह प्राकृतिक विनाशलीला का रूप देखने को मिला. इसके चलते माना जा रहा था कि हिमालय के इन धामों की ओर प्रकृति प्रेमियों और धर्मावलंबियों का आवागमन बढ़ेगा. इसके बावजूद अभी तक सरकार सुरक्षित, सुव्यवस्थित यात्रा के कदम नहीं उठा पाई है. कहा जा सकता है कि वर्ष 2014 भी उत्तराखंड के तीर्थाटन और पर्यटन के लिए अच्छे दिनों के रूप में साबित नहीं हुआ है, अब वर्ष 2015 तीर्थाटन व पर्यटन के लिए किस रूप में सामने आता है. इस पर ही उत्तराखंड के लोगों का भविष्य निर्भर करेगा. राज्य की हरीश सरकार ने चारधाम के लिए केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार से अपेक्षाएं हैं और नरेंद्र मोदी को पांच सांसद जीता कर देने वाले उत्तराखंड के लोगों को भी मोदी से आशा है. ■

feedback@chauthiduniya.com